सूर्योदय 5:37 सूर्यास्त 7:19

आज का तापमान

शिमला	17.5 न्यू	22.2 अधि
धर्मशाला	21.6 न्यू	27.0 अधि

बाजार

सेंसेक्स	76,765
निफ्टी	23,985

सोना 1,43,000 चांदी 2,18,000

भारतेन्दु शिखर

हिमाचल, चंडीगढ़, पंजाब, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, दिल्ली, जम्मू व उत्तराखंड में प्रसारित

आरएनआई नं. HPHIN/2000/02437 | शिमला | बुधवार, 29 जुलाई 2026 | 14 श्रावण, विक्रमी संवत 2083 | वर्ष 28, अंक 95, कुल पृष्ठ 12 | मूल्य : 5 रुपए | info@bhartendushikhar.com | 8894677702

न्यूज शॉर्ट्स

मेटा ने पहले मोदी का वीडियो हटाया, अब रीस्टोर किया

एजेंसी, नई दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का फेसबुक से हटाया गया वीडियो मेटा ने दोबारा रीस्टोर कर दिया है। कंपनी ने मंगलवार को कहा कि तकनीकी गड़बड़ी की वजह से वीडियो गलती से हट गया था। इससे पहले कुछ समय के लिए फेसबुक पर यह वीडियो दिखाई नहीं दे रहा था, जिसके बाद इस पर सवाल उठे। प्रधानमंत्री मोदी ने यह वीडियो 23 जुलाई को जारी किया था। इसमें उन्होंने जेन-जी व छात्रों को संबोधित करते हुए परीक्षा पेपर लीक के खिलाफ सख्त कार्रवाई का भरोसा दिया था। न्यूज एजेंसी आईएएनएस ने सूत्रों के हवाले से दावा किया है कि इलेक्ट्रॉनिक्स एवं आईटी मंत्रालय ने मेटा (फेसबुक और इंस्टाग्राम) के ग्लोबल हेड और कंपनी के पब्लिक पॉलिसी के ग्लोबल हेड को भी तलब किया है।

ट्विशा मौत मामला

सास-पति की हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ी

एजेंसी, भोपाल। मध्य प्रदेश के चर्चित ट्विशा शर्मा मौत मामले में सीबीआई की विशेष अदालत ने मंगलवार को मुख्य आरोपित सास गिरिबाला सिंह और पति समर्थ सिंह की न्यायिक हिरासत 11 अगस्त तक बढ़ा दी। दोनों आरोपितों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से पेशी हुई। सुनवाई के दौरान बचाव पक्ष ने वॉइस सैंपल प्रक्रिया और रिमांड बढ़ाने पर आपत्ति जताई, जिसे अदालत ने खारिज कर दिया। सीबीआई ने जांच की संवेदनशीलता का हवाला देते हुए हिरासत बढ़ाने की मांग की थी। बचाव पक्ष ने जांच में सहयोग नहीं करने के आरोपों को गलत बताया और गवाहों की जानकारी मांगी। सीबीआई ने कहा कि इससे जांच प्रभावित हो सकती है।

देश का औद्योगिक उत्पादन 7.3% बढ़ा

एजेंसी, नई दिल्ली। अर्थव्यवस्था के मोर्चे पर अच्छी खबर है। विनिर्माण क्षेत्र के बेहतर प्रदर्शन और बिजली तथा गैस आपूर्ति क्षेत्र की मजबूत वृद्धि के कारण जून में देश का औद्योगिक उत्पादन 7.3 फीसदी बढ़ा है। इससे पिछले महीने मई के 5.1 फीसदी के मुकाबले यह काफी बेहतर रहा। सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय ने मंगलवार को जारी आंकड़ों में बताया कि जून माह में औद्योगिक उत्पादन सूचकांक (आईआईपी) पर आधारित औद्योगिक उत्पादन सालाना आधार पर 7.3 फीसदी बढ़ा है। आंकड़ों के मुताबिक इस बढ़ोतरी में विनिर्माण (मैन्युफैक्चरिंग) क्षेत्र में 7.8 फीसदी और बिजली क्षेत्र में 10.6 फीसदी की तेजी का मुख्य योगदान रहा है।

केंद्र सरकार ने चीनी की स्टॉक लिमिट तय की

एजेंसी, नई दिल्ली। केंद्र सरकार ने चीनी की जमाखोरी रोकने के लिए बड़ा सख्त कदम उठाया है। सरकार ने बाजार में चीनी की पर्याप्त उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए चीनी कारोबारियों के लिए नई स्टॉक रखने की सीमा लागू किया है। सरकार के नए आदेश के तहत अब कोई भी चीनी डीलर 4,000 क्विंटल से अधिक चीनी का स्टॉक नहीं रख सकेगा। ये नियम 1 अगस्त से 30 नवंबर तक लागू रहेगा। उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय ने मंगलवार को कहा कि सार्वजनिक वितरण प्रणाली (पीडीएस) और सरकारी चीनी भंडार को इस नई स्टॉक सीमा से छूट दी गई है।

पेपर लीक रोकथाम विधेयक पर लोकसभा में हंगामा, प्रियंका का प्रह्लाद जोशी पर कमेंट

रिजिजू बोले- शिक्षामंत्री का चरित्र हनन करने की कोशिश, प्रियंका का जवाब- सबूत दूंगी

◆ प्रयंका ने कहा- छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का अधिकार किसने दिया

एजेंसी, नई दिल्ली। लोकसभा में दोपहर 2 बजे से पेपर लीक से जुड़े 'पब्लिक एग्जामिनेशन (अनुचित साधनों की रोकथाम) संशोधन विधेयक, 2026' पर चर्चा शुरू हुई। विधेयक में 2024 में बने कानून में बदलाव का प्रस्ताव है। केंद्रीय राज्य मंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा इससे पेपर लीक रोकने में मदद मिलेगी।

प्रियंका गांधी ने सरकार से सवाल किया कि छात्रों पर लाठीचार्ज और पैलेट गन चलाने का अधिकार किसने दिया। प्रियंका ने कहा- एक ऐसे व्यक्ति को शिक्षामंत्री बनाया, जिसने गर्भवती महिला के बलात्कारियों की रिहाई पर सहमति व्यक्त की। इसके बाद सत्ता पक्ष ने हंगामा किया। रिजिजू निशिकांत दुबे और जोशी ने विरोध किया और कहा कि पहले प्रियंका इस बात का सबूत दें और माफी मांगे। स्पीकर बोले- मैं प्रियंका से कहूंगा कि बिना तथ्यों से इस तरह की बातें सदन में करें। प्रियंका का जवाब- जोशी ने बिल्किस बानो के बलात्कारियों पर बयान दिया उसका प्रमाण मैं भेज दूंगी। केसी वेणुगोपाल ने कहा- इन्होंने इंदिरा गांधी का नाम लिया है। आप हटा नहीं सकते हैं। निशिकांत बोले- मैंने नेहरू का नाम लिया था और आज भी अपने बयान पर कायम हूं। प्रह्लाद जोशी ने कहा- मेरे बारे में जो बोला गया उस पर मुझे पहले से नहीं बताया गया।

स्पीकर ने टोका- सदन में इस बिल पर ही चर्चा होगी। आप सिर्फ विधेयक पर ही बोलें। इससे पहले सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने कहा कि सरकार वचन नहीं, जुमले देती है। दोपहर का सत्र शुरू होने पर स्पीकर ओम बिड़ला ने कहा कि मैंने चर्चा के लिए 6 घंटे का समय तय किया है। सत्ता पक्ष और विपक्ष चाहें तो समय बढ़ा सकते हैं। इस पर केंद्रीय मंत्री किरेन रिजिजू ने कहा कि सरकार ने सभी दलों से बात की है। अब 8 घंटे चर्चा होगी। जरूरत होगी तो हम 10 घंटे भी चर्चा को तैयार हैं।

रिजिजू ने उठाया आंदोलन और इमरजेंसी का मुद्दा अखिलेश बोले- इमरजेंसी के बाद हुआ था परिवर्तन

अखिलेश की स्पीच पर किरण रिजिजू ने कहा, अखिलेशजी तो समाजवादी हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि छात्रों के आंदोलन के बाद सरकार बिल लेकर आती है, ये अच्छा है या आंदोलन के बाद सरकार उसे कुचलने के लिए इमरजेंसी लगा देती है, वो अच्छा है? अखिलेश यादव का जवाब- इमरजेंसी तो नहीं देखी,लेकिन इमरजेंसी में क्या-क्या हुआ वो दिल्ली में भी देखने को मिल गया। याद दिला दूं इमरजेंसी के बाद परिवर्तन हुआ था इस बार भी परिवर्तन होगा।

नाबालिग प्रदर्शनकारियों को तुरंत रिहा करें : सुप्रीम कोर्ट

◆ दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार केरल और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस

एजेंसी, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय ने सभी राज्यों में प्रदर्शनकारियों के खिलाफ कार्रवाई पर रोक लगा दी है।

मुख्य न्यायाधीश सूर्यकांत की अध्यक्षता वाली बेंच ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि कि वे नाबालिगों को तुरंत रिहा करें। हालांकि, कोर्ट ने कहा कि उन्हें सुरक्षा नहीं मिलेगी, जिनका आपराधिक रिकॉर्ड रहा है। कोर्ट ने दिल्ली, महाराष्ट्र, बिहार, केरल, मध्यप्रदेश और उत्तर प्रदेश के मुख्य सचिवों को नोटिस जारी किया है। कोर्ट ने सभी राज्यों को निर्देश दिया कि प्रदर्शन से जुड़े सभी सीसीटीवी फुटेज, ड्रोन, बॉडी कैमरे, वायरलेस कम्युनिकेशन रिकॉर्ड और पीसीआर कॉल को संरक्षित रखे जाएं। कोर्ट ने सभी राज्यों की पुलिस को निर्देश दिया कि वो प्रदर्शन के दौरान प्रदर्शनकारियों के डिजिटल डाटा को संरक्षित करें और उसे सार्वजनिक नहीं करें। कोर्ट ने ये भी आदेश दिया कि प्रदर्शनकारियों के किसी भी निजी जानकारी और सूचना को प्रकाशित नहीं किया जाएगा। इसके साथ ही प्रदर्शनकारी छात्रों के खिलाफ कोई निरोधात्मक कार्रवाई नहीं की जाएगी। कोर्ट ने कहा कि प्रदर्शन के दौरान गिरफ्तार 18 साल से कम के नाबालिगों को तुरंत रिहा किया जाए। सुनवाई के दौरान कोर्ट ने इस बात पर चिंता जताई कि नीट पेपर लीक के खिलाफ प्रदर्शनाकारियों से निपटने के लिए लाठीचार्ज, पेलेट गन और आंसू गैस छोड़े गए। कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता इस मामले में स्वतंत्र जांच का विरोध नहीं कर रहे हैं।

भारत को कॉमनवेल्थ गेम्स में दूसरा गोल्ड

◆ शर्मिला धनखड़ ने शॉट पुट में मेडल जीता

एजेंसी, ग्लास्गो। राष्ट्रमंडल खेल-2026 में भारत की पैरा एथलेटिक्स टीम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने महिलाओं की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गईं। शर्मिला ने फाइनल में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर शीर्ष स्थान हासिल किया और इतिहास रच दिया। एफ57 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए होता है, जिनके निचले अंगों में दिव्यांगता, अंगों की कमी या मांसपेशियों की शक्ति कम होती है। इसी स्पर्धा में भारत की शिल्पा के शायला ने भी शानदार प्रदर्शन करते हुए कांस्य पदक अपने नाम किया।

जापान में 7.1 तीव्रता के भूकंप के झटकों से गिरी इमारतें, कई घायल

एजेंसी, टोक्यो

मंगलवार को जापान के दक्षिणी हिस्से में एक बेहद शक्तिशाली भूकंप महसूस किया गया है। समाचार एजेंसी रॉयटर्स के अनुसार, इस झटके के बाद तटीय इलाकों के लिए सुनामी का अलर्ट जारी किया गया था, लेकिन फिर बाद में अलर्ट वापस ले लिया गया।

जापान मौसम विज्ञान एजेंसी के अनुसार, मंगलवार को जापान के क्यूशू क्षेत्र के कुमामोटो प्रांत में 7.1 की प्रारंभिक तीव्रता वाला भूकंप आया। यह एक बेहद शक्तिशाली झटका था, जिसने पूरे दक्षिणी जापान को हिलाकर रख दिया। भूकंप के एपीसेंटर के पास कई इमारतें गिरी हुई दिखाई दीं। उकी शहर के फायर डिपार्टमेंट ने ब्रॉडकास्टर को बताया कि शहर में कई जगहों पर आग लगने की वजह से उन्हें बहुत सारी इमरजेंसी कॉल मिलीं।

एनएचके के मुताबिक, यात्सुशिरो में क्यूशू एक्सप्रेसवे पर बने हाईवे ओवरपास को काफी नुकसान पहुंचा और उसी शहर में एक पुल का पैदल चलने वाला हिस्सा गिर गया। भूकंप के तुरंत बाद, जापान मौसम विज्ञान एजेंसी ने तटीय क्षेत्रों के लिए सुनामी की चेतावनी जारी कर दी है। जेएमए के मुताबिक, समुद्र में एक मीटर तक ऊंची लहरें उठने की आशंका है। तटीय इलाकों में रहने वाले लोगों को सतर्क रहने की सलाह दी गई है।

उर्वरक की कमी की अफवाहों पर ध्यान न दें किसान : योगी

सीएम ने कहा- किसानों को पर्याप्त उर्वरक उपलब्ध कराने को सरकार प्रतिबद्ध

◆ खरीफ सीजन में समय पर मिलेगा गुणवत्तापूर्ण उर्वरक

एजेंसी, लखनऊ। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने कहा कि सरकार वर्तमान खरीफ सीजन में मुख्य फसल धान की रोपाई और अन्य फसलों की बुवाई के उपरांत किसानों को फसल संस्तुति के अनुसार पर्याप्त मात्रा में उर्वरकों की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए पूर्ण रूप से प्रतिबद्ध है।

उन्होंने किसानों को भरोसा दिलाया कि परेशान न हों, प्रदेश में उर्वरक की पर्याप्त मात्रा उपलब्ध है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को निर्देश दिया कि किसानों को सुगमता से उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए कृषि व संबंधित विभाग के अधिकारी लगातार मॉनिटरिंग करें। मुख्यमंत्री ने कहा कि किसान भ्रामक सूचनाओं व अफवाहों पर ध्यान न दें और अनावश्यक रूप से उर्वरक भंडारण न करें। पिछले वर्ष की तुलना में इस वर्ष अधिक उर्वरक उपलब्ध कराए गए हैं। किसानों को समय पर गुणवत्तापूर्ण उर्वरक उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। कृषि मंत्री सूर्य प्रताप शाही ने बताया कि प्रदेश में किसानों के लिए उर्वरक का पर्याप्त स्टॉक उपलब्ध है। खरीफ सीजन- 2026 के तहत सोमवार (27 जुलाई) तक कुल 28.25 लाख मीट्रिक टन उर्वरक बिक्री की जा चुकी है, जबकि 29.05 लाख मीट्रिक टन उर्वरक अब भी उपलब्ध है। सरकार किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराने के लिए प्रतिबद्ध है। कृषि निदेशक डॉ. पंकज त्रिपाठी ने बताया कि सभी 18 मंडलों में पर्याप्त खाद उपलब्ध है। जनपदों में किसानों को किसी भी प्रकार की परेशानी होती है तो वे जनपद, मंडल के कृषि अधिकारी से संपर्क कर सकते हैं। सहारनपुर में 43,275 मी. टन, मेरठ में 67551 मी. टन, आगरा में 95852 मी. टन, अलीगढ़ में 86474 मी. टन, बरेली में 116987 मी. टन, मुरादाबाद में 83972 मी. टन, कानपुर में 143076 मी. टन, प्रयागराज में 111070 मी. टन, झांसी में 47722 मी. टन, चित्रकूट में 50189 मी. टन, वाराणसी में 109312 मी. टन, मीरजापुर में 36014 मी. टन, आजमगढ़ में 73086 मी. टन, गोरखपुर में 91659 मी. टन, बस्ती में 51638 मी. टन, गोंडा में 59199 मी. टन, लखनऊ में 138186 मी. टन, अयोध्यामें 71695 मी. टन यूरिया उपलब्ध है।

झारखंड पुलिस को बड़ी कामयाबी 16 माओवादियों ने किया आत्मसमर्पण

एजेंसी, रांची। झारखंड पुलिस को माओवादियों के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान में बड़ी सफलता मिली है। ऑपरेशन 'नवजीवन-2' के तहत प्रतिबंधित भाकपा (माओवादी) संगठन के 16 सक्रिय नक्सलियों ने मंगलवार को पुलिस के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया।

आत्मसमर्पण करने वालों में संगठन के विभिन्न स्तरों के कमांडर और दस्ता सदस्य शामिल हैं। उन्होंने पुलिस को 11 आधुनिक हथियार, 38 मैगजीन और 1,562 जिंदा कारतूस सौंपे। इनमें एक रीजनल कमेटी सदस्य, तीन जोनल कमेटी सदस्य, तीन सब-जोनल कमेटी सदस्य, छह एरिया कमेटी सदस्य और तीन दस्ता सदस्य शामिल हैं। पुलिस महानिदेशक तदाशा मिश्रा ने बताया कि झारखंड पुलिस, सीआरपीएफ, कोबरा बटालियन और झारखंड जगुआर के संयुक्त अभियानों से माओवादी संगठन पर लगातार दबाव बढ़ रहा है। साथ ही राज्य सरकार की आत्मसमर्पण एवं पुनर्वास नीति से प्रभावित होकर नक्सली हिंसा का रास्ता छोड़ रहे हैं। आत्मसमर्पण करने वालों में 15 लाख रुपए के इनामी रीजनल कमेटी सदस्य संतोष उर्फ बासुदेव दा समेत कई बड़े कैडर शामिल हैं।

पांच साल में सीबीएसई के सरकारी स्कूल बनेंगे संस्थान सर्वश्रेष्ठ शिक्षण : सीएम सुक्खू

अनिल कुमार शर्मा, भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू ने कहा है कि प्रदेश के सीबीएसई से संबद्ध सरकारी स्कूल अगले पांच वर्षों में हिमाचल के सर्वश्रेष्ठ शिक्षण संस्थानों में शामिल होंगे।

उन्होंने कहा कि राज्य सरकार का लक्ष्य हर बच्चे को समान और गुणवत्तापूर्ण शिक्षा उपलब्ध कराना है। इसी उद्देश्य से सरकारी स्कूलों में पहली कक्षा से अंग्रेजी माध्यम में पढ़ाई शुरू की गई है और 156 सरकारी स्कूलों को सीबीएसई से संबद्ध किया गया है। इसके सकारात्मक नतीजे सामने आए हैं और सरकारी स्कूलों में 24 हजार से अधिक विद्यार्थियों का नामांकन बढ़ा है। मुख्यमंत्री मंगलवार को शिमला के बिशप कॉटन स्कूल के स्थापना दिवस समारोह को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि हिमाचल प्रदेश शिक्षा के क्षेत्र में आदर्श राज्य के रूप में आगे बढ़ रहा है। यहां का शैक्षणिक माहौल विद्यार्थियों को आगे बढ़ने के बेहतर अवसर देता है।

उन्होंने कहा कि बिशप कॉटन स्कूल केवल एक शिक्षण संस्थान नहीं है, बल्कि उत्कृष्टता, नेतृत्व, अनुशासन और चरित्र निर्माण की समृद्ध परंपरा का प्रतीक है। इस संस्थान ने वर्षों से विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा दी है और इसके पूर्व छात्र देश-विदेश में विभिन्न क्षेत्रों में महत्वपूर्ण योगदान दे रहे हैं। मुख्यमंत्री ने विद्यालय से जुड़ी अपनी यादें भी साझा कीं। उन्होंने कहा कि कॉलेज के दिनों में वह कई बार यहां क्रिकेट प्रतियोगिताओं में हिस्सा लेने आए थे। इसी कारण इस संस्थान से उनका विशेष लगाव रहा है। उन्होंने विद्यालय परिवार को स्थापना दिवस की शुभकामनाएं देते हुए कहा कि यह अवसर केवल स्थापना का उत्सव ही नहीं, उन मूल्यों को याद करने का भी है जिन पर इस संस्थान की नींव रखी गई थी।

फर्जी कॉल सेंटर मामले में ईडी ने मास्टरमाइंड को किया गिरफ्तार

एजेंसी, हैदराबाद। प्रवर्तन निदेशालय (ईडी) ने फर्जी कॉल सेंटर के जरिए अमेरिकी नागरिकों से साइबर ठगी और धनशोधन मामले में मुख्य आरोपी विकास कुमार निमार उर्फ मिस्टी को गिरफ्तार किया है। अदालत ने उसे न्यायिक हिरासत में भेज दिया है। ईडी के अनुसार, विकास कुमार निमार देश के कई शहरों से संचालित साइबर ठगी नेटवर्क का मास्टरमाइंड था। आरोप है कि वह खुद को तकनीकी सहायता कर्मी बताकर अमेरिकी नागरिकों को ठगी का शिकार बनाता था। जांच एजेंसी ने बताया कि आरोपित ने हैदराबाद में फर्जी कॉल सेंटर स्थापित किए थे, जहां से कर्मचारियों के जरिए लोगों को फोन कर कंप्यूटर में वायरस, तकनीकी खराबी या सुरक्षा समस्या का डर दिखाया जाता था और उनसे रकम वसूली जाती थी। ईडी ने वर्ष 2023 में मधापुर थाने में दर्ज प्राथमिकी के आधार पर पीएमएलए के तहत जांच शुरू की थी।

डीटीसी बस में बैठकर मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मानसून व नागरिक सुविधाओं का लिया जायजा

◆ कूड़े के पहाड़ हटाने और सड़कों की मरम्मत पर मुख्यमंत्री ने दिया जोर

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली की मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को डीटीसी बस में यात्रा कर क्षेत्र का व्यापक स्थलीय निरीक्षण किया। इस दौरान उन्होंने संबंधित अधिकारियों के साथ विभिन्न मार्गों पर यात्रा कर मानसून के दौरान शहर की जमीनी स्थिति का आकलन किया और नागरिक सुविधाओं से जुड़े महत्वपूर्ण कार्यों की समीक्षा की।

मुख्यमंत्री ने जन सेवा सदन से बस द्वारा निरीक्षण यात्रा प्रारंभ की, जो आउटर रिंग रोड, मधुबन चौक होते हुए रोहिणी स्थित सेक्टर-33 के डीडीए स्पोर्ट्स कांप्लेक्स तक पहुंची। यात्रा के दौरान उन्होंने मार्ग में लैंडफिल साइटों पर चल रहे कचरा निष्पादन कार्यों की प्रगति का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों से यह सुनिश्चित करने को कहा कि राजधानी में कूड़े के पहाड़ों को समाप्त करने के लिए चल रहे अभियान में किसी प्रकार की ढिलाई न बरती जाए और कार्य निर्धारित समयसीमा में पूर्ण हो। इस अवसर पर दिल्ली के समाज कल्याण मंत्री रवींद्र इंद्राज सिंह समेत संबंधित विभागों के वरिष्ठ अधिकारी भी उपस्थित रहे। मुख्यमंत्री ने निरीक्षण के दौरान वर्षा के कारण संभावित जलभराव वाले क्षेत्रों, प्रमुख सड़कों की सफाई व्यवस्था और सड़क किनारे जमा मलबे एवं कचरे की स्थिति का भी जायजा लिया। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि बारिश के दौरान जल निकासी व्यवस्था को और अधिक प्रभावी बनाया जाए और किसी भी क्षेत्र में जलभराव की स्थिति उत्पन्न न होने दी जाए। उन्होंने सड़कों के चौड़ीकरण, क्षतिग्रस्त सड़कों की मरम्मत और गड्ढों को प्राथमिकता के आधार पर भरने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि राजधानी की सड़कें केवल यातायात का माध्यम नहीं बल्कि दिल्ली की पहचान हैं, इसलिए उनका सुव्यवस्थित और सुरक्षित होना बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने अधिकारियों को सड़क किनारे पर्याप्त संख्या में कूड़ेदान स्थापित करने, प्रमुख चौराहों व सड़क किनारे हरित क्षेत्र विकसित करने और खाली दीवारों को आकर्षक चित्रों व कलात्मक पेंटिंग्स के माध्यम से विकसित करने के निर्देश दिए। उन्होंने कहा कि स्वच्छता और सौंदर्यीकरण साथ-साथ चलें, तभी दिल्ली वास्तव में एक आधुनिक और विश्वस्तरीय राजधानी के रूप में विकसित होगी।

हरित व आधुनिक परिवहन व्यवस्था राज्य सरकार की प्राथमिकता : मुख्यमंत्री धामी

एजेंसी, देहरादून। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने कहा कि राज्य सरकार स्वच्छ, आधुनिक और पर्यावरण-अनुकूल परिवहन व्यवस्था विकसित करने के लिए प्रतिबद्ध है और इसी उद्देश्य से उत्तराखंड में स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 लागू की गई है।

मंगलवार को मुख्यमंत्री कैंप कार्यालय स्थित मुख्य सेवक सदन में आयोजित कार्यक्रम में मुख्यमंत्री धामी ने उत्तराखंड स्वच्छ गतिशीलता परिवर्तन नीति-2024 के तहत छह लाभार्थियों को सब्सिडी चेक वितरित किए और 11 स्वच्छ ईंधन आधारित वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। पांच अन्य लाभार्थियों की सब्सिडी एवं स्वीकृति प्रक्रिया भी परिवहन विभाग की ओर से पूर्ण की जा चुकी है। धामी ने कहा कि यह पहल केवल आर्थिक सहायता नहीं, बल्कि प्रदेश में स्वच्छ ईंधन आधारित सार्वजनिक परिवहन को बढ़ावा देने और डीजल चालित वाहनों से होने वाले प्रदूषण को कम करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम है।

उन्होंने कहा कि जलवायु परिवर्तन की चुनौती से निपटने के लिए विकास और पर्यावरण संरक्षण के बीच संतुलन आवश्यक है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश हरित ऊर्जा और सतत विकास की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है और राज्य सरकार भी इसी सोच के अनुरूप स्वच्छ परिवहन, इलेक्ट्रिक बसों के संचालन, ईवी चार्जिंग स्टेशन और आधुनिक शहरी परिवहन प्रणाली के विकास पर कार्य कर रही है। मुख्यमंत्री ने कहा कि राज्य सरकार उत्तराखंड को हरित विकास का राष्ट्रीय मॉडल बनाने की दिशा में कार्य कर रही है। पीएम सूर्य घर योजना के तहत 40 हजार रूफटॉप सोलर संयंत्रों का प्रारंभिक लक्ष्य निर्धारित समय से पहले हासिल कर लिया गया है तथा कुल लक्ष्य का लगभग 95 प्रतिशत कार्य पूरा हो चुका है।

मंजूरी हरियाणा कैबिनेट बैठक में 26 में से 22 एजेंडे पास, प्रॉपर्टी टैक्स पर नया फार्मूला होगा लागू

अग्निवीरों को 20 फीसदी रिजर्वेशन; ईवी खरीद पर 100% तक छूट

एजेंसी, चंडीगढ़। मंगलवार को चंडीगढ़ में हरियाणा कैबिनेट की अहम बैठक हुई। सीएम नायब सैनी की अध्यक्षता में हुई इस बैठक में 26 एजेंडे रखे गए थे, जिसमें से 22 एजेंडे पास हुए। बैठक के बाद सीएम ने सबसे पहले कॉमनवेल्थ गेम्स में हरियाणा की खिलाड़ी शर्मिला के पैरा शॉटपुट में गोल्ड मेडल जीतने पर बधाई दी।

उन्होंने कहा कि कॉमनवेल्थ में शर्मिला ने शॉटपुट में गोल्ड जीतकर देश का नाम रोशन किया है। उम्मीद है अन्य खिलाड़ी भी पदक जीतकर देश का नाम रोशन करेंगे। हरियाणा मंत्रिमंडल की बैठक के बाद मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने प्रेसवार्ता कर कैबिनेट के निर्णयों की जानकारी दी। कैबिनेट ने अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने, इलेक्ट्रिक वाहनों पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट, महिलाओं के नाम पर वाहन खरीदने पर कर राहत, हरियाणा राज्य अल्पसंख्यक आयोग के गठन और शहीदों के आश्रितों को अनुकंपा नियुक्ति में समय सीमा में छूट देने समेत कई महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। कैबिनेट ने इंडियन रिजर्व बटालियन, स्टेट डिजास्टर रिस्पॉन्स फोर्स, फायरमैन और वाइल्डलाइफ गार्ड के पदों पर हरियाणा के निवासी अग्निवीरों को 20 प्रतिशत क्षैतिज आरक्षण देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी है।

राज्य सरकार पहले ही ग्रुप-बी के पदों पर 1 प्रतिशत, ग्रुप-सी के पदों पर 5 प्रतिशत तथा पुलिस कांस्टेबल, फॉरेस्ट गार्ड, जेल वार्डर और माइनिंग गार्ड के पदों पर 20 प्रतिशत आरक्षण की व्यवस्था कर चुकी है। मुख्यमंत्री की घोषणा के अनुरूप महिलाओं के नाम पर 20 लाख रुपए तक की एक्स-शोरूम कीमत वाले नॉन-ट्रांसपोर्ट वाहनों के नए पंजीकरण पर एक प्रतिशत कर छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई ह। यह लाभ वर्तमान मोटर वाहन कर में मिलने वाली छूट के अतिरिक्त होगा। वहीं, राज्य में ग्रीन मोबिलिटी को बढ़ावा देने के लिए 30 लाख रुपए तक मूल्य वाले दो, तीन और चार पहिया इलेक्ट्रिक वाहनों के पंजीकरण पर 100 प्रतिशत वाहन कर छूट देने का फैसला किया गया है। हालांकि, सीएनजी वाहनों पर पहले से लागू 20 प्रतिशत कर छूट जारी रहेगी।

पीएम आवास योजना के लाभार्थियों को मिलेगी राहत

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी 2.0 के तहत पंजीकृत आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लाभार्थियों के लिए 60 वर्गमीटर तक की पात्र आवासीय इकाइयों पर स्टांप ड्यूटी और पंजीकरण शुल्क में छूट देने के प्रस्ताव को मंजूरी दी गई है। रेवाड़ी में कुसुम इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी की स्थापना के लिए बिल लाने के प्रस्ताव को भी मंजूरी दी गई है।

पुलिस हिरासत में मौत पर मिलेगा मुआवजा

हरियाणा सरकार ने मानवाधिकारों को सुनिश्चित करने के लिए पुलिस हिरासत में होने वाली मौत के मामलों में मृतक के उत्तराधिकारियों या निकटतम परिजनों को 7.5 लाख रुपए मुआवजा देने का प्रावधान किया है। यह मुआवजा पुलिस हिरासत में यातना, पिटाई, आत्महत्या या ड्यूटी में लापरवाही के कारण हुई मृत्यु के मामलों में मिलेगा- प्राकृतिक मृत्यु, बीमारी, हिरासत से भागने के दौरान हुई मृत्यु अथवा प्राकृतिक आपदा के कारण हुई मौत के मामलों में यह प्रावधान लागू नहीं होगा।

पटवारियों की प्रशिक्षण अवधि घटाई

कैबिनेट ने हरियाणा राजस्व पटवारी समूह-सी सेवा नियम, 2011 में संशोधन को मंजूरी दी है. नए नियमों के तहत पटवारियों की अनिवार्य प्रशिक्षण अवधि को डेढ़ वर्ष से घटाकर एक वर्ष कर दिया गया है। इसमें छह माह का संस्थागत प्रशिक्षण और छह माह का फील्ड प्रशिक्षण शामिल होगा।

न्यूज ब्रीफ

बीटेक, बीफार्मेसी की 1677 सीटें आवंटित

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर ने बीटेक, बी-फार्मेसी (डायरेक्ट एंट्री) की चौथे चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में 1677 सीटें आवंटित की गई। बीटेक में प्रवेश के लिए अभ्यर्थियों को सीटें का आवंटित एचपीसीईटी की मेरिट और अभ्यर्थियों द्वारा चुने शिक्षण संस्थानों के विकल्प के आधार पर किया है, जबकि बी फार्मेसी की 438 सीटें जमा दो की मेरिट के आधार पर आवंटित की गई। इसके अलावा एम फार्मेसी के पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग में दस सीटें आवंटित की गई। तकनीकी विवि के अधिष्ठाता शैक्षणिक डॉ राजेश कुमार ने कहा कि बीटेक व बी फार्मेसी (डायरेक्ट एंट्री) में तकनीकी विवि सहित संबंधित निजी व सरकारी शिक्षण संस्थानों में बीटेक (डायरेक्ट एंट्री) और बी फार्मेसी (डायरेक्ट एंट्री) की 1677 सीटें आवंटित की गई, जिन अभ्यर्थियों को सीटें आवंटित की गई है, उन्हें 30 जुलाई तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट करनी होगी, जहां उसे सीट मिली है। जो अभ्यर्थी तय तिथि को पांच बजे तक संबंधित शिक्षण संस्थान में रिपोर्ट नहीं करेगा, वह सीट खाली मानी जाएगी। हिमाचल प्रदेश तकनीकी विश्वविद्यालय हमीरपुर की फार्मेसी व बी टेक (लेटरल एंट्री) की पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 29 जुलाई होगी। डिप्लोमा की मेरिट के आधार पर बी फार्मेसी और बीटेक (लेटरल एंट्री) की सीटें आवंटित की जाएगी। वहीं, बी आर्क की ऑनलाइन काउंसलिंग के पहले चरण की सीटें भी 29 जुलाई को नाटा के मेरिट पर आवंटित की जाएगी। एमटेक की पहले चरण की ऑनलाइन काउंसलिंग 29 जुलाई को ही होगी।

30 जुलाई से शुरू होगी किन्नौर कैलाश यात्रा

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। सावन के पवित्र महीने में होने वाली किन्नौर कैलाश यात्रा इस वर्ष 30 जुलाई से शुरू होगी। जिला प्रशासन ने यात्रा को 10 अगस्त तक संचालित करने का निर्णय लिया है। हालांकि यात्रा की अवधि मौसम की परिस्थितियों पर निर्भर रहेगी और जरूरत पड़ने पर इसमें बदलाव किया जा सकता है। प्रशासन ने साफ किया है कि बिना पंजीकरण किसी भी श्रद्धालु को यात्रा की अनुमति नहीं दी जाएगी। जिला प्रशासन के अनुसार ऑनलाइन पंजीकरण आज 28 जुलाई से शुरू हो गया है, जबकि ऑफलाइन पंजीकरण 30 जुलाई से होगा। प्रतिदिन 375 श्रद्धालु ही यात्रा कर सकेंगे। इनमें 175 ऑनलाइन, 125 ऑफलाइन और 75 श्रद्धालुओं के लिए एडवेंचर टूर ऑपरेटर्स एसोसिएशन, किन्नौर के माध्यम से स्लॉट निर्धारित किए गए हैं। यात्रा केवल तंगलिंग-मेलिंग खड्ड-गुफा मार्ग से संचालित होगी। यात्रा से पहले प्रशासन ने दो चरणों में मार्ग का निरीक्षण कराया। शुरुआती रैकी में कई स्थानों पर भूस्खलन और पत्थर गिरने का खतरा मिलने के कारण यात्रा को अस्थायी रूप से रोक दिया गया था। बाद में दोबारा निरीक्षण के बाद संवेदनशील स्थानों पर सुरक्षा और मरम्मत का काम पूरा किया गया। इसके बाद यात्रा शुरू करने का फैसला लिया गया। यात्रा मार्ग पर पुलिस, स्वास्थ्य, वन, होमगार्ड, जल शक्ति और राजस्व विभाग के कर्मचारी तैनात रहेंगे। विभिन्न पड़ावों पर डॉक्टर, फार्मासिस्ट और पुलिस बल भी मौजूद रहेगा।

महिला पर आवारा बैल ने किया हमला, मौत

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला जिले के रामपुर उपमंडल में जंगल से चारा लेने गई एक महिला की आवारा बैल के हमले में मौत हो गई। पुलिस की जांच में सामने आया है कि महिला की मौत बैल के हमले से लगी अंदरूनी चोटों के कारण हुई। मामले में किसी तरह के संदेह या अन्य कारण के संकेत नहीं मिले हैं। पुलिस के अनुसार सराहन क्षेत्र के खन्टी गांव की रहने वाली 54 वर्षीय श्यामा दासी, पत्नी जय सिंह, 26 जुलाई को पशुओं के लिए चारा लेने जंगल गई थीं। इसी दौरान एक आवारा बैल ने उन पर हमला कर दिया और उन्हें गंभीर चोटें आईं। आसपास के ग्रामीण उन्हें तुरंत उपचार के लिए महात्मा गांधी चिकित्सा सेवा परिसर (एमजीएमएससी) खनेरी अस्पताल लेकर पहुंचे अस्पताल में डॉक्टरों ने प्राथमिक उपचार के बाद उनकी गंभीर स्थिति को देखते हुए उन्हें इंदिरा गांधी मेडिकल कॉलेज (आईजीएमसी), शिमला रेफर कर दिया। पुलिस के अनुसार, शिमला ले जाते समय रास्ते में उनकी मौत हो गई। इसके बाद परिजन शव को वापस खनेरी अस्पताल लेकर आए, जहां पुलिस ने आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी कर पोस्टमार्टम करवाया। पोस्टमार्टम के बाद शव अंतिम संस्कार के लिए उनके बेटे जगमोहन को सौंप दिया गया। झाकड़ी थाना पुलिस ने घटनास्थल की जांच की और गवाहों के बयान दर्ज किए। जांच में यह पाया गया कि महिला की मौत आवारा बैल के हमले से लगी अंदरूनी चोटों के कारण हुई। पुलिस ने बताया कि मामले में किसी प्रकार का शक या संदेह सामने नहीं आया है।

11 हजार फुट ऊंचाई पर हरियाली बढ़ाने की पहल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। समुद्र तल से करीब 11,000 फुट की ऊंचाई पर स्थित हाटू पीक, नारकंडा में आयोजित दो दिवसीय उच्च हिमालयी पौधरोपण अभियान का मंगलवार को सफलतापूर्वक समापन हुआ। पर्यावरण संरक्षण और क्षेत्र में हरित आवरण को मजबूत करने के उद्देश्य से आयोजित इस अभियान में 133 ईको टास्क फोर्स, अज्ञातवास इकोलॉजिकल रिजॉर्ट के कर्मचारियों, हिमाचल प्रदेश वन विभाग के अधिकारियों एवं कर्मचारियों, गुज्जर समुदाय तथा नारकंडा के स्थानीय नागरिकों ने बढ़-चढ़कर भाग लिया। अभियान के दौरान उच्च हिमालयी क्षेत्र में विभिन्न पौधों का रोपण किया गया। प्रतिभागियों ने लगाए गए पौधों की देखभाल और संरक्षण का संकल्प लिया। साथ ही हाटू पीक क्षेत्र को कचरा मुक्त रखने, प्राकृतिक सुंदरता और पर्यावरणीय संतुलन बनाए रखने का भी प्रण लिया। इस अवसर पर तहसीलदार सीबी, मुख्य वन संरक्षक (सीसीएफ) रामपुर, कर्नल विजेंद्र सांगवान, अरुण कुमार, प्रभागीय वन अधिकारी (डीएफओ) कोटगढ़, वन विभाग के अधिकारी, सामाजिक कार्यकर्ता और अन्य गणमान्य व्यक्ति मौजूद रहे। सभी ने पर्यावरण संरक्षण के लिए सामुदायिक भागीदारी से किए जा रहे प्रयासों की सराहना की।

दिल्ली-मनाली वोल्वो बस में सवार युवक युवती से 143 ग्राम चिट्टा बरामद, गिरफ्तार

सुंदरनगर में नाकाबंदी के दौरान पकड़े गए दो आरोपी, कुल्लू के रहने वाले हैं दोनों

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नशे के कारोबार के खिलाफ चल रहे मंडी जिला पुलिस के अभियान में मंगलवार सुबह एक बड़ी कामयाबी हासिल हुई है। दिल्ली से मनाली जा रही एक वोल्वो बस में सवार युवक युवती से 143 ग्राम 180 मिलीग्राम चिट्टा बरामद हुआ। दोनों ही आरोपी कुल्लू जिला के रहने वाले हैं।

पुलिस अधीक्षक मंडी विनोद कुमार ने बताया कि मंडी पुलिस द्वारा नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत मंगलवार सुबह जब सुंदरनगर थाना की पुलिस ने फोरलेन पर पुंघ में नाका लगा रखा था और वाहनों को चेक किया जा रहा था तो इस दौरान दिल्ली से मनाली जा रही एक वोल्वो बस को भी रोका गया। चेकिंग के दौरान बस में सवार एक युवक व युवती पर संदेह हुआ और वह घबराए हुए पाए गए तो उनकी तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान इनके पास से 143 ग्राम 180 मिलीग्राम चिट्टा यानी हेरोइन बरामद की गई। इनकी पहचान हनीश ठाकुर निवासी जिला कुल्लू व अंशिता नेगी निवासी मनाली जिला कुल्लू के तौर पर हुई है। दोनों ही आरोपियों को एनडीपीएस एक्ट की धारा 21 एवं 29 के तहत गिरफ्तार कर लिया गया। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि इन दोनों को अदालत में पेश करके रिमांड हासिल किया गया है तथा इनसे कड़ी पूछताछ की जा रही है। पुलिस के अनुसार चिट्टा की यह मात्रा अत्यधिक है। ऐसे में इसके स्त्रोत एवं इस अवैध कारोबार से जुड़े अन्य व्यक्तियों की संलिप्तता का पता लगाया जा रहा है। उन्होंने बताया कि नशे का कारोबार करने वालों के खिलाफ अभियान लगातार जारी रहेगा। ऐसे लोगों को किसी भी हालत में बख्शा नहीं जाएगा।

एचआरटीसी बस में 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद, एक गिरफ्तार

शिमला। शिमला पुलिस ने नशा तस्करी के खिलाफ कार्रवाई करते हुए, चंडीगढ़ से शिमला आ रही एचआरटीसी की एक बस से 10.34 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद किया है। इस मामले में शिमला के कृष्णा नगर निवासी सौरव घारु को गिरफ्तार किया गया है। पुलिस आरोपी से पूछताछ कर यह पता लगाने की कोशिश कर रही है कि वह नशीला पदार्थ कहां से लेकर आया था और इसे किसे पहुंचाया जाना था। पुलिस के अनुसार स्पेशल सेल की टीम को 26 जुलाई को विश्वसनीय सूचना मिली थी कि सौरव घारु चंडीगढ़ से शिमला आ रही एचआरटीसी बस में चिट्टा लेकर आ रहा है। सूचना मिलने के बाद पुलिस ने शोघी पुलिस चौकी के पास नाकाबंदी कर बस को रोका और तलाशी ली। तलाशी के दौरान आरोपी की सीट के नीचे से 10.34 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। इसके बाद पुलिस ने एनडीपीएस अधिनियम की धारा 21 के तहत मामला दर्ज कर आरोपी को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के एक अधिकारी ने मंगलवार को बताया कि आरोपी को अदालत में पेश किया, जहां से उसे पुलिस रिमांड पर लिया गया है। मामले की जांच जारी है और पुलिस इस पूरे नेटवर्क से जुड़े अन्य लोगों की भूमिका का भी पता लगा रही है।

कार्य निरीक्षक संघ ने विक्रमादित्य सिंह से उठाई वेतन विसंगति दूर करने और पदोन्नति की मांग

भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। लोक निर्माण विभाग एवं जल शक्ति विभाग के कार्य निरीक्षक संघ के प्रतिनिधिमंडल ने प्रदेश अध्यक्ष हितेंद्र ठाकुर और प्रदेश महामंत्री सुनील ठाकुर के नेतृत्व में लोक निर्माण एवं शहरी विकास मंत्री विक्रमादित्य सिंह से कुल्लू स्थित विश्राम गृह में मुलाकात की।

प्रतिनिधिमंडल ने कार्य निरीक्षकों की विभिन्न लंबित मांगों को मंत्री के समक्ष रखा और उनके शीघ्र समाधान की मांग की। संघ ने वर्ष 2016 में लागू किए गए नए वेतनमान में कार्य निरीक्षकों को 5,910 ग्रेड पे के अंतर्गत रखने पर आपत्ति जताई। उन्होंने कहा कि पटवारी, फॉरेस्ट गार्ड, क्लर्क सहित समकक्ष श्रेणियों को 10,300 वेतनमान दिया गया है, इसलिए कार्य निरीक्षकों की वेतन विसंगति दूर कर उन्हें भी समान वेतनमान प्रदान किया जाए। प्रतिनिधिमंडल ने बताया कि विभाग में कनिष्ठ अभियंता के 500 से अधिक पद रिक्त हैं, जबकि 52 कार्य निरीक्षक 18 से 20 वर्ष की नियमित सेवा पूरी कर चुके हैं। इन कर्मचारियों को विभागीय खर्चे पर राजकीय बहु-तकनीकी संस्थान सुंदरनगर से छह माह का प्रशिक्षण भी दिलाया गया है। संघ ने मांग की कि अनुभवी कार्य निरीक्षकों को शीघ्र कनिष्ठ अभियंता के पद पर पदोन्नति दी जाए, जिससे विभाग को भी लाभ मिलेगा।

इसके अलावा प्रशिक्षण प्राप्त कार्य निरीक्षकों के लिए पदोन्नति कोटा 4 प्रतिशत से बढ़ाकर 12 प्रतिशत करने तथा 16 वर्ष की नियमित सेवा पूरी करने वाले कार्य निरीक्षकों को सहायक कनिष्ठ अभियंता का पदनाम देने की मांग भी रखी गई। इस अवसर पर संघ के पदाधिकारियों सहित कुल्लू जिला प्रधान नीरत सिंह, ओमप्रकाश, राजेंद्र कुमार, लाल सिंह, वेदराम, पवन कुमार, कृष्ण लाल, नौक सिंह, धनी राम सहित अन्य सदस्य मौजूद रहे।

सुक्खू सरकार ने पेपर लीक के दोषियों को बचाने और जांच रुकवाने का किया काम : जयराम ठाकुर

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पूर्व मुख्यमंत्री और नेता प्रतिपक्ष जयराम ठाकुर ने मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू पर भर्ती प्रक्रियाओं और कथित पेपर लीक मामलों को लेकर निशाना साधा है।

मंगलवार को जारी बयान में उन्होंने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री यह दावा कर रहे हैं कि उनकी सरकार के दौरान कोई पेपर लीक नहीं हुआ, जबकि प्रदेश की जनता जानना चाहती है कि सरकार ने कितनी भर्तियां पूरी की हैं। उन्होंने कहा कि पेपर लीक के दोषियों को सजा देने के बजाय उन्हें बचाने और जांच को रोकने का काम किया गया। जयराम ठाकुर ने कहा कि प्री-नर्सरी शिक्षक भर्ती प्रक्रिया के दौरान भ्रष्टाचार के आरोप सामने आए, जिसके बाद भर्ती रोक दी गई। उनके अनुसार इससे छोटे बच्चों की पढ़ाई प्रभावित हुई और कई शिक्षकों को अपनी जेब से खर्च कर शिक्षक रखने पड़े। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि चिकित्सा अधिकारियों और नर्सों की भर्ती के लिए आउटसोर्स एजेंसियों के माध्यम से गड़बड़ियां हुईं। उन्होंने दावा किया कि इस मामले में उच्च न्यायालय ने भी कड़ी टिप्पणियां की थीं और कई बार भर्ती प्रक्रिया पर रोक लगी। उन्होंने यह भी आरोप लगाया कि सरकार के मंत्री सार्वजनिक मंचों से सिफारिश के आधार पर नौकरियां दिलाने की बातें करते रहे हैं। नेता प्रतिपक्ष ने हाल में हुई पुलिस भर्ती का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि परीक्षा में शामिल अभ्यर्थियों ने सामूहिक नकल और पेपर बेचने-खरीदने के आरोप लगाए थे। उनके अनुसार पुलिस की कार्रवाई में कुछ आरोपी पकड़े गए, जिनसे नकदी और लेन-देन से जुड़े रिकॉर्ड भी मिले। जयराम ठाकुर ने आरोप लगाया कि इतने गंभीर मामले के बाद भी सरकार ने जांच आगे नहीं बढ़ाई।

104 ग्राम चरस सहित आरोपी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, नाहन। जिला सिरमौर पुलिस ने मादक पदार्थों की तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए पुलिस थाना माजरा क्षेत्र से 104 ग्राम चरस बरामद कर एक व्यक्ति को गिरफ्तार किया है। पुलिस से प्राप्त जानकारी के अनुसार 27 जुलाई को गश्त के दौरान पुलिस टीम को गुप्त सूचना मिली कि मनवर अली पुत्र नीना खान, निवासी गांव मेलियों, डाकघर माजरा, तहसील पांवटा साहिब, जिला सिरमौर, अपने रिहायशी मकान से चरस की बिक्री का अवैध कारोबार कर रहा है। सूचना के आधार पर पुलिस ने तत्काल कार्रवाई करते हुए आरोपी के घर पर दबिश दी। तलाशी के दौरान उसके कब्जे से 104 ग्राम चरस बरामद की गई। बरामदगी के बाद पुलिस ने मनवर अली को मौके पर ही गिरफ्तार कर लिया। इस संबंध में पुलिस थाना माजरा में आरोपी के खिलाफ एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है।

केंद्र सरकार से सहयोग न मिलने के बाद भी विकास कार्य जारी: विनय

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष विनय कुमार ने प्रदेश के भाजपा नेताओं पर आरोप लगाया है कि वह केंद्रीय मंत्रियों के समक्ष झूठ बोलकर प्रदेश की छवि धूमिल करने का प्रयास कर रहें है। उन्होंने कहा है कि मुख्यमंत्री सुक्खू के नेतृत्व में सरकार वित्तीय अनुशासन के साथ अपने सभी दायित्व को सफलता पूर्वक पूरा कर रही है।

विनय कुमार ने कहा है कि केंद्र सरकार प्रदेश के विकास में कोई भी सहयोग नहीं दे रही है। बाबजूद इसके प्रदेश सरकार ने अपने सीमित संसाधनों से सभी विकास कार्यो को भी गति प्रदान कर रही है और प्राकृतिक आपदाओं भारी बारिश से हो रहें नुकसान से भी लोगों को राहत प्रदान कर रही है। विनय कुमार ने कहा है कि प्रदेश में भारी बारिश से आपदा प्रभावित सभी परिवारों को जिनके घर पूरी तरह से ध्वस्त हो रहें है उन्हें घर निर्माण के लिये 7.50 लाख और घर का सामान खरीद के लिए 1 लाख अतिरिक्त दे रही है। उन्होंने कहा है कि प्रदेश में आपदा राहत के लिये न तो केंद्र से कोई सहायता मिल रही है और न ही भाजपा इसमें कोई सहयोग दे रही है। झूठ बोल कर लोगों को गुमराह करना भाजपा का मुख्य एजेंडा है ,जो बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। विनय कुमार ने कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 2024 में प्रदेश को आपदा राहत के लिये 1500 करोड़ देने की बात कही थी, वह आज दिन तक पूरी नहीं हुई। भाजपा इस पर कभी अपना मुंह नहीं खोलती। प्रदेश की आरडीजी बंद कर दी गई है। इस पर भी भाजपा के मुंह पर ताला लगा है।

बिलासपुर आयुर्वेदिक अस्पताल को जल्द मिलेगी सीबीसी मशीन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। उपायुक्त राहुल कुमार ने मंगलवार को आयुर्वेदिक अस्पताल बिलासपुर का निरीक्षण कर वहां उपलब्ध स्वास्थ्य सुविधाओं व उपचार व्यवस्थाओं का जायजा लिया। उन्होंने अस्पताल के विभिन्न चिकित्सकीय कक्षों, ओपीडी, औषधि वितरण केंद्र तथा मरीजों को उपलब्ध करवाई जा रही दवाइयों की व्यवस्था का निरीक्षण किया। इस दौरान डीसी ने मरीजों और उनके परिजनों से बातचीत कर स्वास्थ्य सेवाओं की जानकारी ली। उन्होंने चिकित्सकों और अस्पताल प्रशासन को निर्देश दिए कि मरीजों को गुणवत्तापूर्ण, समयबद्ध और पारदर्शी स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाई जाएं। अस्पताल प्रशासन ने मरीजों की सुविधा के लिए सीबीसी मशीन उपलब्ध करवाने की मांग रखी, जिस पर उपायुक्त ने जल्द आवश्यक कार्रवाई करने का आश्वासन दिया। उन्होंने कहा कि जिला प्रशासन बेहतर स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध करवाने के लिए आवश्यक संसाधनों और उपकरणों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के प्रयास कर रहा है। उन्होंने स्वच्छता, दवा उपलब्धता और उपचार व्यवस्था में निरंतर सुधार के निर्देश दिए।

महिला मोर्चा ने किया पौधरोपण

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। पर्यावरण संरक्षण व हरियाली बढ़ाने के उद्देश्य से चलाए जा रहे 'एक पेड़ मां के नाम' अभियान के तहत भाजपा महिला मोर्चा जिला शिमला ने मंगलवार को कसुम्पटी विधानसभा क्षेत्र के भट्टाकुफर स्थित ज्वाला माता मंदिर के समीप पौधरोपण कार्यक्रम आयोजित किया। कार्यक्रम में पूर्व मंत्री सुरेश भारद्वाज और जिला परिषद सदस्य खुश विक्रम सेन विशेष रूप से उपस्थित रहे। उन्होंने पौधारोपण कर अभियान में भागीदारी निभाई और कहा कि पर्यावरण संरक्षण के लिए जनभागीदारी जरूरी है। उन्होंने कहा कि यह अभियान प्रकृति संरक्षण के साथ मातृत्व सम्मान का प्रतीक भी है। कार्यक्रम की अध्यक्षता भाजपा महिला मोर्चा जिला शिमला अध्यक्ष रीना शर्मा ने की। इस दौरान महिला मोर्चा पदाधिकारियों और कार्यकर्ताओं ने पौधे लगाए तथा उनकी देखभाल का संकल्प लिया। सुरेश भारद्वाज ने लोगों से पौधरोपण को निरंतर प्रक्रिया बनाकर लगाए गए पौधों की नियमित देखभाल करने का आह्वान किया।

भाजपा का कार्यकर्ता संवाद अभियान विधायक जीतराम ने गिनाईं उपलब्धियां

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। झंडूता विधानसभा क्षेत्र में भाजपा के कार्यकर्ता संवाद एवं समन्वय अभियान के तहत विधायक जीतराम कटवाल ने मंगलवार को डाहड, नखलेहड़ा और दाड़ी-भाड़ी पंचायतों का दौरा किया।

इस दौरान उन्होंने कार्यकर्ताओं से संवाद करते हुए भाजपा संगठन की मजबूती और केंद्र सरकार की उपलब्धियों पर चर्चा की। डाहड पंचायत में आयोजित कार्यक्रम के दौरान डाहड, टिकरी और डैहण गांव के जयचंद, मेहर सिंह ढटवालिया, राजेंद्र और हंसराज शर्मा ने प्रदेश कांग्रेस सरकार की नीतियों से नाराज होकर भाजपा की सदस्यता ग्रहण की। विधायक जीतराम कटवाल ने उन्हें भगवा पटका पहनाकर भाजपा परिवार में स्वागत किया। उन्होंने कहा कि भाजपा केवल राजनीतिक दल नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण का अभियान है। संगठन की सबसे बड़ी ताकत समर्पित कार्यकर्ता हैं। कार्यकर्ताओं के आपसी संवाद, समन्वय और एकजुटता से संगठन और मजबूत होता है। उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में देश में हो रहे विकास कार्यों का उल्लेख करते हुए कहा कि भारत आधुनिक सड़कों, रेल, डिजिटल क्रांति, किसान कल्याण, महिला सशक्तिकरण और युवाओं के लिए नए अवसरों के क्षेत्र में तेजी से आगे बढ़ रहा है। कांग्रेस सरकार पर निशाना साधते हुए कटवाल ने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार चुनावी गारंटियां पूरी करने में विफल रही है। उन्होंने कार्यकर्ताओं से केंद्र सरकार की योजनाओं को घर-घर पहुंचाने और प्रदेश सरकार की कथित विफलताओं को जनता के बीच रखने का आह्वान किया। इस अवसर पर विधायक ने लोगों की समस्याएं भी सुनीं और अधिकांश का मौके पर समाधान किया, जबकि अन्य मामलों के लिए संबंधित अधिकारियों को निर्देश दिए।

धार कलां की 27,550 एकड़ जमीन का मामला गरमाया

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। पठानकोट जिले के कंडी क्षेत्र धार कलां में जमीन के मालिकाना हक को लेकर विवाद एक बार फिर गरमा गया है। किसान संघर्ष कमेटी धार कलां की ओर से गांव बुंगल में आयोजित बैठक में राजस्व विभाग द्वारा 27,550 एकड़ जमीन का इंतकाल वन विभाग के नाम दर्ज किए जाने के मामले पर कड़ा विरोध जताया गया। बैठक में धार ब्लॉक के विभिन्न गांवों से सरपंच, पूर्व सरपंच, पंच, नंबरदार और बड़ी संख्या में किसान शामिल हुए।

किसान संघर्ष कमेटी ने बुलाई बैठक, जमीन हकूक को लेकर आर-पार की लड़ाई का ऐलान

कमेटी के उपाध्यक्ष जगजीत सिंह और सचिव किशन चंद गोस्वामी की अध्यक्षता में हुई बैठक में किसानों ने आरोप लगाया कि उपजाऊ और शामलात जमीन का इंतकाल गैर-कानूनी तरीके से वन विभाग के नाम किया गया है। किसान संघर्ष कमेटी के खजांची रविकांत शर्मा ने कहा कि वर्ष 1904 की फॉरेस्ट सेटलमेंट में जमीन की मलकीयत स्थानीय निवासियों और जमीन मालिकों की दर्ज है, जबकि सरकार का अधिकार केवल चील के पेड़ों तक सीमित बताया गया था। उन्होंने आरोप लगाया कि वर्ष 2018 में उपायुक्त पठानकोट कार्यालय की ओर से जारी पत्र की भी अनदेखी की गई और प्रभावित जमीन मालिकों से आपत्तियां तक नहीं मांगी गईं। किसानों ने कहा कि इंतकाल प्रक्रिया के खिलाफ पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट में कई याचिकाएं दायर हैं और कुछ मामलों में स्थगन आदेश भी जारी हैं। किसान नेताओं ने आरोप लगाया कि पुराने अदालती फैसलों को आधार बनाकर पूरे क्षेत्र की जमीनों पर लागू किया जा रहा है, जबकि संबंधित फैसले सीमित जमीनों से जुड़े थे। उन्होंने बताया कि इस मामले में 250 से अधिक किसान विभिन्न अदालतों में कानूनी लड़ाई लड़ रहे हैं। बैठक में किसानों ने चेतावनी दी कि यदि न्यायालय के आदेशों की अनदेखी कर जमीनों पर कार्रवाई की गई तो धार क्षेत्र में बड़ा आंदोलन किया जाएगा। उन्होंने कहा कि किसान पीढ़ियों से इन जमीनों पर खेती करते आ रहे हैं और उनके पास पुराने राजस्व रिकॉर्ड मौजूद हैं। बैठक में राज कुमार, अंगराज पठानिया, जोगिंदर सिंह, कुणाल पठानिया, पूरन सिंह, रमेश शर्मा, स्वर्ण सिंह, रोशन लाल, सुखबीर सिंह, रणधीर सिंह, दयाल सिंह, सुनील कुमार सहित धार ब्लॉक के कई किसान और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

अंतरराष्ट्रीय एक्सपो-2026 में प्रदेश को मिला प्रथम पुरस्कार, फसल विविधीकरण मॉडल की हुई सराहना

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। नई दिल्ली के प्रगति मैदान में आयोजित तीन दिवसीय इंटरनेशनल एग्रीकल्चर, हॉर्टिकल्चर व ऑर्गेनिक एक्सपो-2026 में हिमाचल प्रदेश बागवानी विभाग ने अपनी आधुनिक एवं वैज्ञानिक बागवानी प्रणाली, फसल विविधीकरण मॉडल तथा उच्च मूल्य वाली फसलों के प्रभावशाली प्रदर्शन के लिए प्रथम पुरस्कार से नवाजा गया है।

इस उपलब्धि से हिमाचल प्रदेश ने राष्ट्रीय एवं अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अपनी विशिष्ट पहचान स्थापित करते हुए प्रदेश का गौरव बढ़ाया है। बागवानी निदेशक डॉ. सतीश कुमार शर्मा ने इस उपलब्धि पर विभागीय अधिकारियों, वैज्ञानिकों और प्रदेश के बागवानों को बधाई देते हुए कहा कि यह सम्मान हिमाचल के किसानों, वैज्ञानिकों और अधिकारियों के सामूहिक प्रयासों का परिणाम है। उन्होने बताया कि प्रदर्शनी में देश-विदेश से आए किसानों, वैज्ञानिकों, कृषि विशेषज्ञों, उद्यमियों और नीति-निर्माताओं ने हिमाचल प्रदेश के स्टॉल का अवलोकन किया। डॉ. सतीश शर्मा ने कहा कि इस सफलता का श्रेय मुख्यमंत्री सुखविंद्र सिंह सुक्खू तथा बागवानी मंत्री जगत सिंह नेगी को जाता है, जिनके मार्गदर्शन में प्रदेश में चलाए जा रहे फसल विविधीकरण अभियान का साक्षात परिणाम है।

उन्होंने कहा कि प्रदेश अब केवल सेब राज्य तक सीमित नहीं है, बल्कि फल विविधीकरण, संरक्षित खेती और उच्च मूल्य वाली फसलों के माध्यम से फल राज्य बनने की दिशा में तेजी से आगे बढ़ रहा है। इससे किसानों की आय बढ़ाने के साथ-साथ प्रदेश के बागवानी उत्पादों को राष्ट्रीय और अंतरराष्ट्रीय बाजारों में नई पहचान मिलेगी। बागवानी निदेशक ने बताया कि प्रदर्शनी में ड्रैगन फ्रूट, एवोकाडो, ब्लूबेरी, कीवी, चेरी, अनार, स्ट्रॉबेरी, लिलियम सहित विभिन्न उच्च मूल्य वाली फसलों और जीआई टैग प्राप्त किन्नौरी सेब को प्रदर्शित किया गया। प्रदर्शनी के दौरान वरिष्ठ पौध संरक्षण अधिकारी डॉ. भूपिंदर सिंह नेगी, उत्कृष्टता बागवानी केंद्र शिलारू के विषय विशेषज्ञ डॉ. कुशाल सिंह मेहता तथा मधुमक्खी पालक दमेश कुमार शर्मा ने हजारों किसानों और आगंतुकों को आधुनिक बागवानी योजनाओं, वैज्ञानिक खेती और जलवायु अनुकूल कृषि तकनीकों की जानकारी प्रदान की।

परेशानी दवाइयों और जरूरी सामान की कमी से जूझ रहा मेडिकल कॉलेज हमीरपुर

छोटी सर्जिकल सामग्री भी बाहर से लाने की नौबत

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। डॉ. राधाकृष्णन मेडिकल कॉलेज हमीरपुर में इमरजेंसी में आने वाले मरीजों को भी छोटी-छोटी सर्जिकल की आइटम बाहर से लानी पड़ेंगी, तो फिर किस नाम की इमरजेंसी सेवाएं।

मरीज को पर्ची पर लिख कर बाहर से सामान लाने के लिए कहा जा रहा है। कारण यह है मेडिकल कॉलेज में दवाई और अन्य सामान की सप्लाई नहीं आ रही है। मेडिकल कॉलेज में 3 महीने पहले नई सप्लाई के लिए जो आर्डर प्लेस हुआ था उसकी स्थिति यह है कि संबंधित जिस फर्म को यह सप्लाई किया जाना था, वहां से न ही तो ना का जवाब आ रहा है और ना ही हां का। दिक्कत कहां है कोई बताने को तैयार नहीं है। मेडिकल कॉलेज प्रशासन उच्च अधिकारियों को केवल पत्र लिखकर अपना फर्ज निभा रहा है। इससे मरीजों का भला कैसे हो सकता है। उनकी दिक्कतें कैसे दूर होंगी? दरअसल अस्पताल

इमरजेंसी सेवाओं पर सवाल: कैनुला, सिरिंज और जरूरी दवाओं के लिए मरीजों को भेजा जा रहा बाहर

मेडिकल कॉलेज प्रशासन बोला जल्द आएगी सप्लाई मरीजों की परेशानी जारी

में हर तीन महीनों के लिए बजट भी मुहैया होता है और उसकी खरीद भी उसी के आधार पर की जाती है। इस बार बजट केवल तकरीबन 21 लाख के आसपास आया है। अब इससे क्या खरीदा जाएगा, प्रशासन खुद असमंजस में है। लेकिन जितनी भी इससे खरीद हो सकती थी, उसका आर्डर प्लेस हो चुका है, आएगा कब कोई पता नहीं। इससे पहले तीन महीनों के लिए तकरीबन 88 लाख का बजट आया था। पहले यह बजट हर तीन महीनों के लिए एक करोड़ से ज्यादा का आता था। मरीज यहां लगातार बढ़े हैं, इसलिए यह बजट भी एक करोड़ से ज्यादा मिलना चाहिए था। लेकिन मिल नहीं रहा। केंद्र का पैसा भी इसमें शामिल है। अब इस खींचतान का 'नजला' मरीजों पर गिर रहा है। अब यदि इमरजेंसी में ही कैनुला, ग्लव्स, सिरिंज, कुत्तों के काटे जाने के बाद लगने वाले इंजेक्शन, दबाएं जिनमें पीसीएम भी शामिल है। पेट गैस की गोली भी यदि नहीं मिलेगी, तो फिर कॉटन और बैंडेड की तो उम्मीद कैसे यहां की जा सकती है। इसके अलावा हार्ट इंजेक्शन की भी अब दिक्कत शुरू होने वाली है। यह महंगा इंजेक्शन है, एआरबी का इंजेक्शन भी उपलब्ध नहीं हो रहा। सभी विभागों में इसकी दिक्कत है। डॉक्टर्स और अन्य स्टाफ के लिए मास्क भी दिए जाते थे, वह भी कम आ रहे हैं।

प्रिंसिपल रमेश भारती का कहना था कि कमी किसी चीज की नहीं है, थोड़ी बहुत दिक्कत आगे पीछे रहती है, उसका हल निकाला जा रहा है। उनका कहना था कि किसी ने उन्हें शिकायत नहीं की है। कौन सी चीज उन्हें उपलब्ध नहीं हो रही, लेकिन जब उनसे यह कहा गया कि आप इमरजेंसी के बाहर खड़े हो जाइए थोड़ी देर में सारी स्थिति अपने आप ब्यां हो जाएगी। उन्होंने कहा पता करेंगे, लेकिन सप्लाई जल्दी आने वाली है।

शिक्षा बोर्ड को कांग्रेस का राजनीतिक स्वागत केंद्र बना दिया: राकेश जम्वाल

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। भाजपा प्रदेश मुख्य प्रवक्ता राकेश जम्वाल ने हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड की कार्यप्रणाली पर गंभीर सवाल उठाते हुए कहा कि कांग्रेस सरकार ने संवैधानिक और शैक्षणिक संस्थाओं को भी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बना दिया है।

हिमाचल प्रदेश स्कूल शिक्षा बोर्ड के अध्यक्ष राजेश शर्मा की प्राथमिकताएं पूरी तरह सवालों के घेरे में हैं। एक ओर प्रदेश के हजारों विद्यार्थी अपनी मूल डीएमसी और मार्कशीट के लिए परेशान हैं, वहीं दूसरी ओर बोर्ड प्रशासन कांग्रेस नेताओं के स्वागत-सत्कार और राजनीतिक औपचारिकताओं में व्यस्त दिखाई दे रहा है। राकेश जम्वाल ने कहा कि हाल ही में कांग्रेस की वरिष्ठ नेता एवं हिमाचल मामलों की प्रभारी रजनी पाटिल के शिक्षा बोर्ड कार्यालय पहुंचने पर उनके स्वागत के लिए कर्मचारियों को लाइन में खड़ा किया गया। उन्होंने पूछा कि क्या शिक्षा बोर्ड का कार्य राजनीतिक मेहमानों का स्वागत करना है या विद्यार्थियों के भविष्य को सुरक्षित करना?

कार्यालय ग्राम पंचायत लोहडर विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

निविदा आमंत्रण सूचना

सर्वसाधारण को सूचित किया जाता है कि वित्तीय वर्ष 2026-2027 के विकास कार्य हेतु क्र. बजरी, क्र. रेता, प्लांट रेता, पक्की ईन्ट HOLLOW सिमेंट सेटरिंग, लोहा प्लेट, किराया प्लेट डंगे हेतू सेटरिंग लकड़ी किराया हेतू, रास्ते हेतू सेटरिंग किराया (लैंटर बीम कालम के लिए) प्रति स्केयर फुट मैटीरीयल ढुलाई (रेत, बजरी सीमेंट, ईंट लेवर व अन्य सामग्री) खच्चरों द्वारा दूरी के हिसाब से प्रति फुट, जे0सी0बी0 कच्चा व पक्का पटान, प्रति मीटर कंक्रीट, मिक्सर प्रति दिन के हिसाब से, साईन बोर्ड लिखाई, सीमेंट ढुलाई, गाड़ी सिविल सप्लाई डिपो से लोहडर पंचायत के किसी भी कोने पर लोडिंग व अनलोडिंग प्रति बैग आदि की निविदाएं आमंत्रित की जाती हैं। सभी निविदाएं 10 अगस्त 2026 शाम 5 बजे तक लिफाफे में बंद पंचायत कार्यालय में पहुंच जानी चाहिए। सभी निविदाएं दिनांक 12/08/2026 को 3 बजे कमेटी द्वारा पंचायत कार्यालय में खोली जाएंगी। निविदाएं हेतू निम्न शर्तें रखी गई हैः- 1. समग्री बिलों को M Form के साथ पंचायत में उपलब्ध करवाना अनिवार्य होगा अन्यथा बिल की अदायगी नहीं की जाएगी। 2. निविदा खोलने के दौरान निविदाताओं को उपस्थित होना आवश्यक है। अलग से कोई भी पत्र नहीं खोला जाएगा। 3. निविदाताओं के उपलब्ध न होने पर पंचायत द्वारा निविदा खोल दी जाएगी। 4. निविदाता के पास स्वयं के नाम का वैध जी0 एस0 टी0 का पंजीकरण होना अनिवार्य है।

प्रधान/सचिव ग्राम पंचायत लोहडर विकास खण्ड बिझड़ी, जिला हमीरपुर (हि.प्र.)

न्यूज शॉर्ट्स

उधम सिंह नगर में सामूहिक दुष्कर्म के तीन आरोपी मुठभेड़ के बाद गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, उधमसिंह। उत्तराखंड के उधम सिंह नगर जिले में एक युवती से कथित सामूहिक दुष्कर्म के मामले में पुलिस ने मंगलवार तड़के मुठभेड़ के बाद तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। मुठभेड़ के दौरान मुख्य आरोपी के पैर में गोली लगी, जिसके बाद उसे जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। पुलिस के अनुसार शनिवार रात सिडकुल में कार्यरत एक युवती अपने तीन दोस्तों के साथ घूमने निकली थी। आरोप है कि इसी दौरान बाइक सवार तीन युवकों ने उसका अपहरण कर गदरपुर क्षेत्र के जंगल में ले जाकर उसके साथ सामूहिक दुष्कर्म किया।

अल्मोड़ा में भारी बारिश से पितना-रणकुना मोटर मार्ग पर भरा मलबा

भारतेंदु संवाददाता, अल्मोड़ा। जिले में मंगल को मौसम का मिजाज पल-पल बदलता रहा। सुबह से आसमान में बादलों की आवाजाही बनी रही। दोपहर तक उमस रही, जबकि शाम होते-होते मुख्यालय समेत कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश हुई। लगातार वर्षा से ग्रामीण मोटर मार्ग पितना-रणकुना पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हो गया।

उत्तराखंड में भारी बारिश के कारण यमुनोत्री पैदल मार्ग धंसा

भारतेंदु संवाददाता, उत्तरकाशी। उत्तराखंड में लगातार बारिश के चलते यमुनोत्री हाईवे और जानकीचट्टी-यमुनोत्री पैदल मार्ग पर राम मंदिर के समीप नदी का जलस्तर बढ़ने से लगभग 25 से 30 मीटर पैदल मार्ग 2 से 2.5 मीटर तक धंस गया है। मार्ग के क्षतिग्रस्त होने के कारण वर्तमान में इस हिस्से से यात्रियों की आवाजाही सुरक्षित नहीं मानी जा रही है।

उत्तराखंड में अगले 3 दिन भारी बारिश की चेतावनी 9 जिलों में ऑरेंज अलर्ट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून के तेवर फिर तल्ख होने लगे हैं। पहाड़ से लेकर मैदान तक दिनभर बादलों का डेरा है और बौछारों के दौर जारी हैं। इस बीच ज्यादातर क्षेत्रों में भारी बारिश के आसार बने हुए हैं। मौसम विभाग ने बुधवार को नौ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर आरेंज अलर्ट जारी किया है। इन जिलों में फ्लैश फ्लड की आशंका जताई गई है।

त्यूणी में बड़ा हादसा टोंस नदी में बहा बाइक सवार युवक

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून के त्यूणी क्षेत्र में सोमवार शाम बड़ा हादसा हो गया। आराकोट-नया बाजार मार्ग पर बाइक सवार दो लोगों में से एक युवक संतुलन बिगड़ने के कारण टोंस नदी में जा गिरा और लापता हो गया। हादसे के बाद एसडीआरएफ और पुलिस की संयुक्त टीम ने नदी में सर्च ऑपरेशन शुरू कर दिया है। लापता युवक हिमाचल प्रदेश का निवासी बताया जा रहा है।

कांवड़ मार्ग पर खाद्य सुरक्षा अभियान, लंगरों से लिए गए 15 सैंपल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। कांवड़ यात्रा के दृष्टिगत खाद्य सुरक्षा विभाग ने यात्रा मार्ग पर संचालित लंगर-भंडारों का आकस्मिक निरीक्षण का अभियान चलाया। अभियान का उद्देश्य श्रद्धालुओं को स्वच्छ, सुरक्षित और गुणवत्तापूर्ण भोजन उपलब्ध कराना और खाद्य सुरक्षा मानकों का प्रभावी अनुपालन सुनिश्चित करना है। निरीक्षण के दौरान जनपद के गंगोत्री यात्रा मार्ग पर ताछला में लंगर शिवशक्ति सेवा टूरिस्ट, स्वरूपनगर (दिल्ली) द्वारा फकोट में संचालित लंगर भंडारों का खाद्य सुरक्षा व मानक अधिनियम के प्रावधानों के तहत निरीक्षण व नमूना संग्रहण किया गया।

ऋषिकेश में हरियाली अभियान तेज

विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस पर डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने बांटे पौधे

भारतेंदु संवाददाता, ऋषिकेश। विश्व प्रकृति संरक्षण दिवस के अवसर पर ऋषिकेश में पर्यावरण संरक्षण को लेकर विशेष कार्यक्रम आयोजित किया गया। ऋषिकेश विधायक एवं पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने अपने कैंप कार्यालय में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के प्रेरणादायी अभियान एक पेड़ मां के नाम को आगे बढ़ाते हुए विभिन्न सामाजिक और महिला संगठनों से जुड़ी पदाधिकारियों को पौधों का वितरण किया। इस दौरान उन्होंने लोगों से अधिक से अधिक पौधारोपण करने और पर्यावरण संरक्षण में अपनी भागीदारी निभाने का आह्वान किया।

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने कहा कि प्रकृति का संरक्षण प्रत्येक व्यक्ति की जिम्मेदारी है। वर्तमान समय में बढ़ते प्रदूषण, जलवायु परिवर्तन और पर्यावरणीय संकट को देखते हुए पेड़-पौधे लगाना बेहद जरूरी हो गया है। उन्होंने कहा कि केवल पौधा लगाना ही पर्याप्त नहीं है, बल्कि उसकी नियमित देखभाल करना भी आवश्यक है। यदि प्रत्येक व्यक्ति अपने जीवन में एक पौधा लगाकर उसका संरक्षण करे तो आने वाली पीढ़ियों को बेहतर और सुरक्षित पर्यावरण मिल सकता है।

वृक्षारोपण से ही सुरक्षित होगा भविष्य: डॉ. अग्रवाल

डॉ. प्रेमचंद अग्रवाल ने क्या कहा

- **पौधारोपण** तभी सफल होगा, जब लगाए गए पौधों का संरक्षण भी किया जाए। आने वाली पीढ़ियों को सुरक्षित और स्वच्छ वातावरण उपलब्ध कराना हम सभी का नैतिक दायित्व है।

कई सामाजिक कार्यकर्ता रहे मौजूद

उन्होंने कार्यक्रम में मौजूद महिलाओं की भूमिका की सराहना करते हुए कहा कि महिलाएं समाज में जागरूकता फैलाने की महत्वपूर्ण कड़ी हैं। यदि महिलाएं पर्यावरण संरक्षण का संकल्प लेंगी तो यह अभियान घर-घर तक पहुंच सकता है। उन्होंने सभी महिला पदाधिकारियों से अपने क्षेत्रों में पौधारोपण अभियान चलाने और लोगों को इसके लिए प्रेरित करने की अपील की। कार्यक्रम में उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता जताई और पौधों की देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम में श्यामपुर मंडल अध्यक्ष चंद्र मोहन पोखरियाल, भाजपा कार्यकर्ता सुमित सेठी सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और महिला पदाधिकारी मौजूद रहे। सभी उपस्थित लोगों ने पर्यावरण संरक्षण के प्रति अपनी प्रतिबद्धता व्यक्त करते हुए पौधे लगाने और उनकी नियमित देखभाल करने का संकल्प लिया। कार्यक्रम का उद्देश्य समाज में पर्यावरण के प्रति जागरूकता बढ़ाना और हरित उत्तराखंड के निर्माण की दिशा में सकारात्मक प्रयासों को गति देना रहा।

नीलकंठ कांवड़ मेले के चलते 18 स्कूलों में अवकाश घोषित

- कांवड़ यात्रा मार्ग पर स्थित 18 शिक्षण संस्थान रहेंगे बंद
- सुरक्षा व्यवस्था को देखते हुए जिलाधिकारी ने घोषित किया अवकाश

भारतेंदु संवाददाता, पौड़ी गढ़वाल। नीलकंठ महादेव कांवड़ मेला-2026 के दौरान श्रद्धालुओं की भारी भीड़ को देखते हुए जिला प्रशासन ने छात्र-छात्राओं की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए बड़ा निर्णय लिया है। जिलाधिकारी स्वाति एस. भदौरिया ने नीलकंठ यात्रा मार्ग और आसपास स्थित 18 शिक्षण संस्थानों में निर्धारित अवधि के लिए अवकाश घोषित कर दिया है। इस निर्णय का उद्देश्य विद्यार्थियों को संभावित दुर्घटनाओं और यातायात अव्यवस्था से सुरक्षित रखना है।

जिलाधिकारी ने कहा कि कांवड़ मेले के दौरान नीलकंठ मार्ग पर लाखों श्रद्धालुओं की आवाजाही रहती है, जिससे यातायात पर अत्यधिक दबाव पड़ता है। ऐसे में विद्यार्थियों के सुरक्षित आवागमन को सुनिश्चित करने और यात्रा व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए संबंधित विद्यालयों में अवकाश घोषित किया गया है। उन्होंने सभी विभागों और विद्यालय प्रबंधन को आदेश का कड़ाई से पालन कराने के निर्देश दिए हैं।

प्रशासन के आदेश के अनुसार नीलकंठ और दिउली क्षेत्र के चार विद्यालयों में 30 जुलाई से 11 अगस्त तक अवकाश रहेगा। वहीं लक्ष्मणझूला, स्वर्गाश्रम, घट्टूगाड़, गंगाभोगपुर और नीलकंठ क्षेत्र के 14 अन्य शिक्षण संस्थानों में 5 अगस्त से 11 अगस्त तक छुट्टियां रहेंगी। जिला प्रशासन का मानना है कि इस निर्णय से एक ओर छात्रों की सुरक्षा सुनिश्चित होगी तो दूसरी ओर कांवड़ यात्रा के दौरान यातायात प्रबंधन भी अधिक प्रभावी ढंग से किया जा सकेगा।

डिग्री नहीं सक्षम युवा तैयार करें विश्वविद्यालय: राज्यपाल

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून में राज्यपाल एवं कुलाधिपति लेफ्टिनेंट जनरल गुरमीत सिंह (सेवानिवृत्त) ने प्रदेश के राजकीय विश्वविद्यालयों के कुलपतियों के साथ समीक्षा बैठक की। बैठक में विश्वविद्यालयों की उपलब्धियों, चुनौतियों, शोध कार्यों, नवाचार और रिक्त पदों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। राज्यपाल ने कहा कि विश्वविद्यालयों का उद्देश्य केवल विद्यार्थियों को डिग्री प्रदान करना नहीं, बल्कि उन्हें सक्षम, आत्मविश्वासी और राष्ट्र निर्माण में योगदान देने योग्य बनाना होना चाहिए।

राज्यपाल ने विश्वविद्यालयों की शिक्षा व्यवस्था की समीक्षा की

राज्यपाल ने कुलपतियों से अपेक्षा की कि वे नई शिक्षा नीति और आधुनिक तकनीक के अनुरूप विश्वविद्यालयों को विकसित करें, ताकि युवा रोजगार, उद्यमिता और भविष्य की चुनौतियों का सामना करने के लिए तैयार हो सकें।

'नशा मुक्त भारत' अभियान पर हल्द्वानी में भव्य जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन

भारतेंदु संवाददाता, हल्द्वानी। हल्द्वानी के कालाढूंगी में केंद्रीय संचार ब्यूरो, क्षेत्रीय कार्यालय नैनीताल द्वारा विकसित भारत 2047 और नशा मुक्त भारत अभियान पर विशेष जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किया गया। कार्यक्रम में चित्र प्रदर्शनी, नुक्कड़ नाटक और सांस्कृतिक प्रस्तुतियों के माध्यम से लोगों को सरकारी योजनाओं तथा सामाजिक सरोकारों की जानकारी दी गई। विधायक बंशीधर भगत ने रोजगार और आजीविका गारंटी मिशन जी राम जी को ग्रामीण विकास और रोजगार के क्षेत्र में महत्वपूर्ण पहल बताया। दर्जा राज्य मंत्री शांति मेहरा ने चित्र प्रदर्शनी का उद्घाटन किया। कार्यक्रम में नशे के दुष्प्रभावों से बचने और स्वस्थ समाज निर्माण का संदेश दिया गया।

टौंस नदी पुल के एप्रोच मार्ग धंसने पर सतपाल महाराज सक्रिय

- एप्रोच मार्ग धंसने पर लोनिवि मंत्री सतपाल महाराज ने मांगी रिपोर्ट

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। देहरादून-पांवटा साहिब पुराने राजमार्ग पर प्रेमनगर स्थित नंदा की चौकी के पास टौंस नदी पर बने नए पुल के एप्रोच मार्ग के आंशिक रूप से धंसने का लोक निर्माण मंत्री सतपाल महाराज ने संज्ञान लिया है। उन्होंने विभागीय अधिकारियों को तुरंत मरम्मत कार्य शुरू करने और मार्ग को जल्द सुचारु करने के निर्देश दिए हैं।

लोक निर्माण मंत्री ने बताया कि पुल का मुख्य ढांचा और स्ट्रक्चर पूरी तरह सुरक्षित है। भारी बारिश के कारण रिटर्न वाल के पास किए गए मिट्टी भरान वाले हिस्से में पानी जाने से अंदर खाली स्थान बन गया, जिससे एप्रोच रोड में धंसाव की स्थिति पैदा हुई। विभाग ने मौके पर पहुंचकर सुधार कार्य शुरू कर दिया है।

उत्तराखंड में बढ़ रहे कैंसर के मरीज 12,600 के पार पहुंची रोगियों की संख्या

- कैंसर की चपेट में उत्तराखंड पांच साल में 7.3 प्रतिशत बढ़े मामले

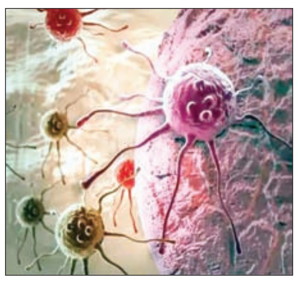

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में कैंसर के बढ़ते मामलों ने स्वास्थ्य क्षेत्र के सामने एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है। भारतीय आयुर्विज्ञान अनुसंधान परिषद (आईसीएमआर) के नेशनल कैंसर रजिस्ट्री प्रोग्राम के अनुसार राज्य में कैंसर मरीजों की संख्या बढ़कर 12,642 तक पहुंच गई है। पिछले पांच वर्षों में कैंसर के मामलों में करीब 7.3 प्रतिशत की वृद्धि दर्ज की गई है। वर्ष 2021 में राज्य में कैंसर मरीजों की संख्या 11,779 थी, जो अब बढ़कर 12 हजार से अधिक हो चुकी है। विशेषज्ञों के अनुसार कैंसर के बढ़ते मामलों के पीछे कई कारण जिम्मेदार हैं। बदलती जीवनशैली, तंबाकू और नशे का सेवन, असंतुलित खानपान, पर्यावरणीय प्रभाव और बढ़ती उम्र को प्रमुख कारण माना जा रहा है। आधुनिक जीवनशैली में शारीरिक गतिविधियों की कमी और तनाव भी स्वास्थ्य पर प्रतिकूल प्रभाव डाल रहे हैं। ग्रामीण और पर्वतीय क्षेत्रों में समय पर जांच और उपचार की सुविधा का अभाव भी बीमारी के गंभीर रूप लेने की एक बड़ी वजह बन सकता है।

पिथौरागढ़ में बारिश का कहर नंदा देवी बेस कैंप मार्ग बंद

भारतेंदु संवाददाता, पिथौरागढ़। पिथौरागढ़ जिले में पिछले 24 घंटे से जारी भारी वर्षा ने सीमांत इलाकों में मुश्किलें बढ़ा दी हैं। तेज बारिश के कारण चीन सीमा को जोड़ने वाले मार्गों पर यातायात प्रभावित हुआ है। नंदा देवी बेस कैंप ट्रैकिंग मार्ग पर ल्वा गांव के निकट एक पुलिया बह जाने से बेस कैंप और आसपास के क्षेत्रों का संपर्क कट गया है। वहीं तवाघाट-लिपुलेख मार्ग, मुनस्यारी-मिलम मार्ग, थल-मुनस्यारी सहित जिले की 22 प्रमुख सड़कें बंद हो गई हैं। भारी बारिश के चलते काली नदी, गोरी गंगा, धौली गंगा और अन्य नदी-नाले उफान पर हैं, जिससे प्रशासन ने लोगों से सतर्क रहने की अपील की है।

जिले के कई क्षेत्रों में लगातार बारिश से भूस्खलन और सड़क अवरोध की स्थिति बनी हुई है। प्रशासन और आपदा प्रबंधन विभाग की टीमें बंद मार्गों को खोलने में जुटी हैं। सीमांत क्षेत्रों में आवश्यक सेवाएं प्रभावित न हों इसके लिए निगरानी बढ़ा दी गई है। मौसम विभाग ने आने वाले दिनों में भी बारिश की संभावना जताई है।

उत्तराखंड में बारिश का कहर, कई जिलों में स्कूल बंद और हाईवे बाधित

- देहरादून-पिथौरागढ़ में 12वीं तक के स्कूल बंद

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में मानसून ने अपना रौद्र रूप दिखाना शुरू कर दिया है। प्रदेश के पहाड़ी और मैदानी क्षेत्रों में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण जनजीवन अस्त-व्यस्त हो गया है। देहरादून और पिथौरागढ़ समेत कई जिलों में मौसम की स्थिति को देखते हुए प्रशासन ने कक्षा एक से 12वीं तक के सभी स्कूलों और आंगनबाड़ी केंद्रों को बंद रखने का निर्णय लिया है। बच्चों की सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए यह कदम उठाया गया है। भारी बारिश के कारण कई स्थानों पर जलभराव और भूस्खलन की स्थिति बनी हुई है। मसूरी क्षेत्र में भूस्खलन से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ा, जबकि बद्रीनाथ हाईवे पर मलबा आने से यातायात प्रभावित हुआ। पहाड़ी क्षेत्रों में लगातार पत्थर गिरने और सड़कें अवरुद्ध होने की घटनाएं सामने आ रही हैं। इससे यात्रियों और स्थानीय लोगों की मुश्किलें बढ़ गई हैं। मौसम विभाग ने प्रदेश के नौ जिलों में भारी से बहुत भारी वर्षा को लेकर ऑरेंज अलर्ट जारी किया है। विभाग ने कई क्षेत्रों में अचानक बाढ़ और भूस्खलन की आशंका जताई है।

रुद्रप्रयाग में अपराध समीक्षा बैठक आयोजित एसपी ने त्वरित कार्रवाई के दिए निर्देश

- लंबित मामलों के जल्द निस्तारण और अपराध रोकथाम पर एसपी का रहा फोकस

भारतेंदु संवाददाता, रुद्रप्रयाग। रुद्रप्रयाग पुलिस कार्यालय सभागार में पुलिस अधीक्षक नीहारिका तोमर की अध्यक्षता में मासिक अपराध समीक्षा गोष्ठी आयोजित की गई। बैठक में जिला अभियोजन निदेशालय, सभी कोतवाली और शाखा प्रभारी सहित विवेचकों ने भाग लिया। इस दौरान जिले की कानून व्यवस्था, लंबित मामलों के निस्तारण, डिजिटल पुलिसिंग, आपदा प्रबंधन और आगामी कांवड़ मेले की तैयारियों को लेकर विस्तृत चर्चा की गई।

पुलिस अधीक्षक ने 60 और 90 दिनों से अधिक समय से लंबित मामलों तथा अधूरी विवेचनाओं का प्राथमिकता के आधार पर निस्तारण करने के निर्देश दिए। उन्होंने डिजिटल प्रणालियों जैसे ई-साक्ष्य, सीसीटीएनएस, ई-सम्मन और अन्य पोर्टलों के प्रभावी उपयोग पर जोर दिया। साथ ही शिकायतों का समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण समाधान सुनिश्चित करने को कहा।

भारी बारिश और भूस्खलन की संभावनाओं को देखते हुए सभी थाना प्रभारियों को हाई अलर्ट पर रहने के निर्देश दिए गए। आपदा राहत उपकरणों को तैयार रखने और एसडीआरएफ, फायर सर्विस तथा आपदा प्रबंधन विभाग के साथ बेहतर समन्वय बनाने पर जोर दिया गया।

5 से 30 सितंबर तक चलेगी नंदा देवी बड़ी जात यात्रा

ऐतिहासिक नंदा देवी यात्रा की तैयारियां शुरू, समिति जुटी आयोजन में

भारतेंदु संवाददाता, गोपेश्वर (चमोली)। उत्तराखंड की लोक आस्था और सांस्कृतिक परंपरा का प्रतीक मानी जाने वाली मां नंदा देवी बड़ी जात यात्रा की तैयारियां तेज हो गई हैं। पांच सितंबर से 30 सितंबर तक आयोजित होने वाली इस ऐतिहासिक यात्रा के सफल आयोजन के लिए यात्रा समिति ने तैयारियां शुरू कर दी हैं। इसी क्रम में यात्रा समिति के पदाधिकारी बदरीनाथ धाम पहुंचे और भगवान बदरी विशाल के दर्शन कर यात्रा के सफल और निर्विघ्न आयोजन की कामना की।

यात्रा समिति के अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) हरेंद्र सिंह रावत और उपाध्यक्ष सुखबीर रौतेला ने बदरीनाथ मंदिर में दर्शन के बाद मंदिर के रावल अमरनाथ नंबूदरी, बदरीनाथ-केदारनाथ मंदिर समिति के पदाधिकारियों और सीमांत गांव बामणी तथा माणा के प्रतिनिधियों से मुलाकात की। इस दौरान उन्हें नंदा देवी बड़ी जात यात्रा में शामिल होने के लिए औपचारिक निमंत्रण दिया गया।

आयोजन को सफल बनाने के लिए विभिन्न स्तरों पर तैयारियां की जा रही हैं। श्रद्धालुओं की सुविधा, यात्रा मार्ग की व्यवस्था, धार्मिक कार्यक्रमों के संचालन और स्थानीय लोगों की भागीदारी को लेकर योजना बनाई जा रही है। सीमांत क्षेत्रों के गांवों को भी यात्रा से जोड़ने के प्रयास किए जा रहे हैं। नंदा देवी बड़ी जात केवल धार्मिक यात्रा नहीं बल्कि उत्तराखंड की लोक संस्कृति, परंपरा और सामाजिक एकता का प्रतीक भी है।

-यात्रा समिति अध्यक्ष कर्नल (सेवानिवृत्त) हरेंद्र सिंह रावत

हरिद्वार अखाड़ा परिषद में वर्चस्व की जंग तेज

हरिद्वार अखाड़ा विवाद गहराया, श्रीमहंत रविंद्र पुरी ने लगाए गंभीर आरोप

भारतेंदु संवाददाता, हरिद्वार। हरिद्वार में अखाड़ा परिषद से जुड़े संत समाज के बीच चल रही खींचतान अब गंभीर आरोपों तक पहुंच गई है। अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के निरंजनी गुट के अध्यक्ष और मां मनसा देवी मंदिर ट्रस्ट के अध्यक्ष श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने महानिर्वाणी गुट के अध्यक्ष श्रीमहंत रविंद्र पुरी पर अपनी हत्या की साजिश रचने का आरोप लगाया है। इस आरोप के बाद संत समाज और अखाड़ों के बीच चल रहा विवाद और अधिक गहरा गया है।

श्रीमहंत डॉ. रविंद्र पुरी ने पत्रकार वार्ता कर कहा कि इंटरनेट मीडिया पर एक पोस्ट का स्क्रीन शॉट प्रसारित हुआ है, जिसमें उनके खिलाफ आपत्तिजनक बातें लिखी गई हैं और धमकी देने का प्रयास किया गया है। उन्होंने आरोप लगाया कि इस पूरे मामले के पीछे महानिर्वाणी गुट के अध्यक्ष का हाथ हो सकता है। हालांकि आरोपों की आधिकारिक पुष्टि जांच के बाद ही हो सकेगी।

अखाड़ा परिषद देश के प्रमुख धार्मिक संगठनों में शामिल है और कुंभ जैसे बड़े धार्मिक आयोजनों में इसकी महत्वपूर्ण भूमिका रहती है। ऐसे में अखाड़ों के प्रमुख संतों के बीच विवाद का असर संत समाज की छवि और आपसी समन्वय पर भी पड़ सकता है।

उन्होंने कहा कि वह किसी भी तरह की धमकी से डरने वाले नहीं हैं और संत समाज की गरिमा तथा अपने दायित्वों का निर्वहन करते रहेंगे। इस मामले के सामने आने के बाद अखाड़ा परिषद के भीतर चल रही वर्चस्व की लड़ाई एक बार फिर चर्चा में आ गई है।

आपदा | 233 मिलीमीटर बारिश से देहरादून में हालात बिगड़े, कई क्षेत्रों में सड़कें क्षतिग्रस्त

उत्तराखंड में दो दिन के लिए रोकी गई चारधाम यात्रा

- भूस्खलन ने बढ़ाई मुश्किलें, 28 और 29 जुलाई को चारधाम यात्रा पर लगा विराम

भारतेंदु संवाददाता, देहरादून। उत्तराखंड में लगातार हो रही मूसलाधार बारिश ने जनजीवन को बुरी तरह प्रभावित किया है। पहाड़ी क्षेत्रों में भारी वर्षा के कारण कई स्थानों पर भू-स्खलन की घटनाएं सामने आई हैं, जिससे सड़क मार्गों पर आवाजाही प्रभावित हुई है। श्रद्धालुओं की सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए प्रशासन ने 28 और 29 जुलाई को चारधाम यात्रा को स्थगित करने का निर्णय लिया है। गढ़वाल आयुक्त आनंद स्वरूप ने बताया कि चारधाम यात्रा मार्गों पर कई जगह भूस्खलन हुआ है और मौसम विभाग ने भारी बारिश की चेतावनी जारी की है। ऐसे में यात्रियों की सुरक्षा सर्वोच्च प्राथमिकता है। मौसम साफ होने और मार्गों के सुरक्षित होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू की जाएगी। मौसम विज्ञान केंद्र देहरादून ने राज्य के कई जिलों में भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है।

अचानक बारिश का अलर्ट जारी

उत्तरकाशी, देहरादून, टिहरी, रुद्रप्रयाग, चमोली, पौड़ी, हरिद्वार, नैनीताल, बागेश्वर और पिथौरागढ़ में तेज बारिश, आकाशीय बिजली और अचानक वर्षा का अलर्ट जारी किया गया है।

233 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई

प्रशासन ने लोगों से अपील की है कि वे केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करें और खराब मौसम में अनावश्यक यात्रा से बचें। पिछले 24 घंटों में देहरादून जिले के मालदेवता क्षेत्र में सबसे अधिक 233 मिलीमीटर बारिश दर्ज की गई।

बढ़ती जलभराव की समस्या

इसके अलावा हाथीबड़कला, जौलीग्रांट और मसूरी सहित कई क्षेत्रों में भारी वर्षा हुई है। लगातार बारिश के कारण नदियों और गदेरों के जलस्तर में वृद्धि, सड़क मार्गों के अवरुद्ध होने और निचले इलाकों में जलभराव की आशंका बनी हुई है।

1.81 करोड़ के गबन मामले में हाई कोर्ट सख्त

सीबीआई जांच की मांग वाली याचिका पर सुनवाई, विजिलेंस ब्यूरो को विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने ग्रामीण विकास एवं पंचायत विभाग से जुड़े कथित भ्रष्टाचार मामले में पंजाब विजिलेंस ब्यूरो से विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट तलब की है। यह मामला दिसंबर 2024 में फिरोजपुर में दर्ज एफआईआर से संबंधित है। कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश की खंडपीठ ने यह आदेश गांव मंडौली, जिला पटियाला के पूर्व सरपंच इकबाल सिंह द्वारा दायर जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान दिया।

याचिका में मांग की गई है कि मामले की आगे की जांच पंजाब विजिलेंस ब्यूरो के बजाय केंद्रीय जांच ब्यूरो (सीबीआई) को सौंपी जाए। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले के मुख्य आरोपित अरुण शर्मा का नाम एफआईआर दर्ज होने के लगभग 18 महीने बाद शामिल किया गया। उनका आरोप है कि भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत अभियोजन स्वीकृति मिलने के बाद ही उन्हें आरोपित बनाया गया।

याचिकाकर्ता के अधिवक्ता ने अदालत को बताया कि अरुण शर्मा ने अपने प्रभाव का इस्तेमाल कर जांच को प्रभावित करने का प्रयास किया। साथ ही आरोप लगाया गया कि उन्होंने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश की अदालत में यह गलत जानकारी दी कि उनके खिलाफ धारा 17-ए के तहत कोई स्वीकृति नहीं दी गई है, जबकि बाद में उन्हें आरोपित बनाया गया।

याचिका के अनुसार अरुण शर्मा ने अपनी अधीनस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर जसप्रीत कौर के साथ कथित मिलीभगत कर लगभग 1.81 करोड़ रुपये के सरकारी धन का गबन किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि निष्पक्ष जांच सुनिश्चित करने और वास्तविक दोषियों तक पहुंचने के लिए मामले की जांच सीबीआई को सौंपी जानी चाहिए।

सुनवाई के दौरान हाई कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को मामले की जांच की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत अगली सुनवाई में रिपोर्ट और याचिका में लगाए गए आरोपों पर विचार करेगी।

गलत बयान देने का आरोप

यह भी आरोप लगाया कि अरुण शर्मा ने अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश, फिरोजपुर की अदालत से अंतरिम राहत प्राप्त करने के लिए यह गलत बयान दिया कि उनके खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की धारा 17-ए के तहत कोई स्वीकृति नहीं दी गई है।

> याचिकाकर्ता की ओर से अदालत को यह भी बताया गया कि जब तक एफआईआर की आगे की जांच सीबीआई को नहीं सौंपी जाती, तब तक वास्तविक दोषियों को कानून के कठघरे तक नहीं लाया जा सकेगा।

वर्तमान स्थिति जानने के लिए मांगी रिपोर्ट

याचिका में आरोप लगाया गया है कि तत्कालीन अधिकारी अरुण शर्मा ने अपनी अधीनस्थ डाटा एंट्री ऑपरेटर जसप्रीत कौर के साथ कथित मिलीभगत कर लगभग 1.81 करोड़ रुपये के सरकारी धन का गबन किया। याचिकाकर्ता का कहना है कि मामले की निष्पक्ष जांच के लिए इसे सीबीआई को सौंपा जाना आवश्यक है। सुनवाई के दौरान पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने पंजाब विजिलेंस ब्यूरो को जांच की वर्तमान स्थिति पर विस्तृत स्टेटस रिपोर्ट दाखिल करने का निर्देश दिया। अदालत ने स्पष्ट किया कि अगली सुनवाई में इस रिपोर्ट और याचिकाकर्ता द्वारा लगाए गए आरोपों पर विस्तार से विचार किया जाएगा। अदालत ने विजिलेंस ब्यूरो से यह भी अपेक्षा की है कि जांच में अब तक की गई कार्रवाई, एकत्र किए गए साक्ष्यों और आगे की प्रस्तावित जांच का पूरा विवरण रिपोर्ट में प्रस्तुत किया जाए। इस मामले की अगली सुनवाई में रिपोर्ट के आधार पर आगे की न्यायिक प्रक्रिया तय की जाएगी।

पंजाब के सरकारी अस्पतालों में जल्द मिलेंगी आधुनिक जांच सुविधाएं

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब सरकार राज्य की स्वास्थ्य सेवाओं को और अधिक सुदृढ़ बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाने जा रही है। जल्द ही राज्य के सभी 23 जिला अस्पतालों तथा चयनित उपमंडल अस्पतालों में एमआरआई, सीटी स्कैन और अन्य आधुनिक जांच सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएंगी। इस पहल का उद्देश्य मरीजों को उनके जिले में ही गुणवत्तापूर्ण जांच सुविधा उपलब्ध कराना है, ताकि उन्हें महंगे निजी जांच केंद्रों का सहारा न लेना पड़े और समय पर इलाज शुरू हो सके।

वर्तमान समय में अधिकांश सरकारी अस्पतालों में एमआरआई और सीटी स्कैन जैसी उन्नत जांच सुविधाएं उपलब्ध नहीं हैं। इसके कारण मरीजों को निजी अस्पतालों और जांच केंद्रों में जाना पड़ता है, जहां जांच पर हजारों रुपये खर्च करने पड़ते हैं। आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों के लिए यह अतिरिक्त खर्च बड़ा बोझ बन जाता है। कई मरीज पैसों की कमी के कारण समय पर जांच नहीं करा पाते, जिससे बीमारी का पता देर से चलता है और उपचार में भी देरी हो जाती है।

स्वास्थ्य विभाग के अनुसार नई व्यवस्था सार्वजनिक-निजी भागीदारी मॉडल के तहत लागू की जाएगी। इसके अंतर्गत निजी संस्थाएं सरकारी अस्पतालों में आधुनिक मशीनें स्थापित करेंगी और उनका संचालन भी करेंगी। मरीजों को सरकार द्वारा निर्धारित रियायती दरों पर जांच की सुविधा मिलेगी। इससे सरकार को एकमुश्त भारी निवेश नहीं करना पड़ेगा, जबकि लोगों को बेहतर और आधुनिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध हो सकेंगी।

जिला अस्पतालों में जल्द शुरू होंगी एमआरआई और सीटी स्कैन सुविधाएं

स्वास्थ्य मंत्री डॉ. बलबीर सिंह ने बताया कि कई जिला अस्पतालों में मशीनें लगाने का कार्य शुरू हो चुका है। कुछ उपमंडल अस्पतालों को भी इस योजना में शामिल किया गया है। उन्होंने कहा कि राष्ट्रीय और राज्य राजमार्गों के निकट स्थित अस्पतालों में यह सुविधा उपलब्ध होने से सड़क दुर्घटनाओं में घायल मरीजों की तत्काल जांच संभव होगी। इससे गंभीर घायलों का उपचार बिना देरी शुरू किया जा सकेगा और कई लोगों की जान बचाने में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य विभाग का कहना है कि राज्य में रेडियोलॉजी विशेषज्ञ चिकित्सकों की कमी लंबे समय से बनी हुई है। सरकारी अस्पतालों में विशेषज्ञों के अनेक पद खाली हैं, जिससे आधुनिक जांच सेवाओं के विस्तार में कठिनाई आती है। इसी चुनौती को ध्यान में रखते हुए निजी भागीदारी का मॉडल अपनाया जा रहा है, ताकि विशेषज्ञ सेवाओं की कमी के बावजूद मरीजों को बेहतर सुविधा मिल सके।

न्यूज ब्रीफ

व्यापारियों की समस्याओं पर प्रशासन सख्त जल्द समाधान के दिए निर्देश

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। जिला प्रशासन ने व्यापारियों की समस्याओं के जल्द समाधान के लिए कदम उठाए हैं। जिला ट्रेडर्स कमीशन के अध्यक्ष रणजीत पाल सिंह और अतिरिक्त उपायुक्त अंकिता कांसल की अध्यक्षता में हुई बैठक में व्यापारियों ने सीवरेज, सफाई, खराब सड़कों, पार्किंग और बाजारों में चोरी जैसी समस्याएं उठाईं। व्यापारियों ने चोरी रोकने के लिए पुलिस गश्त बढ़ाने की मांग की। अतिरिक्त उपायुक्त ने संबंधित विभागों को शिकायतों का प्राथमिकता के आधार पर समाधान करने और आपसी तालमेल से काम करने के निर्देश दिए। रणजीत पाल सिंह ने कहा कि व्यापारियों की सभी समस्याओं को गंभीरता से सुना गया है और समाधान के लिए विभागों से लगातार संपर्क किया जा रहा है।

सफाई कर्मियों की हड़ताल से जीरकपुर में गहराया कूड़ा संकट

भारतेन्दु संवाददाता, जीरकपुर। लंबित मांगों और बरनाला लाठीचार्ज के विरोध में जीरकपुर के सफाई कर्मी अनिश्चितकालीन हड़ताल पर चले गए हैं। हड़ताल के कारण शहर की सफाई व्यवस्था पूरी तरह प्रभावित हो गई है। लोहगढ़, पभात, बलटाना और पीर मुछल्ला सहित कई क्षेत्रों में कूड़े के ढेर लग गए हैं। स्थानीय लोगों का कहना है कि कई दिनों से कूड़ा नहीं उठाया गया, जिससे दुर्गंध फैल रही है। बरसात के मौसम में सड़ते कूड़े से मच्छर और मक्खियों की संख्या बढ़ने का खतरा है, जिससे डेंगू, मलेरिया और अन्य बीमारियों की आशंका बढ़ गई है। लोगों ने प्रशासन से जल्द समाधान की मांग की है।

विदेश भेजने के नाम पर लाखों की ठगी, एजेंटों पर केस

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। विदेश भेजने का झांसा देकर लोगों से करोड़ों रुपये की ठगी के मामले सामने आए हैं। मोहाली पुलिस ने 11 इमिग्रेशन एजेंटों के खिलाफ पांच अलग-अलग मामले दर्ज किए हैं। आरोप है कि एजेंटों ने यूके, अमेरिका, कनाडा, ऑस्ट्रेलिया और अजरबैजान का वीजा दिलाने का भरोसा देकर लाखों रुपये लिए, लेकिन न तो वीजा दिलाया और न ही रकम वापस की। पीड़ितों में गुरप्रीत सिंह, कश्मीरी राम, दविंदर सिंह, सुमेश ढाका और मसरूफ शामिल हैं। इनसे करीब 91 लाख रुपये से अधिक की ठगी का आरोप है। पुलिस अधीक्षक दिलप्रीत सिंह ने बताया कि मामलों की जांच जारी है। उन्होंने लोगों से एजेंटों के लाइसेंस और दस्तावेज जांचने की अपील की है।

कुराली में एटीएम तोड़ने पहुंचे चोर, कैमरे लेकर फरार

भारतेन्दु संवाददाता, कुराली। कुराली शहर में तीन चोरों ने पंजाब नेशनल बैंक के एटीएम को तोड़ने की कोशिश की, लेकिन वे नकदी निकालने में सफल नहीं हो सके। घटना के बाद चोर वहां लगे सीसीटीवी कैमरे चोरी कर फरार हो गए। बैंक मैनेजर सिमरप्रीत कौर ने पुलिस को शिकायत देकर कार्रवाई की मांग की है। जानकारी के अनुसार सोमवार सुबह जब बैंक कर्मचारी एटीएम खोलने पहुंचे तो बाहर लगे ताले टूटे हुए मिले। जांच में सामने आया कि तड़के करीब दो बजे तीन युवक स्कूटी पर सवार होकर पहुंचे थे। सीसीटीवी फुटेज में वे एटीएम तोड़ने का प्रयास करते दिखाई दिए। इसी दौरान एक कार वहां पहुंची, जिसे देखकर चोर घबरा गए और मौके से फरार हो गए। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और चोरों की पहचान के लिए प्रयास किए जा रहे हैं। बैंक प्रबंधन ने आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने की मांग की है।

शादी का झांसा देकर संबंध बनाने पर युवक पर केस

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। मोहाली पुलिस ने अमृतसर निवासी हरमनप्रीत सिंह के खिलाफ शादी का झांसा देकर युवती से संबंध बनाने और बाद में शादी से इन्कार करने के आरोप में मामला दर्ज किया है। पुलिस ने भारतीय न्याय संहिता की धारा 69 के तहत कार्रवाई की है। जानकारी के अनुसार करीब 25 वर्षीय युवती ने जून 2026 में जिला पुलिस प्रमुख को शिकायत दी थी। युवती ने आरोप लगाया कि उसकी मुलाकात हरमनप्रीत सिंह से हुई थी, जिसके बाद दोनों के बीच दोस्ती प्रेम संबंध में बदल गई। आरोप है कि युवक ने शादी का वादा कर उसके साथ शारीरिक संबंध बनाए। युवती के गर्भवती होने के बाद हरमनप्रीत ने शादी करने और बच्चे को अपनाने से इन्कार कर दिया। महिला सेल द्वारा की गई जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद पुलिस ने मामला दर्ज किया। पुलिस ने बताया कि मामले की जांच जारी है और आगे की कार्रवाई जांच के आधार पर की जाएगी।

हाई कोर्ट ने कर्मचारियों को पेंशन लाभ पर दी राहत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने लंबे समय तक पार्ट-टाइम, अस्थायी और ठेके के आधार पर सेवाएं देने वाले कर्मचारियों के पक्ष में महत्वपूर्ण फैसला सुनाया है। अदालत ने स्पष्ट किया है कि नियमित होने से पहले की गई उनकी सेवा अवधि को भी पेंशन के लिए योग्य सेवा माना जाएगा। जस्टिस हरप्रीत सिंह बराड़ ने 95 याचिकाओं का एक साथ निपटारा करते हुए यह फैसला दिया। अदालत ने कहा कि यदि किसी कर्मचारी की पहले की सेवा अवधि जोड़ने के बाद वह ओल्ड पेंशन स्कीम (ओपीएस) के दायरे में आता है, तो उसे केवल इस आधार पर लाभ से वंचित नहीं किया जा सकता कि उसका नियमितीकरण नई पेंशन योजना (एनपीएस) लागू होने के बाद हुआ है। इस फैसले से उन कर्मचारियों को बड़ी राहत मिलेगी, जिन्होंने नियमित होने से पहले कई वर्षों तक अस्थायी या अन्य आधारों पर लगातार सेवाएं दी हैं। हाई कोर्ट के आदेश से पेंशन लाभ को लेकर चल रहे कई विवादों पर स्थिति स्पष्ट हो गई है।

अनिल विज ने मोदी सरकार की जमकर की सराहना

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के ऊर्जा, परिवहन और श्रम मंत्री अनिल विज ने कहा कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जनता की भावनाओं को समझते हैं। राम मंदिर आंदोलन का जिक्र करते हुए उन्होंने कहा कि उन्होंने कई आंदोलनों में लाठियां खाईं, लेकिन पहले की सरकारें मांगों पर ध्यान नहीं देती थीं। पेपर लीक मामले पर विज ने विपक्ष पर निशाना साधते हुए कहा कि विपक्ष मुद्दों को भड़काने का काम करता है, जबकि सरकार ने तुरंत कार्रवाई करते हुए एसआईटी गठित की और आरोपियों को गिरफ्तार किया। वन नेशन-वन इलेक्शन पर उन्होंने कहा कि इससे चुनावी खर्च घटेगा और विकास कार्यों में तेजी आएगी।विज ने कहा कि सरकार देशहित और जनकल्याण को प्राथमिकता देकर फैसले ले रही है। उन्होंने दावा किया कि प्रधानमंत्री मोदी के नेतृत्व में कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं, जिनका सीधा लाभ आम जनता तक पहुंच रहा है। उन्होंने कहा कि चुनाव सुधार और पारदर्शी व्यवस्था से लोकतंत्र और मजबूत होगा। वहीं, सरकार युवाओं के भविष्य को ध्यान में रखते हुए परीक्षाओं में पारदर्शिता बनाए रखने के लिए लगातार कदम उठा रही है।

युवक की मौत पर हंगामा, ससुराल पक्ष पर केस दर्ज

भारतेन्दु संवाददाता, कुराली। गांव बड़ौदी में एक युवक की मौत के बाद परिजनों और ग्रामीणों ने सड़क पर शव रखकर न्याय की मांग की। मृतक की पहचान अवजीत सिंह के रूप में हुई है। परिजनों के अनुसार अवजीत का पत्नी कमलजीत कौर के साथ विवाद चल रहा था और तलाक का मामला अदालत में विचाराधीन था। रविवार दोपहर अवजीत अपने घर में बेहोशी की हालत में मिला था। उसे अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया। परिजनों ने आरोप लगाया कि वह ससुराल पक्ष से परेशान था और इसी कारण उसने यह कदम उठाया। कार्रवाई की मांग को लेकर उन्होंने कुराली-सीसवां-चंडीगढ़ रोड पर जाम लगा दिया।

सूचना मिलने पर माजरी थाना पुलिस मौके पर पहुंची और उचित कार्रवाई का आश्वासन देकर जाम खुलवाया। पुलिस ने मृतक की पत्नी कमलजीत कौर, सास कुलदीप कौर और दोनों सालों गगनदीप सिंह व कलजीत सिंह के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है।

सरकारी कर्मचारियों को सोलर शुल्क से मिली राहत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ प्रशासन सरकारी आवासों में रहने वाले कर्मचारियों को सोलर पावर प्लांट से जुड़े मासिक शुल्क में राहत देने की तैयारी कर रहा है। प्रधानमंत्री सूर्य योजना के तहत जिन सरकारी मकानों की छतों पर सोलर पावर प्लांट लगाए गए हैं, वहां अब कर्मचारियों के लिए हर महीने अनिवार्य रूप से यूजर चार्ज देना जरूरी नहीं होगा। प्रशासन ने इस संबंध में प्रस्ताव तैयार कर लिया है और अगले महीने इसे मंजूरी मिलने की संभावना जताई जा रही है।

वर्तमान व्यवस्था के तहत तीन किलोवाट क्षमता वाले सोलर पावर प्लांट के लिए कर्मचारियों से प्रति किलोवाट 300 रुपये के हिसाब से कुल 900 रुपये प्रतिमाह वसूले जाते हैं। छह किलोवाट क्षमता वाले प्लांट वाले बड़े सरकारी मकानों में रहने वाले कर्मचारियों से 1800 रुपये प्रति माह तक यूजर चार्ज लिया जाता है। कई कर्मचारियों का कहना है कि वे सोलर प्लांट से उत्पन्न पूरी बिजली का उपयोग नहीं कर पाते, फिर भी उन्हें तय राशि का भुगतान करना पड़ता है।

इससे उन पर अतिरिक्त आर्थिक बोझ पड़ता है।

प्रशासन के नए प्रस्ताव के अनुसार जो कर्मचारी सोलर प्लांट से मिलने वाली बिजली का उपयोग नहीं करना चाहेंगे, उनसे कोई मासिक यूजर चार्ज नहीं लिया जाएगा। ऐसे कर्मचारियों को केवल सामान्य बिजली आपूर्ति की वास्तविक खपत के आधार पर बिजली बिल का भुगतान करना होगा। उनके मकान की छत पर लगे सोलर प्लांट से बनने वाली बिजली सीधे विद्युत ग्रिड में जाएगी और उससे होने वाली आय प्रशासन के खाते में जमा होगी।

दूसरी ओर जो कर्मचारी सोलर ऊर्जा का उपयोग जारी रखना चाहेंगे, उनसे पहले की तरह निर्धारित मासिक यूजर चार्ज लिया जाएगा। प्रशासन का मानना है कि इस व्यवस्था से कर्मचारियों को अपनी आवश्यकता के अनुसार विकल्प चुनने की सुविधा मिलेगी और अनावश्यक आर्थिक बोझ भी कम होगा।

सरकारी मकानों पर सोलर प्लांट लगाने का पूरा खर्च प्रशासन वहन कर रहा है, जबकि निजी मकानों में यह खर्च स्वयं उपभोक्ताओं को उठाना पड़ता है। पिछले छह महीनों से शहर में बिजली के बिल भी हर महीने जारी किए जा रहे हैं, जिससे बिजली खपत की निगरानी और भुगतान व्यवस्था अधिक व्यवस्थित हुई है।

नगर निगम चुनाव से पहले 'आप 'में बढ़ी टूट, छह पार्षदों ने छोड़ा साथ

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

◆ आप के कमजोर संगठन पर उठे सवाल, बढ़ी राजनीतिक चुनौती

नगर निगम चुनाव से पहले आम आदमी पार्टी को चंडीगढ़ में लगातार राजनीतिक झटके लग रहे हैं। वर्ष 2021 के नगर निगम चुनाव में सबसे अधिक 14 सीटें जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनी आप अब केवल आठ पार्षदों तक सिमट गई है। पिछले कुछ वर्षों में पार्टी के छह पार्षद अन्य दलों में शामिल हो चुके हैं, जबकि जल्द ही दो और पार्षदों के पार्टी छोड़ने की चर्चा भी तेज है। इससे पार्टी के संगठन और नेतृत्व पर सवाल उठने लगे हैं।

राजनीतिक जानकारों का मानना है कि चुनाव से पहले पार्षदों का लगातार पार्टी छोड़ना आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती बन सकता है। कांग्रेस और भाजपा दोनों ही अपने संगठन को मजबूत करने के लिए दूसरे दलों के जनप्रतिनिधियों को अपने साथ जोड़ने में सक्रिय हैं। कांग्रेस नेताओं का दावा है कि आने वाले दिनों में आप का एक और पार्षद उनकी पार्टी में शामिल हो सकता है। अब तक भाजपा ने कांग्रेस और आप दोनों दलों के कई पार्षदों को अपने साथ जोड़ा है। वहीं कांग्रेस ने भी आप के कई पार्षदों को शामिल कर अपनी राजनीतिक स्थिति मजबूत करने का प्रयास किया है। दूसरी ओर आप ने केवल शिरोमणि अकाली दल के एक पार्षद को अपने साथ जोड़ा है।

पार्टी छोड़ चुके कई पार्षदों ने कमजोर संगठन और प्रभावी नेतृत्व के अभाव को मुख्य कारण बताया है। उनका कहना है कि संगठन में जनप्रतिनिधियों की बात नहीं सुनी जाती थी और विकास कार्यों को लेकर भी अपेक्षित सहयोग नहीं मिलता था। कुछ नेताओं ने यह भी आरोप लगाया कि पार्टी के भीतर स्पष्ट नेतृत्व और समन्वय की कमी रही, जिससे कार्यकर्ताओं और पार्षदों में असंतोष बढ़ता गया।

चंडीगढ़ में हर आठवां खाद्य नमूना मिला मिलावटी

डेयरी उत्पादों सहित कई खाद्य पदार्थों में मिलावट, किडनी और लिवर रोगों का बढ़ा खतरा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

चंडीगढ़ में खाद्य पदार्थों में मिलावट का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा लोकसभा में प्रस्तुत रिपोर्ट ने शहर की खाद्य सुरक्षा व्यवस्था पर गंभीर सवाल खड़े कर दिए हैं। रिपोर्ट के अनुसार पिछले पांच वर्षों में शहर से लिए गए खाद्य पदार्थों के 2,149 नमूनों में से 259 नमूने जांच में निर्धारित गुणवत्ता मानकों पर खरे नहीं उतरे। यानी लगभग 12 प्रतिशत नमूने फेल पाए गए, जो इस बात का संकेत हैं कि शहर में हर आठ में से एक खाद्य पदार्थ का नमूना मिलावटी या मानकों के अनुरूप नहीं है।

रिपोर्ट के अनुसार डेयरी उत्पादों में सबसे अधिक अनियमितताएं सामने आई हैं। दूध, पनीर, घी और अन्य दुग्ध उत्पादों में मिलावट के कई मामले पाए गए हैं। इसके अलावा मसालों, तेल, मिठाइयों और अन्य खाद्य सामग्री में भी गुणवत्ता संबंधी खामियां मिली हैं।

प्रशासन समय-समय पर सैंपल लेकर कार्रवाई करता है, लेकिन इसके बावजूद मिलावटखोरी पर पूरी तरह रोक नहीं लग सकी है।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों का कहना है कि मिलावटी खाद्य पदार्थों का लगातार सेवन शरीर के लिए बेहद खतरनाक साबित हो सकता है। दूध और अन्य खाद्य सामग्री में यूरिया, डिटर्जेंट, स्टार्च, फार्मेलिन तथा विभिन्न सिंथेटिक रसायनों की मिलावट की जाती है। ऐसे पदार्थों के सेवन से किडनी, लिवर और पाचन तंत्र पर गंभीर असर पड़ सकता है। लंबे समय तक इनका सेवन करने से शरीर की रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होने के साथ कई गंभीर बीमारियों का खतरा भी बढ़ जाता है।

खाद्य सुरक्षा विभाग ने मिलावट रोकने के लिए लगातार अभियान चलाए हैं। पिछले पांच वर्षों के दौरान खाद्य सुरक्षा नियमों के उल्लंघन के 301 मामलों में दोषियों पर जुर्माना लगाया गया, जबकि 75 मामलों में अदालतों ने सजा भी सुनाई। प्रशासन का कहना है कि नियमों का उल्लंघन करने वाले कारोबारियों के खिलाफ आगे भी सख्त कार्रवाई जारी रहेगी।

पंजाब यूनिवर्सिटी में करंट लगने से पीएचडी छात्रा की हुई मौत

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

पंजाब यूनिवर्सिटी परिसर में मंगलवार को एक दर्दनाक हादसे में माइक्रोबायोलॉजी विभाग की पीएचडी स्कॉलर ज्योति की करंट लगने से मौत हो गई। वह हरियाणा के रेवाड़ी जिले की रहने वाली थीं। इस घटना से पूरे विश्वविद्यालय परिसर में शोक का माहौल है, जबकि कैंपस की विद्युत सुरक्षा व्यवस्था को लेकर गंभीर सवाल खड़े हो गए हैं।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार ज्योति मंगलवार सुबह गर्ल्स हॉस्टल नंबर-10 से माइक्रोबायोलॉजी विभाग जा रही थीं। वह गर्ल्स हॉस्टल नंबर-8 और यूआईईटी को जोड़ने वाली सड़क के किनारे बने कच्चे रास्ते से गुजर रही थीं। इसी दौरान अचानक उन्हें करंट लग गया और वह मौके पर ही गंभीर रूप से घायल होकर गिर पड़ीं। आसपास मौजूद लोगों और अन्य छात्रों ने तुरंत उन्हें सेक्टर-16

स्थित सरकारी मेडिकल कॉलेज एवं अस्पताल पहुंचाया, लेकिन चिकित्सकों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना की सूचना मिलते ही पुलिस और विश्वविद्यालय प्रशासन मौके पर पहुंच गया। फिलहाल यह स्पष्ट नहीं हो पाया है कि करंट किस कारण फैला और हादसा कैसे हुआ। पुलिस ने मामले की जांच शुरू कर दी है और विद्युत व्यवस्था की तकनीकी जांच भी कराई जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि जांच रिपोर्ट आने के बाद ही दुर्घटना के वास्तविक कारणों का पता चल सकेगा। इस हादसे के बाद विश्वविद्यालय के छात्रों में भारी रोष है।

एनएचएम हड़ताल से मोहाली के 45 क्लीनिक बंद

भारतेन्दु संवाददाता, मोहाली। राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (एनएचएम) के कर्मचारियों की 25 जुलाई से जारी हड़ताल का असर मोहाली जिले की स्वास्थ्य सेवाओं पर पड़ रहा है। हड़ताल के कारण जिले के 45 आम आदमी क्लीनिकों में सेवाएं पूरी तरह प्रभावित हो गई हैं। इससे मरीजों को मुफ्त इलाज, जांच और दवाओं के लिए परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

सबसे ज्यादा दिक्कत बुजुर्गों, महिलाओं और नियमित दवा लेने वाले मरीजों को हो रही है। क्लीनिक बंद होने से बड़ी संख्या में मरीज सिविल अस्पताल पहुंच रहे हैं, जिससे ओपीडी में भीड़ बढ़ गई है। कई मरीज बिना इलाज कराए वापस लौटने को मजबूर हुए, जबकि कुछ ने निजी अस्पतालों और लैब का सहारा लिया।

मरीजों का कहना है कि आम आदमी क्लीनिक में रक्तचाप, शुगर सहित कई सामान्य जांच मुफ्त होती थीं, लेकिन अब निजी संस्थानों में इन्हीं सेवाओं के लिए अधिक खर्च करना पड़ रहा है।

जलभराव कई सेक्टरों में जलभराव से यातायात प्रभावित, लोगों को झेलनी पड़ी परेशानी

तेज बारिश में डूबा चंडीगढ़, निगम की तैयारियों की खुली पोल

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

रविवार रात से सोमवार सुबह तक हुई तेज बारिश ने एक बार फिर चंडीगढ़ नगर निगम की मानसून तैयारियों की हकीकत सामने ला दी। शहर के कई प्रमुख मार्गों, आंतरिक सड़कों और रिहायशी क्षेत्रों में भारी जलभराव हो गया, जिससे आम जनजीवन बुरी तरह प्रभावित रहा। सड़कें तालाब जैसी नजर आने लगीं और वाहन चालकों के साथ-साथ पैदल राहगीरों को भी भारी परेशानियों का सामना करना पड़ा। कई स्थानों पर वाहनों की लंबी कतारें लग गईं और कार्यालय जाने वाले कर्मचारी, विद्यार्थी तथा अन्य लोग समय पर अपने गंतव्य तक नहीं पहुंच सके।

सबसे अधिक प्रभावित क्षेत्रों में सेक्टर-39बी का एचआईजी हाउसिंग क्षेत्र रहा, जहां मकान नंबर 1055 के सामने सड़क पर कई घंटे तक पानी जमा रहा। इसी क्षेत्र में इमटेक के सामने भी जलभराव के कारण यातायात प्रभावित हुआ। सेक्टर-28डी स्थित खेड़ा मंदिर के सामने सड़क पूरी तरह पानी में डूब गई, जिससे श्रद्धालुओं और स्थानीय निवासियों को काफी दिक्कत हुई। सेक्टर-61 में मकान नंबर 431 से 436 तक पूरी लाइन में पानी भर गया और कई घरों के बाहर से होते हुए पानी आंगन तक पहुंच गया।

तेज बारिश में निगम की मानसून तैयारियां पहली परीक्षा में पूरी तरह नाकाम

इसके अलावा सेक्टर-26, बापूधाम कॉलोनी, इंडस्ट्रियल एरिया, सेक्टर-9, सेक्टर-43 और कई अन्य इलाकों में भी जलभराव की स्थिति बनी रही। कई दोपहिया वाहन पानी में बंद हो गए, जबकि कार चालकों को भी बेहद धीमी गति से गुजरना पड़ा। स्थानीय लोगों का कहना है कि समय पर सीवर और वर्षा जल निकासी प्रणाली की सफाई नहीं होने के कारण बारिश का पानी निकल नहीं सका।

नगर निगम ने मानसून से पहले आठ कंट्रोल रूम स्थापित करने और विशेष टीमें तैनात करने का दावा किया था, ताकि जलभराव की स्थिति में तुरंत कार्रवाई की जा सके। हालांकि पहली ही तेज बारिश में ये दावे खोखले साबित हुए। कई क्षेत्रों में घंटों तक पानी जमा रहा और राहत कार्य समय पर शुरू नहीं हो सके। लोगों का कहना है कि हर वर्ष नालों और सीवर लाइनों की सफाई पर करोड़ों रुपये खर्च किए जाने के बावजूद स्थिति में कोई सुधार दिखाई नहीं देता।

स्थानीय नागरिकों ने नगर निगम प्रशासन से अस्थायी उपायों के बजाय स्थायी समाधान अपनाने, जल निकासी व्यवस्था को आधुनिक बनाने तथा नियमित रूप से नालों और सीवरों की प्रभावी सफाई सुनिश्चित करने की मांग की है, ताकि हर मानसून में लोगों को ऐसी परेशानियों का सामना न करना पड़े।

इस बीच नगर निगम के अधिकारियों ने प्रभावित क्षेत्रों का निरीक्षण कर जल निकासी कार्य में तेजी लाने का दावा किया। पंपिंग मशीनों और सफाई कर्मचारियों की अतिरिक्त टीमें भी तैनात की गईं।

असम में जलभराव के कारण चंडीगढ़ की कई ट्रेनों ने बदले मार्ग

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

असम में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण सिलघर रेलवे यार्ड में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई है, जिसका असर चंडीगढ़ से पूर्वोत्तर राज्यों के लिए चलने वाली कई ट्रेनों पर पड़ा है। रेलवे प्रशासन ने सुरक्षा को ध्यान में रखते हुए कई ट्रेनों के मार्ग में बदलाव किया है, जबकि कुछ ट्रेनों को आंशिक रूप से रद और कुछ को पूरी तरह रद कर दिया गया है। इससे यात्रियों की परेशानियां बढ़ गई हैं।

रेलवे अधिकारियों के अनुसार डिचोव नदी का जलस्तर बढ़ने से सिलघर रेलवे यार्ड में पानी भर गया है। इसके चलते इंजीनियरिंग विभाग ने संबंधित रेलखंड पर ट्रेनों का संचालन अस्थायी रूप से रोक दिया है। सुरक्षा कारणों से कई ट्रेनों को वैकल्पिक मार्ग से चलाने का निर्णय लिया गया है।

चंडीगढ़ से डिब्रूगढ़ जाने वाली 15904 चंडीगढ़-डिब्रूगढ़ एक्सप्रेस को अब निर्धारित मार्ग के स्थान पर रानी, रांगापानी और न्यू बोंगाईगांव होकर चलाया जाएगा। इसी प्रकार 15903 डिब्रूगढ़-चंडीगढ़ एक्सप्रेस का मार्ग भी बदल दिया गया है। मार्ग परिवर्तन के कारण दोनों दिशाओं में यात्रा करने वाले यात्रियों को अतिरिक्त समय लग सकता है और

ट्रेनों के निर्धारित समय में भी बदलाव संभव है।

रेलवे ने बताया कि प्रभावित ट्रेनों में राजधानी एक्सप्रेस, राजेंद्र नगर राजधानी, विवेक एक्सप्रेस, कामरूप एक्सप्रेस, नागालैंड एक्सप्रेस सहित पूर्वोत्तर क्षेत्र की कई अन्य महत्वपूर्ण ट्रेनें भी शामिल हैं। कुछ ट्रेनों को बीच रास्ते तक ही संचालित किया जा रहा है, जबकि कुछ सेवाओं को अस्थायी रूप से रद किया गया है।

रेलवे प्रशासन ने यात्रियों से अपील की है कि यात्रा शुरू करने से पहले अपनी ट्रेन की ताजा स्थिति अवश्य जांच लें। इसके लिए यात्री रेलवे की आधिकारिक वेबसाइट, हेल्पलाइन नंबर या एनटीईएस के माध्यम से जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। प्रशासन का कहना है कि जलभराव की स्थिति सामान्य होने और ट्रैक पूरी तरह सुरक्षित घोषित होने के बाद ही नियमित रेल संचालन बहाल किया जाएगा। फिलहाल यात्रियों की सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दी जा रही है।

आम जनता की सुरक्षा के लिए सांसद सीचेवाल ने छोड़ी अपनी सिक्योरिटी

सांसद सीचेवाल ने सुरक्षा वापस कर बढ़ते अपराधों पर चिंता जताई, जनता की सुरक्षा को बताया प्राथमिकता

भारतेंदु संवाददाता, कपूरथला

राज्यसभा सांसद संत बलबीर सिंह सीचेवाल ने अपनी सरकारी सुरक्षा वापस करने का निर्णय लिया है। उन्होंने पंजाब के पुलिस महानिदेशक को पत्र लिखकर अपनी सुरक्षा में तैनात सुरक्षाकर्मियों को तत्काल हटाने का अनुरोध किया है। सीचेवाल के इस फैसले को राजनीतिक हलकों में अलग नजरिए से देखा जा रहा है, क्योंकि जहां कई नेता अधिक सुरक्षा की मांग करते हैं, वहीं उन्होंने स्वेच्छा से मिली सुरक्षा को लौटाने का फैसला किया है।

संत सीचेवाल ने सुरक्षा वापस करने के साथ-साथ पंजाब की मौजूदा कानून व्यवस्था पर भी चिंता जताई है। उन्होंने अपने पत्र में कहा कि जालंधर जिले के लोहियां क्षेत्र और सुल्तानपुर लोधी इलाके में चोरी, लूटपाट और अन्य आपराधिक घटनाएं लगातार बढ़ रही हैं। ऐसे हालात में उनका मानना है कि उनकी व्यक्तिगत सुरक्षा से ज्यादा जरूरी आम लोगों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करना है।

उन्होंने बताया कि वर्तमान में उनकी सुरक्षा में छह सुरक्षाकर्मी तैनात हैं। हालांकि शुरुआत में भी उन्होंने सुरक्षा लेने से इनकार किया था। उनका कहना है कि उन्हें किसी प्रकार का खतरा नहीं है और सुरक्षा की आवश्यकता आम नागरिकों को अधिक है। उन्होंने पुलिस विभाग को सुझाव दिया कि उनके साथ तैनात छह सुरक्षाकर्मियों में से तीन को थाना लोहियां खास और तीन को थाना सुल्तानपुर लोधी में तैनात किया जाए, ताकि इनका उपयोग क्षेत्र की सुरक्षा व्यवस्था को बेहतर बनाने में किया जा सके।

संत सीचेवाल ने पत्र में क्षेत्र में बढ़ते अपराधों का उल्लेख करते हुए कहा कि लोगों में असुरक्षा की भावना बढ़ रही है। उन्होंने बताया कि लोहियां और आसपास के इलाकों में चोरी और लूटपाट की घटनाएं लगातार सामने आ रही हैं। उन्होंने मलसियां पुलिस चौकी में पुलिस बल की कमी का भी जिक्र किया। उनके अनुसार, पर्याप्त पुलिस बल नहीं होने के कारण अपराधियों के हौसले बढ़ रहे हैं और आम लोग खुद को सुरक्षित महसूस नहीं कर रहे।

उन्होंने अपने गांव सीचेवाल का उदाहरण देते हुए कहा कि एक ही रात में वहां चोरी की आठ घटनाएं सामने आई थीं। इसके अलावा बिजली की तारों की चोरी भी क्षेत्र में आम समस्या बन चुकी है। उन्होंने कहा कि ऐसी घटनाओं से ग्रामीणों में चिंता बढ़ रही है और प्रशासन को इस दिशा में प्रभावी कदम उठाने की जरूरत है।

संत सीचेवाल ने पवित्र काली बेईं का भी उल्लेख किया। उन्होंने कहा कि श्री गुरु नानक देव जी से जुड़े इस पवित्र तीर्थ स्थल पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु आते हैं, लेकिन बढ़ती आपराधिक घटनाओं के कारण श्रद्धालुओं में भी भय का माहौल पैदा हो रहा है। उन्होंने कहा कि धार्मिक स्थलों और आम जनता की सुरक्षा को प्राथमिकता दी जानी चाहिए।

उन्होंने अपने पत्र में स्पष्ट किया कि सुरक्षा व्यवस्था का उद्देश्य केवल किसी व्यक्ति विशेष की सुरक्षा करना नहीं, बल्कि समाज के प्रत्येक नागरिक को सुरक्षित वातावरण उपलब्ध कराना होना चाहिए। उन्होंने पंजाब सरकार और पुलिस प्रशासन से अपील की कि अपराधों पर नियंत्रण के लिए पुलिस व्यवस्था को मजबूत किया जाए और आम लोगों की सुरक्षा सुनिश्चित की जाए।

संत बलबीर सिंह सीचेवाल के इस कदम को सामाजिक जिम्मेदारी से जोड़कर देखा जा रहा है। उन्होंने कहा कि यदि उनकी सुरक्षा में तैनात जवान जनता की सुरक्षा के लिए अधिक उपयोगी साबित हो सकते हैं तो यह ज्यादा बेहतर होगा। उनका मानना है कि पुलिस बल का सही उपयोग आम नागरिकों में विश्वास बढ़ाने और अपराधों पर रोक लगाने में किया जाना चाहिए।

जालंधर ग्रेनेड हमले में पाकिस्तानी आरोपी पर वारंट जारी

एनआईए अदालत ने फरार आरोपी शहजाद भट्टी के खिलाफ उठाया कड़ा कदम

भारतेंदु संवाददाता, जालंधर। जालंधर के सोशल मीडिया प्रभावक नवदीप सिंह उर्फ रोजर संधू के घर हुए ग्रेनेड हमले के मामले में मोहाली की विशेष राष्ट्रीय जांच एजेंसी अदालत ने सख्त कार्रवाई की है। अदालत ने पाकिस्तानी आतंकवादी और सोशल मीडिया प्रभावक शहजाद भट्टी के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी किया है।

ग्रेनेड हमले की साजिश में शहजाद भट्टी पर जांच एजेंसी की कार्रवाई तेज

अदालत ने यह कदम आरोपी के लगातार फरार रहने के कारण उठाया है। जांच एजेंसी के अनुसार शहजाद भट्टी के खिलाफ पंजाब के अलग-अलग थानों में आतंकवाद, आपराधिक साजिश और गैरकानूनी गतिविधियों से जुड़े कई मामले दर्ज हैं। जांच में यह भी सामने आया है कि आरोपी वर्तमान में ब्राजील में छिपा हुआ है।

राष्ट्रीय जांच एजेंसी की जांच में कई महत्वपूर्ण जानकारियां सामने आई हैं। जांच के अनुसार शहजाद भट्टी पाकिस्तानी मोबाइल नंबर के माध्यम से एक संदेश समूह चला रहा था, जिसमें कई भारतीय नंबर भी जुड़े हुए थे। आरोप है कि इसी समूह के माध्यम से जालंधर में हुए हमले की योजना तैयार की गई थी।

जांच एजेंसी के मुताबिक शहजाद भट्टी भारत विरोधी गतिविधियों को संचालित कर रहा है और विदेश में रहकर अपने नेटवर्क के जरिए गतिविधियां चला रहा है। एजेंसी अब आरोपी को भारत लाने के लिए कानूनी प्रक्रिया आगे बढ़ा रही है।

मामला 16 मार्च 2025 का है, जब जालंधर के थाना मकसूदां क्षेत्र में सोशल मीडिया प्रभावक नवदीप सिंह उर्फ रोजर संधू के घर की बालकनी में एक संदिग्ध वस्तु मिली थी। जांच में वह वस्तु हैंड ग्रेनेड निकली। इसके बाद पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की थी।

प्रारंभिक जांच में सामने आया कि शहजाद भट्टी ने सोशल मीडिया मंचों के माध्यम से नवदीप संधू पर दबाव बनाया था। आरोप है कि ऑनलाइन माध्यम से पैसे देने और लाइव प्रसारण से जुड़े विवाद के बाद उसने भारतीय नेटवर्क की मदद से हमला करवाने की साजिश रची।

गैर जमानती वारंट अदालत की एक महत्वपूर्ण प्रक्रिया है। इसे तब जारी किया जाता है जब कोई आरोपी लगातार फरार रहता है या अदालत में पेश नहीं होता। यह वारंट आरोपी की गिरफ्तारी तक प्रभावी रहता है। इसके आधार पर आरोपी के खिलाफ अंतरराष्ट्रीय स्तर पर तलाश और उसे विदेश से वापस लाने की प्रक्रिया भी शुरू की जा सकती है।

जांच एजेंसियां अब शहजाद भट्टी के संपर्कों और उसके नेटवर्क की गहन जांच कर रही हैं। अधिकारियों का कहना है कि मामले में जुड़े अन्य लोगों की भूमिका भी खंगाली जा रही है।

संगरूर भाजपा कार्यालय पेट्रोल बम मामले में दो आरोपी गिरफ्तार, साजिश का हुआ खुलासा

सोशल मीडिया संपर्क से रची साजिश, विदेश बैठे व्यक्ति पर पुलिस की नजर

भारतेंदु संवाददाता, संगरूर। संगरूर में भाजपा जिला कार्यालय पर पेट्रोल बम फेंकने की घटना का पुलिस ने 12 घंटे के भीतर खुलासा करने का दावा किया है। पुलिस ने इस मामले में दो आरोपितों को गिरफ्तार किया है। दोनों आरोपित संगरूर जिले के रहने वाले हैं। पुलिस जांच में सामने आया है कि दोनों सोशल मीडिया के माध्यम से विदेश में बैठे एक व्यक्ति के संपर्क में थे, जिसने बड़ी रकम देने का लालच देकर वारदात को अंजाम देने के लिए कहा था।

एसएसपी संगरूर डॉ. रवजोत ग्रेवाल ने बताया कि 26 जुलाई की रात करीब 2:35 बजे दो युवक उपली गांव की ओर से पैदल आए थे। आरोपितों ने बोतल में पेट्रोल भरकर उसमें आग लगाई और भाजपा कार्यालय की चारदीवारी के ऊपर से भवन की दीवार की तरफ फेंक दिया। इसके बाद दोनों मौके से फरार हो गए। पुलिस के अनुसार इस वारदात का उद्देश्य कार्यालय को नुकसान पहुंचाना और माहौल खराब करना था।

जांच के दौरान पुलिस ने हैपी सिंह उर्फ हैपी निवासी भम्माबंदी थाना लोंगोवाल और जसप्रीत सिंह उर्फ जस्सी निवासी लहरा को गिरफ्तार किया। पुलिस ने आरोपितों के पास से वारदात में इस्तेमाल मोटरसाइकिल और दो मोबाइल फोन बरामद किए हैं। मामले में यूएपीए की धाराएं भी जोड़ी गई हैं।

पूछताछ में सामने आया कि दोनों आरोपित सोशल मीडिया के जरिए 'राणा भाई' नामक व्यक्ति के संपर्क में आए थे। आरोप है कि उक्त व्यक्ति ने उन्हें पेट्रोल बम फेंकने और घटना का वीडियो बनाकर भेजने के बदले बड़ी रकम देने का भरोसा दिलाया था। वारदात के बाद आरोपितों ने वीडियो बनाकर उसे भेजी, जिसके बाद उन्हें यूपीआई के माध्यम से केवल 1200 और 1000 रुपये यानी कुल 2200 रुपये का भुगतान किया गया।

पुलिस अब विदेश में बैठे इस व्यक्ति की पहचान और उसके सोशल मीडिया खातों की जांच कर रही है। साथ ही आरोपितों के मोबाइल फोन और यूपीआई लेनदेन की भी पड़ताल की जा रही है।

बिजली विभाग के जेई पर 12 लाख की हेराफेरी का केस दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। थाना पीएयू पुलिस ने बिजली विभाग के एक जेई के खिलाफ सरकारी राशि में हेराफेरी के आरोप में मामला दर्ज किया है। आरोप है कि जेई ने वर्ष 2023-24 के दौरान विभाग की करीब 12 लाख 25 हजार 669 रुपये की राशि सरकारी खाते में जमा नहीं करवाई। पुलिस के अनुसार अग्र नगर स्थित बिजली विभाग कार्यालय के अधिकारियों की ओर से इस मामले में शिकायत दी गई थी।

शिकायत में आरोप लगाया गया कि विभाग में तैनात जेई बिक्कर सिंह ने निर्धारित प्रक्रिया के तहत जमा होने वाली सरकारी रकम को खाते में जमा नहीं किया।

मामले की शिकायत मिलने के बाद पुलिस ने जांच शुरू की। जांच में आरोप सही पाए जाने के बाद जेई बिक्कर सिंह पुत्र दल सिंह के खिलाफ सरकारी धन में हेराफेरी करने के आरोप में केस दर्ज किया गया है।

ब्लैकमेल और दहेज प्रताड़ना के आरोप, पति समेत तीन पर केस

महिला ने लगाए गंभीर आरोप, पुलिस जांच के बाद दर्ज हुई एफआईआर

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। निजी बैंक में नौकरी करने वाली एक महिला की शिकायत पर थाना मोती नगर पुलिस ने उसके पति, ससुर और सास के खिलाफ मामला दर्ज किया है। महिला ने आरोप लगाया है कि उसे पहले धमकाकर शादी के लिए मजबूर किया गया और बाद में दहेज के लिए प्रताड़ित किया गया। पुलिस ने जांच के बाद एफआईआर दर्ज कर मामले की जांच शुरू कर दी है।

ब्लैकमेल कर शादी कराने और दहेज मांगने का महिला ने लगाया आरोप

शिकायतकर्ता महिला ने पुलिस को बताया कि शादी से पहले वह एक निजी बैंक में काम करती थी। इसी दौरान उसकी मुलाकात शुभम वशिष्ठ से हुई। महिला का आरोप है कि शुभम ने खुद को प्रभावशाली और हथियार रखने वाला बताकर उसे डराया-धमकाया। उसने आपत्तिजनक तस्वीरों को वायरल करने की धमकी देकर 8 जून 2023 को मंदिर में शादी करने के लिए मजबूर किया।

महिला के अनुसार बाद में परिवार की सहमति से 18 जून 2023 को होटल में विवाह समारोह भी आयोजित किया गया, जिसमें उसके परिवार ने लाखों रुपये खर्च किए और आभूषण सहित दहेज का सामान दिया। आरोप है कि शादी के बाद पति और ससुराल वालों ने उससे पैसों की मांग शुरू कर दी।

महिला ने आरोप लगाया कि उसके नाम पर एसी की फाइनेंसिंग करवाई गई और उसकी किस्तें भी उसी से भरवाई गईं। इसके बाद 20 लाख रुपये की मांग की जाने लगी। महिला का कहना है कि विरोध करने पर उसके साथ मारपीट की जाती थी और मानसिक रूप से परेशान किया जाता था।

शिकायत के अनुसार महिला ने अलग-अलग समय पर बैंक से ऋण लेकर और परिवार से आर्थिक मदद लेकर लाखों रुपये पति और ससुराल पक्ष को दिए। उसने आरोप लगाया कि उसकी पूरी तनख्वाह भी उससे ले ली जाती थी। महिला ने यह भी आरोप लगाया कि पति हथियार दिखाकर उसे जान से मारने की धमकी देता था।

पुलिस कमिश्नर की मंजूरी के बाद थाना मोती नगर में पति शुभम वशिष्ठ, ससुर कृष्णकांत वशिष्ठ और सास रमा वशिष्ठ के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। एडीसीपी ऑपरेशन रमनदीप सिंह भुल्लर की जांच के बाद कार्रवाई की गई। पुलिस ने व्हाट्सएप चैट और अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद मामला दर्ज किया है।

लुधियाना में जमीन सौदे में 8 करोड़ की ठगी, केस दर्ज

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। करोड़ों रुपये की जमीन के सौदे में धोखाधड़ी का मामला सामने आया है। आरोप है कि कुछ लोगों ने 7.125 एकड़ जमीन का सौदा तय कर पीड़ित से 8 करोड़ रुपये ले लिए, लेकिन तय समय पर जमीन की रजिस्ट्री नहीं करवाई और रकम भी वापस नहीं की। पुलिस ने शिकायत की जांच के बाद आधा दर्जन आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।

जानकारी के अनुसार शिकायतकर्ता इशपाल सिंह चावला ने पुलिस को दी शिकायत में बताया कि आरोपियों ने उनके साथ 7.125 एकड़ जमीन का सौदा 53 करोड़ 43 लाख 75 हजार रुपये में तय किया था। सौदे के तहत उन्होंने जमीन मालिकों को 6 करोड़ रुपये बतौर बयाना दिए थे, जबकि 2 करोड़ रुपये कमीशन के रूप में दिए गए थे।

शिकायतकर्ता का आरोप है कि पूरी रकम लेने के बाद भी आरोपियों ने तय तारीख पर जमीन की रजिस्ट्री उनके नाम नहीं करवाई। इसके अलावा पैसे वापस मांगने पर भी कोई समाधान नहीं किया गया। पीड़ित को जब लगा कि उसके साथ सुनियोजित तरीके से धोखाधड़ी की गई है तो उसने पुलिस प्रशासन से शिकायत कर कार्रवाई की मांग की।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि शिकायत की गहन जांच के बाद आरोपियों के खिलाफ धोखाधड़ी और अमानत में खयानत सहित संबंधित धाराओं के तहत केस दर्ज किया गया है।

लाठीचार्ज की निष्पक्ष जांच और दोषियों पर कार्रवाई की कांग्रेस ने उठाई मांग

सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज मामले में कांग्रेस पहुंची अनुसूचित जाति आयोग

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में सफाई कर्मचारियों पर कथित लाठीचार्ज के मामले को लेकर कांग्रेस ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग का रुख किया है। पंजाब कांग्रेस के सांसदों के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को आयोग के अधिकारियों से मुलाकात कर मामले की शिकायत सौंपी और दोषी अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की।

प्रतिनिधिमंडल में पंजाब से कांग्रेस सांसद अमरिंदर सिंह राजा वड़िंग, गुरजीत सिंह औजला, डॉ. अमर सिंह और धर्मवीर गांधी शामिल रहे। कांग्रेस नेताओं ने आरोप लगाया कि पंजाब सरकार ने अपनी मांगों को लेकर शांतिपूर्ण प्रदर्शन कर रहे सफाई कर्मचारियों पर लाठीचार्ज कराया, जिसमें कई कर्मचारी घायल हुए। उन्होंने कहा कि प्रदर्शन में बड़ी संख्या में जिला स्तर के कर्मचारी शामिल थे।

कांग्रेस नेताओं का कहना है कि सफाई कर्मचारियों का बड़ा वर्ग अनुसूचित जाति समुदाय से आता है, इसलिए यह मामला केवल कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि सामाजिक न्याय और दलित अधिकारों से भी जुड़ा हुआ है। उन्होंने आयोग से मामले की निष्पक्ष जांच कराने और जिम्मेदार अधिकारियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई की मांग की। सांसदों ने राष्ट्रीय अनुसूचित जाति आयोग से पीड़ित कर्मचारियों को न्याय दिलाने और घटना की पूरी जांच कराने का आग्रह किया।

फरीदकोट जेल में बंदियों से चार मोबाइल फोन हुए बरामद

भारतेंदु संवाददाता, फरीदकोट। केंद्रीय जेल फरीदकोट में सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने के लिए चलाए गए विशेष तलाशी अभियान के दौरान एक हाई रिस्क बंदी और तीन हवालातियों के कब्जे से चार मोबाइल फोन और एक सिम कार्ड बरामद किए गए हैं। जेल प्रशासन की शिकायत पर सिटी कोतवाली फरीदकोट पुलिस ने जेल एक्ट की संबंधित धाराओं के तहत अलग-अलग मामले दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। जानकारी के अनुसार केंद्रीय जेल के सहायक सुपरिटेंडेंट करमजीत सिंह भुल्लर ने पुलिस को बताया कि 27 जुलाई को जेल गार्ड की सहायता से सुरक्षा जोन, विभिन्न ब्लॉकों और बैरकों की गहन जांच की गई। इस दौरान ब्लॉक-बी की बैरक नंबर-6 में बंद हाई रिस्क बंदी नवजोत सिंह निवासी ईश्वर सिंह वाला, बरनाला के कब्जे से एक टच स्क्रीन मोबाइल फोन और सिम कार्ड बरामद हुआ।

लुधियाना ट्रांसपोर्ट नगर में गड्ढों से हादसे, हाईवे प्रबंधन पर उठे सवाल

भारतेंदु संवाददाता, लुधियाना। नेशनल हाईवे अथॉरिटी की कथित लापरवाही के चलते ट्रांसपोर्ट नगर चौक में बड़ा हादसा होने से टल गया। बारिश के बाद फ्लाईओवर के साथ लगी टूटी सर्विस रोड पर पानी भरने से गहरे गड्ढे दिखाई नहीं दिए, जिसके कारण कई वाहन इनमें फंस गए। वाहन चालकों और ट्रांसपोर्टरों ने हाईवे प्रबंधन की कार्यप्रणाली पर सवाल उठाए हैं।

ट्रांसपोर्टर चरण सिंह लोहारा, बलराज शर्मा, सुरिंद्र सिंह अलवर, जेपी अग्रवाल, प्रिंस नारंग और रमन सिंह चड्ढा ने आरोप लगाया कि वाहन चालकों से टोल टैक्स तो वसूला जा रहा है, लेकिन सर्विस रोड और फ्लाईओवर की मरम्मत पर ध्यान नहीं दिया जा रहा। उन्होंने कहा कि टूटी सड़क और गड्ढों के कारण आए दिन हादसे हो रहे हैं और यातायात व्यवस्था भी प्रभावित हो रही है।

जानकारी के अनुसार बारिश के बाद ट्रांसपोर्ट नगर चौक में पानी से भरे गड्ढों में करीब आधा दर्जन वाहन फंस गए। इनमें दो ऑटो और एक कार पलट गई। हादसे में वाहनों को नुकसान पहुंचा और कुछ लोगों के घायल होने की भी सूचना है।

एक कार चालक, जो दूसरे शहर से जालंधर की ओर जा रहा था, पानी में छिपे गहरे गड्ढे को नहीं देख पाया। कार गड्ढे में फंसकर पलट गई, हालांकि चालक बाल-बाल बच गया। इसके अलावा माल से लदा टेंपो और कुछ ऑटो व ई-रिक्शा भी गड्ढों में फंस गए।

फाजिल्का में 40 हजार बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर, 41 करोड़ से अधिक का बकाया शेष

भारतेंदु संवाददाता, फाजिल्का। बिजली विभाग के नए आंकड़ों ने जिले में बकाया बिजली बिलों की बड़ी समस्या को उजागर किया है। विभाग के अनुसार फाजिल्का में 40 हजार से अधिक बिजली उपभोक्ता डिफॉल्टर हो चुके हैं। इन उपभोक्ताओं पर कुल 41.88 करोड़ रुपये से अधिक का बिजली बिल बकाया है। इसमें सरकारी विभागों के बकाया बिल भी शामिल हैं।

बिजली विभाग की जानकारी के अनुसार जिले में कुल 40,185 उपभोक्ताओं को डिफॉल्टर घोषित किया गया है। इनमें 474 सरकारी विभाग और 39,711 शहरी व ग्रामीण उपभोक्ता शामिल हैं। सरकारी विभागों पर करीब 18.27 करोड़ रुपये की राशि लंबित है, जबकि शहरों और गांवों के उपभोक्ताओं पर लगभग 23.61 करोड़ रुपये का बिजली बिल बकाया है।

बकाया राशि वाले सरकारी विभागों में वाटर सप्लाई, सीवरेज, स्ट्रीट लाइट, अस्पताल, सरकारी स्कूल और डिस्पेंसरी सहित कई संस्थान शामिल हैं। विभाग का कहना है कि लंबे समय से बिजली बिल जमा नहीं करने वाले उपभोक्ताओं के खिलाफ कार्रवाई की प्रक्रिया शुरू कर दी गई है।

बिजली विभाग ने बड़ी संख्या में डिफॉल्टर उपभोक्ताओं को नोटिस भेजने की प्रक्रिया शुरू कर दी है। विभाग अब उन उपभोक्ताओं के बिजली कनेक्शन काटने की तैयारी कर रहा है, जिन पर लंबे समय से भुगतान लंबित है। शुरुआती कार्रवाई के तहत करीब 150 बिजली कनेक्शन काटे भी जा चुके हैं।

विभाग के अधिकारियों ने उपभोक्ताओं से अपील की है कि वे जल्द से जल्द अपने लंबित बिजली बिलों का भुगतान करें, ताकि उन्हें असुविधा का सामना न करना पड़े। अधिकारियों का कहना है कि बिजली आपूर्ति व्यवस्था को सुचारू बनाए रखने के लिए समय पर बिल भुगतान जरूरी है।

बिजली विभाग की इस कार्रवाई से उन उपभोक्ताओं में चिंता बढ़ गई है, जिन्होंने लंबे समय से अपने बिल जमा नहीं किए हैं। विभाग अब बकाया वसूली अभियान को और तेज करने की तैयारी में है। विभाग ने स्पष्ट किया है कि अभियान के दौरान नियमों के अनुसार कार्रवाई की जाएगी। उपभोक्ताओं को समय पर भुगतान करने और भविष्य में बकाया न बढ़ाने की सलाह दी गई है।

असहमति एलडीसी योजना विवाद में अदालत ने न्याय व्यवस्था ठप करने पर जताई आपत्ति

हाई कोर्ट ने वकीलों की हड़ताल पर जताई सख्त नाराजगी

भारतेंदु संवाददाता, चंडीगढ़। पंजाब में विधिक सहायता बचाव वकील योजना (एलडीसी) के विरोध में जिला अदालतों में चल रही वकीलों की हड़ताल पर पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने सोमवार को कड़ा रुख अपनाया। अदालत ने स्पष्ट शब्दों में कहा कि किसी भी योजना के क्रियान्वयन को लेकर वास्तविक शिकायतों पर विचार किया जा सकता है, लेकिन अनुचित मांगों को मनवाने के लिए न्यायिक कार्य ठप करना किसी भी स्थिति में स्वीकार नहीं किया जाएगा। अदालत ने टिप्पणी की कि न्यायिक व्यवस्था को दबाव में लाकर झुकाने का प्रयास सफल नहीं होने दिया जाएगा।

यह मामला पंजाब के विभिन्न जिला न्यायालयों में पिछले 27 दिनों से जारी अनिश्चितकालीन हड़ताल से संबंधित जनहित याचिका की सुनवाई के दौरान सामने आया। याचिका में कहा गया कि वकीलों के काम से विरत रहने के कारण राज्यभर में न्यायिक कार्य लगभग ठप हो गया है और हजारों वादकारी समय पर न्याय नहीं प्राप्त कर पा रहे हैं। इससे आम नागरिकों के संवैधानिक अधिकार प्रभावित हो रहे हैं तथा लंबित मामलों का बोझ लगातार बढ़ता जा रहा है।

न्याय व्यवस्था रोकने के प्रयास को हाई कोर्ट ने अस्वीकार्य बताया

कार्यवाहक मुख्य न्यायाधीश अश्वनी कुमार मिश्रा और न्यायमूर्ति रोहित कपूर की खंडपीठ ने सुनवाई के दौरान कहा कि पिछले 27 दिनों से न्यायिक राहत की उपलब्धता गंभीर रूप से प्रभावित हुई है। अदालत ने कहा कि यदि एलडीसी योजना के संचालन या उसके क्रियान्वयन में कोई वास्तविक समस्या है तो उसके समाधान के लिए वैधानिक और संवैधानिक तरीके उपलब्ध हैं, लेकिन अदालतों का काम रोककर दबाव बनाना उचित नहीं माना जा सकता। पीठ ने यह भी पूछा कि न्यायालयों का कामकाज बाधित कर वकील समाज को आखिर क्या संदेश देना चाहते हैं।

हाई कोर्ट ने टिप्पणी की कि ऐसा प्रतीत होता है जैसे यह मान लिया गया हो कि न्यायिक व्यवस्था अंततः दबाव के आगे झुक जाएगी, जबकि अदालत ऐसा होने नहीं देगी। अदालत ने कहा कि न्यायिक संस्थाओं की गरिमा बनाए रखना सभी पक्षों की जिम्मेदारी है और कानून के शासन को किसी भी परिस्थिति में प्रभावित नहीं होने दिया जा सकता।

याचिकाकर्ता अधिवक्ता अरविंद सेठ ने अपनी जनहित याचिका में बताया कि राष्ट्रीय विधिक सेवा प्राधिकरण (नालसा) ने आर्थिक रूप से कमजोर और जरूरतमंद आरोपितों को प्रभावी कानूनी सहायता उपलब्ध कराने के उद्देश्य से एलडीसी योजना लागू की है। इस योजना के तहत पूर्णकालिक विधिक सहायता बचाव वकीलों की नियुक्ति की व्यवस्था की गई है ताकि पात्र लोगों को समयबद्ध और गुणवत्तापूर्ण कानूनी सहायता मिल सके।

मोबाइल की लत और अनियमित नींद से कमजोर हो रही नई पीढ़ी की कार्यक्षमता

आज का युवा वर्ग तकनीक के युग में तेजी से आगे बढ़ रहा है, लेकिन इसी के साथ उसकी जीवनशैली में भी बड़े बदलाव आए हैं। मोबाइल, सोशल मीडिया, ऑनलाइन गेम, वेब सीरीज और इंटरनेट के अत्यधिक उपयोग के कारण देर रात तक जागना और सुबह देर से उठना एक सामान्य आदत बनती जा रही है।

शुरुआत में यह केवल मनोरंजन या सुविधा की आदत लगती है, लेकिन धीरे-धीरे यह युवाओं के शारीरिक, मानसिक और सामाजिक स्वास्थ्य के लिए गंभीर चुनौती बन रही है। मानव शरीर एक निश्चित जैविक घड़ी के अनुसार संचालित होता है, जिसे बॉडी क्लॉक कहा जाता है। यह प्राकृतिक रूप से दिन और रात के चक्र के साथ तालमेल बनाकर शरीर की विभिन्न प्रक्रियाओं को नियंत्रित करती है। समय पर सोना और जागना शरीर के हार्मोन संतुलन, पाचन तंत्र, मस्तिष्क की कार्यक्षमता और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बेहतर बनाए रखता है। इसके विपरीत, देर रात तक जागने की आदत इस प्राकृतिक व्यवस्था को प्रभावित कर देती है।

चिकित्सकों के अनुसार, लंबे समय तक नींद की कमी या अनियमित नींद लेने वाले युवाओं में तनाव, चिंता, अवसाद, चिड़चिड़ापन, याददाश्त कमजोर होना और ध्यान केंद्रित करने में कठिनाई जैसी समस्याएं बढ़ सकती हैं। पर्याप्त नींद न मिलने से मस्तिष्क को आवश्यक आराम नहीं मिल पाता, जिसका सीधा प्रभाव विद्यार्थियों की पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी और नौकरीपेशा युवाओं की कार्यक्षमता पर पड़ता है।

देर रात तक मोबाइल या अन्य स्क्रीन देखने की आदत भी इस समस्या को बढ़ाती है। स्क्रीन से निकलने वाली नीली रोशनी शरीर में नींद नियंत्रित करने वाले हार्मोन मेलाटोनिन के निर्माण को प्रभावित करती है। इससे नींद आने में देरी होती है और व्यक्ति देर तक जागने के चक्र में फंस जाता है। यह आदत लंबे समय में मोटापा, मधुमेह, उच्च रक्तचाप, हृदय संबंधी समस्याओं और कमजोर प्रतिरक्षा प्रणाली जैसी बीमारियों का खतरा बढ़ा सकती है। इस बदलती जीवनशैली का सामाजिक प्रभाव भी दिखाई दे रहा है। देर से उठने वाले युवा अक्सर सुबह की सकारात्मक शुरुआत से वंचित रह जाते हैं। नाश्ता छोड़ना, व्यायाम से दूरी बनाना, परिवार के साथ समय कम बिताना और दिनभर थकान महसूस करना उनकी दिनचर्या का हिस्सा बन जाता है। इससे समय प्रबंधन, अनुशासन और जिम्मेदारियों के प्रति उदासीनता बढ़ सकती है।

शिक्षण संस्थानों में भी इसके दुष्परिणाम देखने को मिल रहे हैं। कई विद्यार्थी कक्षाओं में ध्यान नहीं दे पाते, उनमें सीखने की क्षमता

सुखदेव सिंह
नूरपुर, जिला कांगड़ा

प्रभावित होती है और परीक्षा परिणामों पर भी नकारात्मक असर पड़ता है। इसी प्रकार नौकरी करने वाले युवाओं में थकान, कम उत्पादकता और काम के प्रति उत्साह में कमी देखी जा सकती है।

इस समस्या से निपटने के लिए परिवार, शिक्षण संस्थानों और समाज को मिलकर प्रयास करने होंगे। माता-पिता को बच्चों के स्‍क्रीन टाइम पर संतुलित निगरानी रखनी चाहिए और स्वयं भी स्वस्थ जीवनशैली का उदाहरण प्रस्तुत करना चाहिए। विद्यालयों और महाविद्यालयों में नींद, मानसिक स्वास्थ्य और डिजिटल संतुलन के महत्व पर जागरूकता कार्यक्रम आयोजित किए जाने चाहिए।

युवाओं को भी यह समझना होगा कि सफलता केवल देर रात तक जागने से नहीं मिलती, बल्कि स्वस्थ शरीर और शांत मन से मिलती है। नियमित समय पर सोना-जागना, सोने से पहले मोबाइल से दूरी बनाना, व्यायाम करना, संतुलित भोजन लेना और सकारात्मक दिनचर्या अपनाना जीवन में बड़ा बदलाव ला सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

मधुर वाणी से बनते हैं मजबूत रिश्ते, कटु शब्द पलभर में तोड़ देते हैं वर्षों का विश्वास और अपनापन

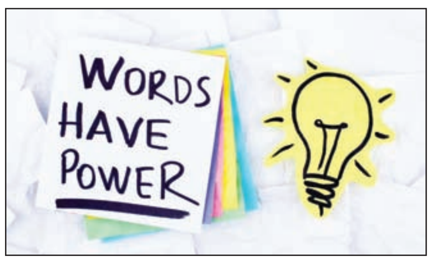

मनुष्य को ईश्वर का दिया हुआ सबसे अनमोल उपहार है। इसी भाषा के माध्यम से हम अपने विचार, भावनाएं और संस्कार एक-दूसरे तक पहुंचाते हैं। कहा भी जाता है कि 'बोल ही मनुष्य की पहचान है।' व्यक्ति कैसा है, उसकी परवरिश कैसी हुई है, उसकी सोच कितनी व्यापक है-यह सब उसकी बोलचाल से ही स्पष्ट हो जाता है। हमारी बोलचाल केवल शब्दों का समूह नहीं है, बल्कि यह हमारे घर, परिवार, समाज और संस्कारों का आईना है।

संस्कार वह बीज हैं जो हमें बचपन से माता-पिता, परिवार और समाज द्वारा दिए जाते हैं। जिस घर में बड़ों का आदर करना, सच बोलना, दूसरों की मदद करना सिखाया जाता है, उस घर के बच्चों की भाषा में भी मिठास और शालीनता दिखाई देती है। इसके विपरीत जिस घर में गाली-गलौज और कटु वचन आम हैं, वहां के लोग अनजाने में ही कठोर भाषा का प्रयोग करने लगते हैं। जब कोई व्यक्ति आपसे पहली बार मिलता है तो वह आपके कपड़े या धन से नहीं, बल्कि आपके दो-चार वाक्यों से प्रभावित होता है। 'कृपया', 'धन्यवाद', 'क्षमा करें', 'आप कैसे हैं' जैसे छोटे-छोटे शब्द हमारे संस्कारों की गहराई बताते हैं। एक सुसंस्कृत व्यक्ति क्रोध में भी अपनी भाषा की मर्यादा नहीं तोड़ता, क्योंकि उसे पता होता है कि शब्द एक बार मुंह से निकल जाएं तो वापस नहीं आते। देवभूमि हिमाचल में आज भी बुजुर्गों के पैर छूकर 'राम राम जी' कहना, पड़ोसी से 'नमस्ते' के साथ हालचाल पूछना आम बात है। यह केवल अभिवादन नहीं है, बल्कि पीढ़ियों से चले आ रहे संस्कारों का प्रतीक है।

मनोवैज्ञानिक भी मानते हैं कि व्यक्ति जो बोलता है, वही सोचता है। नकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर बात में कमी निकालेगा, शिकायत करेगा और ताने देगा। वहीं सकारात्मक सोच वाला व्यक्ति हर स्थिति में उम्मीद और समाधान की बात करेगा। उदाहरण के लिए-बस लेट हो जाए तो एक व्यक्ति बोलेगा 'क्या बेकार सिस्टम है, कुछ नहीं हो सकता'। दूसरा व्यक्ति बोलेगा 'कोई बात नहीं, थोड़ा इंतजार कर लेते हैं, अगली बस पकड़ लेंगे।' दोनों की परिस्थिति एक है, पर बोलचाल अलग है। यहीं से उनकी मानसिकता का पता चलता है। आज सोशल मीडिया के युग में भी यही देखने को मिलता है। कुछ लोग कमेंट में दूसरों का सम्मान करते हैं, प्रोत्साहित करते हैं। वहीं, कुछ लोग छोटी-छोटी बात पर ट्रोलिंग और अपशब्दों का प्रयोग करते हैं। यह सब उनकी अंदर की मानसिकता को दर्शाता है। भारतीय संस्कृति में अभिवादन का विशेष महत्व है। 'नमस्ते', 'राम-राम', 'सलाम', 'सत श्री अकाल' और 'आदाब' जैसे शब्द केवल अभिवादन नहीं, बल्कि सम्मान, प्रेम, अपनापन और अच्छे संस्कारों के प्रतीक हैं। ये हमारी सभ्यता और पारिवारिक मूल्यों को दर्शाते हैं। जब हम किसी का आदरपूर्वक अभिवादन करते हैं, तो संबंधों में मधुरता और विश्वास बढ़ता है तथा वातावरण सकारात्मक बनता है। व्यक्ति की भाषा उसके संस्कार, शिक्षा और मानसिकता का परिचय देती है। मीठी वाणी से कठिन से कठिन कार्य भी सरल हो जाते हैं, जबकि कटु शब्द अच्छे संबंधों को भी तोड़ सकते हैं। संत तुलसीदास ने कहा है- 'ऐसी वाणी बोलिए, मन का आपा खोय। औरन को शीतल करे, आपहु शीतल होय।' यह संदेश आज भी उतना ही प्रासंगिक है।

डॉ. राज कुमारी
साइकोलॉजिस्ट

आधुनिक जीवनशैली और पश्चिमी प्रभाव के कारण हमारी बोलचाल में परिवर्तन आया है। अंग्रेजी बोलना बुरा नहीं है, लेकिन अपनी मातृभाषा, शिष्टाचार और बड़ों के सम्मान को भूलना उचित नहीं। बच्चों में विनम्र भाषा, अभिवादन की आदत और बड़ों का सम्मान करने के संस्कार विकसित करना समय की आवश्यकता है। हमें बोलने से पहले यह अवश्य सोचना चाहिए कि हमारे शब्द किसी को आहत तो नहीं करेंगे। मधुर वाणी, विनम्र व्यवहार और सम्मानजनक भाषा ही सच्चे व्यक्तित्व की पहचान हैं।

(ये लेखिका के निजी विचार हैं)

> **नेकी** कर और दरिया में डाल।
>
> -किस्सा हातिमताई

संपादकीय

बेहतर इलाज की पहली पसंद भारत

भारत आज दुनिया के सबसे तेजी से उभरते मेडिकल टूरिज्म केंद्रों में अपनी मजबूत पहचान बना चुका है। कभी विदेशी मरीजों के लिए केवल कम लागत वाले इलाज का विकल्प माना जाने वाला भारत अब अत्याधुनिक चिकित्सा सुविधाओं, विश्वस्तरीय अस्पतालों, अनुभवी डॉक्टरों और गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं के कारण वैश्विक स्वास्थ्य मानचित्र पर अग्रणी स्थान प्राप्त कर रहा है। वर्ष 2009 में जहां केवल 1.12 लाख विदेशी मरीज इलाज के लिए भारत आए थे, वहीं वर्ष 2025 तक यह संख्या बढ़कर 5.07 लाख से अधिक हो गई। महज सोलह वर्षों में साढ़े चार गुना से अधिक की यह वृद्धि इस बात का प्रमाण है कि भारत चिकित्सा क्षेत्र में तेजी से विश्व का भरोसेमंद केंद्र बन रहा है। विशेषज्ञों का अनुमान है कि वर्ष 2030 तक भारत का मेडिकल टूरिज्म बाजार 1.56 लाख करोड़ रुपये तक पहुंच सकता है। यह उपलब्धि केवल स्वास्थ्य क्षेत्र तक सीमित नहीं है बल्कि देश की अर्थव्यवस्था, रोजगार, विदेशी मुद्रा अर्जन और वैश्विक प्रतिष्ठा को भी नई ऊंचाइयों तक ले जाने की क्षमता रखती है।

भारत की सबसे बड़ी ताकत उसकी उत्कृष्ट चिकित्सा विशेषज्ञता और कुशल मानव संसाधन हैं। देश में हृदय रोग, कैंसर, न्यूरोलॉजी, ऑर्थोपेडिक्स, अंग प्रत्यारोपण, नेत्र चिकित्सा, प्लास्टिक सर्जरी, आईवीएफ और रोबोटिक सर्जरी जैसे जटिल उपचार विश्वस्तरीय गुणवत्ता के साथ उपलब्ध हैं। भारतीय डॉक्टरों की दक्षता और अनुभव पूरी दुनिया में सम्मानित हैं। बड़ी संख्या में भारतीय चिकित्सक विदेशों के प्रतिष्ठित संस्थानों में प्रशिक्षण प्राप्त कर चुके हैं और आधुनिक चिकित्सा तकनीकों में पारंगत हैं। यही कारण है कि गंभीर बीमारियों से जूझ रहे मरीज भी भारत आकर उपचार कराने में विश्वास दिखा रहे हैं।

भारत में चिकित्सा सेवाओं की लागत विकसित देशों की तुलना में काफी कम है। अमेरिका, ब्रिटेन और यूरोप के कई देशों में जिन सर्जरी और उपचारों पर लाखों रुपये अधिक खर्च होते हैं, वही सुविधाएं भारत में अपेक्षाकृत कम लागत पर उपलब्ध हैं। कम खर्च का अर्थ गुणवत्ता में कमी नहीं है। भारत के अनेक अस्पताल अंतरराष्ट्रीय मानकों के अनुरूप सेवाएं प्रदान करते हैं और आधुनिक मशीनों, उन्नत प्रयोगशालाओं तथा अत्याधुनिक ऑपरेशन थिएटरों से सुसज्जित हैं। कम लागत, बेहतर गुणवत्ता और कम प्रतीक्षा अवधि का यह संयोजन विदेशी मरीजों को भारत की ओर आकर्षित कर रहा है।

भारत की चिकित्सा व्यवस्था की एक और विशेषता यह है कि यहां जांच, निदान और उपचार की प्रक्रिया अपेक्षाकृत तेज होती है। कई विकसित देशों में मरीजों को सर्जरी के लिए महीनों तक प्रतीक्षा करनी पड़ती है, जबकि भारत में आवश्यक जांच और उपचार कम समय में उपलब्ध हो जाते हैं। इससे गंभीर रोगों के इलाज में देरी नहीं होती और मरीजों का समय तथा धन दोनों बचते हैं। अस्पतालों में बहुभाषी सहायता सेवाएं, अंतरराष्ट्रीय मरीज समन्वय केंद्र और उपचार से पहले लागत की स्पष्ट जानकारी भी विदेशी मरीजों का विश्वास बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही हैं।

भारत केवल आधुनिक एलोपैथिक चिकित्सा तक सीमित नहीं है। आयुर्वेद, योग, प्राकृतिक चिकित्सा, सिद्ध, यूनानी और होम्योपैथी जैसी पारंपरिक चिकित्सा प्रणालियां भी दुनिया भर के लोगों को आकर्षित कर रही हैं। अनेक विदेशी मरीज आधुनिक चिकित्सा के साथ आयुर्वेदिक उपचार, योग और प्राकृतिक चिकित्सा का लाभ भी लेना चाहते हैं। इससे भारत की समग्र स्वास्थ्य प्रणाली को वैश्विक स्तर पर नई पहचान मिल रही है। स्वास्थ्य पर्यटन और वेलनेस टूरिज्म के बढ़ते चलन ने भी भारत की लोकप्रियता में उल्लेखनीय वृद्धि की है।

सरकार ने मेडिकल टूरिज्म को बढ़ावा देने के लिए कई महत्वपूर्ण कदम उठाए हैं। 172 देशों के नागरिकों के लिए ई-मेडिकल वीजा की सुविधा, मरीजों के साथ आने वाले परिजनों के लिए ई-मेडिकल अटेंडेंट वीजा और आयुर्वेद तथा अन्य पारंपरिक चिकित्सा पद्धतियों के लिए ई-आयुष वीजा जैसी व्यवस्थाओं ने भारत को विदेशी मरीजों के लिए अधिक सुविधाजनक बना दिया है। इसके अतिरिक्त 'हील इन इंडिया' अभियान के माध्यम से देश को वैश्विक चिकित्सा केंद्र के रूप में विकसित करने का प्रयास किया जा रहा है। इस पहल का उद्देश्य विश्वस्तरीय स्वास्थ्य सेवाओं को एकीकृत करना, उपचार प्रक्रिया को सरल बनाना और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर भारत की चिकित्सा क्षमता का प्रभावी प्रचार करना है।

मेडिकल टूरिज्म के विस्तार से देश की अर्थव्यवस्था को भी व्यापक लाभ मिल रहा है। विदेशी मरीज केवल अस्पतालों तक सीमित नहीं रहते बल्कि होटल, परिवहन, पर्यटन, दवा उद्योग, चिकित्सा उपकरण, खानपान और स्थानीय सेवाओं पर भी खर्च करते हैं। इससे प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रूप से लाखों लोगों को रोजगार मिलता है। अस्पतालों में डॉक्टरों, नर्सों, तकनीशियनों और अन्य स्वास्थ्य कर्मियों की मांग बढ़ती है, वहीं पर्यटन और आतिथ्य उद्योग को भी नई गति मिलती है।

-शिवांश धाकड़

सखी सावन क्यों बहका रे

कविता

वीरेंद्र शर्मा वात्स्यायन, सेवानिवृत्त प्रवक्ता
ऊना (हिमाचल प्रदेश)

सखी आज सावन क्यों बहका रे, पेड़ों पर क्यों पड़े झूले अरे सखी
हंस रहीं उन्मुक्त समस्त बालाएं, आसमान झमाझम है बरस रहा
तड़ित चमककर है डरा रही, बादलों की घोर गर्जना सुनकर
अरे सखी सावन क्यों बहका रे, पानी की बूंदों पर चढ़ा खुमार
बाग महकने से लगे ....फूल सुगंधि बिखरने लगे
आ गया सावन का त्योहार, मेले लग रहे बेशुमार........
कलियों पर आई बहार, भंवरों की गुंजार सुन
कोयल टेरने लगी, मेघों को हेरने लगी
सखी सावन क्यों बहका रे ? विरह की रात ......
विरहन की आंखों में, आशाओं की बहार आने लगी
यौवन अंगड़ाई लेने लगी, तन मन महकने लगा
सावन बहकने लगा !

जब एरिस की खोज ने सौरमंडल की परिभाषा बदल दी और प्लूटो बन गया बौना ग्रह

29 जुलाई 2005 आधुनिक खगोल विज्ञान के इतिहास में एक अत्यंत महत्वपूर्ण दिन माना जाता है। इसी दिन खगोलविदों ने सौरमंडल के बाहरी क्षेत्र में स्थित एक विशाल खगोलीय पिंड **एरिस** की खोज की औपचारिक घोषणा की। यह खोज अमेरिका के पालोमर वेधशाला में कार्यरत खगोलविद **माइकल ई. ब्राउन**, **चैड ट्रूजिलो** और **डेविड रैबिनोविट्ज़** की टीम ने की थी। एरिस आकार और द्रव्यमान के मामले में प्लूटो के बराबर या उससे भी बड़ा प्रतीत हुआ। इस खोज ने वैज्ञानिकों के सामने एक महत्वपूर्ण प्रश्न खड़ा कर दिया कि यदि प्लूटो को ग्रह माना जाता है तो एरिस को भी ग्रह माना जाना चाहिए या फिर ग्रह की परिभाषा पर नए सिरे से विचार किया जाना चाहिए।

एरिस सूर्य से बहुत अधिक दूरी पर स्थित **काइपर बेल्ट** और उससे आगे के बिखरे हुए क्षेत्र का एक प्रमुख पिंड है। इसकी कक्षा अत्यंत लंबी और अंडाकार है तथा यह सूर्य की एक परिक्रमा पूरी करने में लगभग 557 वर्ष का समय लेता है। एरिस के साथ उसके छोटे उपग्रह **डिस्नोमिया** की भी खोज हुई जिससे वैज्ञानिकों को उसके द्रव्यमान का सटीक अनुमान लगाने में सहायता मिली। अध्ययन से स्पष्ट हुआ कि एरिस प्लूटो से अधिक भारी है और उसकी सतह बर्फ से ढकी हुई है।

एरिस की खोज ने पूरी दुनिया के खगोल वैज्ञानिकों के बीच व्यापक बहस छेड़ दी। कई वर्षों तक यह चर्चा चलती रही कि ग्रह किसे कहा जाए और किन विशेषताओं के आधार पर किसी खगोलीय पिंड को ग्रह का दर्जा दिया जाए। अंततः वर्ष 2006 में **अंतरराष्ट्रीय खगोलीय संघ** ने ग्रह की नई और स्पष्ट परिभाषा निर्धारित की। इस परिभाषा के अनुसार किसी खगोलीय पिंड को ग्रह कहलाने के लिए सूर्य की परिक्रमा करना, अपने गुरुत्वाकर्षण के कारण लगभग गोल आकार प्राप्त करना और अपनी कक्षा के आसपास के अन्य पिंडों को हटाकर उस क्षेत्र पर अपना प्रभुत्व स्थापित करना आवश्यक माना गया।

धर्म देवा, प्रशिक्षित स्नातक शिक्षक
गांव धारना, जिला चंबा

नई परिभाषा के आधार पर प्लूटो तीसरी शर्त को पूरा नहीं कर सका क्योंकि उसकी कक्षा के आसपास अनेक अन्य बर्फीले पिंड मौजूद हैं। इसी कारण प्लूटो को ग्रहों की सूची से हटाकर **बौने ग्रह** की श्रेणी में शामिल कर दिया गया। एरिस को भी इसी श्रेणी में रखा गया। इस निर्णय ने दुनिया भर में विज्ञान प्रेमियों और विद्यार्थियों के बीच नई जिज्ञासा पैदा की क्योंकि दशकों तक नौ ग्रहों के रूप में पढ़ाया जाने वाला सौरमंडल अब आठ प्रमुख ग्रहों तक सीमित हो गया।

एरिस की खोज केवल एक नए खगोलीय पिंड की पहचान भर नहीं थी बल्कि इसने वैज्ञानिक सोच और अनुसंधान की दिशा को भी बदल दिया। इसके बाद सौरमंडल के दूरस्थ क्षेत्रों में अनेक अन्य बौने ग्रहों और छोटे खगोलीय पिंडों की खोज को गति मिली। वैज्ञानिकों को यह समझने का अवसर मिला कि सौरमंडल पहले की तुलना में कहीं अधिक विशाल और जटिल है तथा इसके बाहरी हिस्सों में अभी भी अनेक रहस्य छिपे हुए हैं।

आज एरिस की खोज को खगोल विज्ञान की सबसे प्रभावशाली घटनाओं में गिना जाता है। इसने यह सिद्ध किया कि विज्ञान लगातार विकसित होने वाली प्रक्रिया है और नई खोजें वर्षों से स्थापित धारणाओं को भी बदल सकती हैं। 29 जुलाई 2005 इसलिए इतिहास में उस दिन के रूप में दर्ज है जब एक नई खोज ने ग्रहों की परिभाषा बदल दी और मानव की अंतरिक्ष संबंधी समझ को एक नया आयाम प्रदान किया।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

बंजर होती उपजाऊ भूमि और खाली होते गांव हिमाचल के कृषि भविष्य के लिए बड़ी चेतावनी

हिमाचल प्रदेश में आजकल एक गंभीर चुनौती हमारे सामने खड़ी है-ग्रामीण क्षेत्रों से युवाओं का तेजी से औद्योगिक क्षेत्रों और महानगरों की ओर पलायन। रोजगार, बेहतर शिक्षा, स्वास्थ्य सुविधाओं और आधुनिक जीवन की तलाश में गांवों से युवा लगातार शहरों की ओर जा रहे हैं। यह स्वाभाविक भी है, क्योंकि प्रत्येक युवा अपने बेहतर भविष्य का सपना देखता है, किंतु इस पलायन का दूसरा पक्ष अत्यंत चिंताजनक है।

गांवों में खेती और बागवानी करने वाले हाथ कम होते जा रहे हैं। परिणामस्वरूप हजारों हेक्टेयर उपजाऊ भूमि आज बंजर होती जा रही है। जिन खेतों में कभी धान, मक्का, गेहूं और सब्जियां लहलहाती थीं, जहां फलों के बाग प्रदेश की अर्थव्यवस्था को मजबूती देते थे, वहां आज झाड़ियां और वीरानी दिखाई देने लगी हैं। यदि यही स्थिति बनी रही तो आने वाले वर्षों में हिमाचल की कृषि और बागवानी आधारित अर्थव्यवस्था पर गंभीर प्रभाव पड़ सकता है। केवल भूमि का बंजर होना ही चिंता का विषय नहीं है, बल्कि इससे खाद्य सुरक्षा, पर्यावरण संरक्षण, ग्रामीण संस्कृति और स्थानीय अर्थव्यवस्था भी प्रभावित होगी।

समय की मांग है कि सरकार, कृषि और बागवानी विभाग मिलकर व्यापक और व्यवहारिक रणनीति तैयार करें। किसानों और विशेष रूप से युवाओं को नवीनतम कृषि तकनीकों, आधुनिक मशीनों, गुणवत्तायुक्त एवं उन्नत बीजों, उच्च गुणवत्ता वाले पौधों तथा वैज्ञानिक खेती की जानकारी बड़े पैमाने पर उपलब्ध कराई जाए। केवल योजनाएं बनाना पर्याप्त नहीं है, बल्कि उन्हें गांव-गांव तक प्रभावी ढंग से पहुंचाना भी आवश्यक है।

कृषि और बागवानी को लाभकारी एवं सम्मानजनक व्यवसाय बनाने के लिए प्रशिक्षण शिविर, प्रदर्शन खेत, मोबाइल तकनीकी दल, डिजिटल सलाह, प्रसंस्करण इकाइयां, शीत भंडारण, बेहतर विपणन व्यवस्था और उचित मूल्य सुनिश्चित करने की दिशा में ठोस प्रयास किए जाने चाहिए। यदि आधुनिक तकनीक और वैज्ञानिक सोच को स्थानीय अनुभव के साथ जोड़ा जाए, तो हिमाचल का युवा खेती और बागवानी को भी एक सफल उद्यम के रूप में अपना सकता है। आज आवश्यकता स्मार्ट खेती और वैज्ञानिक बागवानी की है। जब युवाओं को यह विश्वास होगा कि आधुनिक कृषि से सम्मानजनक आय, आत्मनिर्भरता और उज्ज्वल भविष्य प्राप्त किया जा सकता है, तब पलायन की गति स्वतः कम होगी।

रोजगार, शिक्षा और बेहतर सुविधाओं की तलाश में युवाओं का गांवों से पलायन बढ़ रहा है, जिसका सबसे बड़ा दुष्प्रभाव हिमाचल की कृषि और बागवानी पर पड़ रहा है। खेत खाली हो रहे हैं और उपजाऊ भूमि धीरे-धीरे बंजर बनती जा रही है। बढ़ती खेती लागत, अनिश्चित बाजार, जलवायु परिवर्तन, जंगली जानवरों से फसलों की क्षति तथा आधुनिक तकनीकों की कमी ने इस समस्या को और गंभीर बना दिया है। इस चुनौती से निपटने के लिए सरकार को आधुनिक खेती, उन्नत बीज, सिंचाई, यंत्रीकरण, प्रशिक्षण, प्रसंस्करण, शीत भंडारण और बेहतर विपणन व्यवस्था को गांव-गांव तक पहुंचाना होगा। साथ ही कृषि और बागवानी को शिक्षा, तकनीक और उद्यमिता से जोड़कर युवाओं को स्टार्टअप तथा मूल्य संवर्धन के अवसर उपलब्ध कराने होंगे। हिमाचल की उपजाऊ भूमि केवल उत्पादन का साधन नहीं, बल्कि हमारी संस्कृति और आने वाली पीढ़ियों की अमूल्य धरोहर है।

विशाल कल्याण, सहायक प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन यूनिवर्सिटी, सोलन

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

वर्षा का महत्व समझें और जल संरक्षण अपनाएं प्रकृति के अमूल्य उपहार को बचाने का लें संकल्प

विश्व वर्षा दिवस का उद्देश्य वर्षा के महत्व और जल संरक्षण के प्रति लोगों में जागरूकता बढ़ाना है। यद्यपि यह दिवस किसी एक अंतरराष्ट्रीय संस्था द्वारा आधिकारिक रूप से मान्यता प्राप्त वैश्विक दिवस नहीं है लेकिन कई सामाजिक संगठन शिक्षण संस्थान और पर्यावरण से जुड़ी संस्थाएं इसे वर्षा के महत्व को समझाने के लिए मनाती हैं। पृथ्वी पर जीवन का आधार जल है और जल का सबसे बड़ा प्राकृतिक स्रोत वर्षा है। यदि समय पर पर्याप्त वर्षा न हो तो खेती पीने के पानी उद्योग बिजली उत्पादन और प्राकृतिक संतुलन सभी प्रभावित होते हैं। इसलिए वर्षा केवल एक प्राकृतिक घटना नहीं बल्कि जीवन का आधार है।

भारत जैसे कृषि प्रधान देश में वर्षा का विशेष महत्व है। देश की बड़ी आबादी आज भी खेती पर निर्भर है और खेती का अधिकांश हिस्सा मानसून की वर्षा पर आधारित है। अच्छी वर्षा होने पर फसलें लहलहाती हैं किसानों की आय बढ़ती है और देश की अर्थव्यवस्था को मजबूती मिलती है। इसके विपरीत कम वर्षा होने पर सूखे की स्थिति उत्पन्न होती है जिससे खेती प्रभावित होती है और खाद्यान्न उत्पादन घट जाता है। यही कारण है कि भारत में मानसून को जीवनदायिनी ऋतु कहा जाता है।

वर्षा केवल खेती के लिए ही आवश्यक नहीं है बल्कि नदियों झीलों तालाबों और भूजल स्रोतों को भी पुनर्जीवित करती है। वर्षा का पानी धरती के भीतर जाकर भूजल स्तर को बढ़ाता है जिससे कुएं हैंडपंप और ट्यूबवेल लंबे समय तक पानी उपलब्ध करा पाते हैं। यदि लगातार वर्षा कम हो तो भूजल स्तर नीचे चला जाता है और पेयजल संकट गहरा जाता है। आज देश के अनेक शहरों और गांवों में गर्मियों के दौरान पानी की कमी इसी कारण देखने को मिलती है।

जलवायु परिवर्तन के कारण वर्षा का स्वरूप तेजी से बदल रहा है। कहीं बहुत अधिक वर्षा हो रही है तो कहीं लंबे समय तक सूखा पड़ रहा है। कई क्षेत्रों में अचानक बादल फटने की घटनाएं बढ़ी हैं जिससे बाढ़ और भूस्खलन जैसी प्राकृतिक आपदाएं आती हैं। वहीं दूसरी ओर कुछ इलाकों में पर्याप्त वर्षा नहीं होने से जल संकट गहराता जा रहा है। वैज्ञानिकों का मानना है कि बढ़ते तापमान और पर्यावरण प्रदूषण के कारण मौसम का संतुलन प्रभावित हो रहा है। ऐसे में वर्षा के जल का संरक्षण पहले से कहीं अधिक आवश्यक हो गया है।

आज सबसे बड़ी चुनौती यह है कि वर्षा का अधिकांश पानी बिना उपयोग के नदियों के माध्यम से समुद्र में चला जाता है। यदि इस पानी को वैज्ञानिक ढंग से संग्रहित किया जाए तो आने वाले समय में पानी की कमी को काफी हद तक दूर किया जा सकता है। वर्षा जल संचयन अर्थात रेन वाटर हार्वेस्टिंग इसका सबसे प्रभावी उपाय माना जाता है। घरों स्कूलों कार्यालयों और सार्वजनिक भवनों की छतों से गिरने वाले वर्षा जल को पाइपों के माध्यम से टैंकों या भूमिगत संरचनाओं में एकत्र किया जा सकता है। इससे भूजल स्तर बढ़ता है और भविष्य के लिए पानी सुरक्षित रहता है।

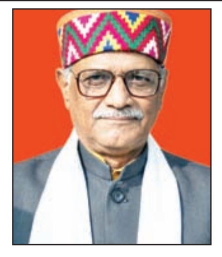

रामलाल पाठक
निहारखन बासला, ब्रह्मपुखर
बिलासपुर (हि.प्र.)

भारत सरकार और विभिन्न राज्य सरकारें भी जल संरक्षण को बढ़ावा देने के लिए अनेक योजनाएं चला रही हैं। जल शक्ति अभियान अमृत सरोवर योजना और कैच द रेन जैसे अभियान लोगों को वर्षा जल संचयन और जल संरक्षण के लिए प्रेरित कर रहे हैं। इन अभियानों के माध्यम से गांवों और शहरों में तालाबों का पुनर्जीवन चेक डैम निर्माण और जल स्रोतों के संरक्षण पर विशेष ध्यान दिया जा रहा है। यदि समाज और सरकार मिलकर प्रयास करें तो जल संकट की समस्या को काफी हद तक कम किया जा सकता है।

(ये लेखक के निजी विचार हैं)

व्यक्तित्व विशेष

बॉलीवुड के दमदार अभिनेता

संजय दत्त का जन्म 29 जुलाई 1959 को मुंबई में हुआ था। वह दिग्गज अभिनेता सुनील दत्त और प्रसिद्ध अभिनेत्री नर्गिस के पुत्र हैं। फिल्मी माहौल में पले बढ़े संजय दत्त ने बचपन से ही अभिनय की दुनिया को करीब से देखा। उन्होंने बाल कलाकार के रूप में फिल्म **रेशमा और शेरा** में छोटी भूमिका निभाई थी लेकिन मुख्य अभिनेता के रूप में उनकी पहली फिल्म **रॉकी** वर्ष 1981 में रिलीज हुई। इस फिल्म ने उन्हें रातोंरात स्टार बना दिया और दर्शकों ने उनके अभिनय को खूब सराहा।

संजय दत्त
जन्म : 29 जुलाई 1959

संजय दत्त का फिल्मी सफर जितना सफल रहा उतना ही उतार चढ़ाव से भी भरा रहा। अपने करियर के दौरान उन्होंने कई सुपरहिट फिल्मों में काम किया जिनमें साजन, खलनायक, वास्तव,मुन्नाभाई एमबीबीएस, लगे रहो मुन्नाभाई, अग्निपथ, केजीएफ चैप्टर 2 और शमशेरा जैसी फिल्में शामिल हैं। उन्होंने रोमांटिक नायक से लेकर एक्शन हीरो और गंभीर किरदारों तक हर भूमिका को प्रभावशाली ढंग से निभाया। खास तौर पर मुन्नाभाई का उनका किरदार भारतीय सिनेमा के सबसे लोकप्रिय पात्रों में गिना जाता है।

संजय दत्त का निजी जीवन कई कठिन दौर से गुजरा। नशे की लत से संघर्ष हो या कानूनी मामलों का सामना करना हो उन्होंने हर चुनौती का डटकर मुकाबला किया। वर्ष 1993 के मुंबई बम धमाकों से जुड़े मामले में उन्हें कानूनी प्रक्रिया का सामना करना पड़ा और जेल भी जाना पड़ा। इसके बावजूद उन्होंने हार नहीं मानी और जीवन में दोबारा मजबूती के साथ वापसी की। उनका संघर्ष अनेक लोगों के लिए प्रेरणा का स्रोत माना जाता है क्योंकि उन्होंने विपरीत परिस्थितियों में भी अपने आत्मविश्वास और मेहनत को नहीं छोड़ा।

संजय दत्त को उनके प्रशंसक प्यार से संजू बाबा भी कहते हैं। आज भी उनकी लोकप्रियता पहले की तरह बनी हुई है और युवा पीढ़ी भी उनके अभिनय की प्रशंसक है। बड़े पर्दे पर उनका प्रभावशाली व्यक्तित्व और संवाद बोलने की अनोखी शैली उन्हें अन्य अभिनेताओं से अलग पहचान दिलाती है।

'भारतेन्दु शिखर

प्रकाशक, मुद्रक, संपादक एवं स्वामी शिवांश धाकड़ द्वारा शर्मा भवन, न्यू रणजीत नगर, एप्पल फ्रूट मंडी, नजदीक ढली टनल, शिमला (हि.प्र.) 171006 से प्रकाशित एवं बायोसर्ट इंटरनेशनल प्रा. लि. प्लॉट नंबर 8, फेज-2 इंडस्ट्रियल एरिया, नगरोटा बगवां, जिला कांगड़ा (हि.प्र.), पिन नंबर-176047 से मुद्रित। समस्त समाचारों के चयन एवं संपादन के लिए पीआरबी एक्ट के अंतर्गत उत्तरदायी तथा इनसे उत्पन्न समस्त विवाद शिमला न्यायालय के अधीन होंगे।

आरएनआई संदर्भ संख्या-HPHIN/2000/02437
ई-मेल : bhartendunewsmedia@gmail.com, फोन नंबर : 88946-77702

न्यूज ब्रीफ

संत रविदास की 650वीं जयंती के उपलक्ष्य में देशभर में समरसता यात्राएं निकालेगी विहिप

एजेंसी, लखनऊ। संत शिरोमणि रविदास की 650वीं जयंती वर्ष के अवसर पर विश्व हिन्दू परिषद (विहिप) देशभर में विभाग स्तर पर समरसता यात्राओं का आयोजन करेगी। विहिप के केंद्रीय मंत्री देवजी भाई रावत ने बताया कि इन यात्राओं के माध्यम से संत रविदास के सामाजिक समरसता, समानता और आध्यात्मिकता के संदेश को समाज तक पहुंचाया जाएगा। उन्होंने कहा कि संत रविदास से जुड़े स्थानों और मंदिरों से यात्राएं निकाली जाएंगी। संतों की पदयात्राओं के साथ प्रखंड स्तर पर समरसता सहभोज भी आयोजित होंगे। अवध प्रांत में 27 सितंबर से चार अक्टूबर तक यात्रा प्रस्तावित है। वहीं विहिप 22 नवंबर से 13 दिसंबर तक सदस्यता अभियान चलाएगी, जिसमें दो करोड़ से अधिक सदस्य बनाने का लक्ष्य रखा गया है। संगठन अशोक सिंघल की जन्म शताब्दी वर्ष पर भी विभिन्न कार्यक्रम आयोजित करेगा।

गुरुओं की तपोभूमि को संवार रही सरकार संत स्थलों का हो रहा कायाकल्प

एजेंसी, लखनऊ। उत्तर प्रदेश सरकार आध्यात्मिक पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए संतों, ऋषियों और गुरुओं से जुड़े तीर्थ स्थलों के संरक्षण और विकास पर काम कर रही है। गुरु पूर्णिमा के अवसर पर प्रदेश की समृद्ध गुरु परंपरा को याद करते हुए विभिन्न परियोजनाओं को गति दी जा रही है। सरकार द्वारा संत रविदास की जन्मस्थली वाराणसी के सीर गोवर्धन धाम, देवरिया स्थित देवरहा बाबा आश्रम और गुरु गोरखनाथ से जुड़े स्थलों के विकास कार्य कराए जा रहे हैं। इसके अलावा कई ऋषि आश्रमों, तपोस्थलों और धार्मिक स्थलों के सौंदर्यीकरण के लिए भी योजनाएं संचालित हैं। इन परियोजनाओं का उद्देश्य सांस्कृतिक विरासत को सुरक्षित रखने के साथ धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा देना है। इससे श्रद्धालुओं को बेहतर सुविधाएं मिलेंगी और नई पीढ़ी संतों एवं गुरुओं की ज्ञान परंपरा से जुड़ सकेगी।

रोडवेज का फैसला, मुरादाबाद-हरियाणा रूट पर चलेंगी अतिरिक्त बसें

एजेंसी, मुरादाबाद। उत्तर प्रदेश के मुरादाबाद से हरियाणा जाने वाले यात्रियों के लिए राहत भरी खबर है। परिवहन निगम इस रूट पर दो अतिरिक्त रोडवेज बसें चलाने की तैयारी कर रहा है। वर्तमान में मुरादाबाद डिपो से हरियाणा के लिए केवल एक बस संचालित हो रही है, जिससे यात्रियों को भीड़ और सीटों की कमी का सामना करना पड़ता है।

यात्रियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए परिवहन निगम ने दो नई बसों के संचालन का प्रस्ताव तैयार किया है। मुरादाबाद रोडवेज परिक्षेत्र की सहायक क्षेत्रीय प्रबंधक राजवती ने बताया कि नई बसें शुरू होने से यात्रियों को समय पर सुविधा मिलेगी और भीड़ कम होगी। मुख्यालय से मंजूरी मिलते ही बसों का संचालन शुरू कर दिया जाएगा।

प्लॉट में मिला युवक का शव, पास से शराब और बीयर कैन बरामद

एजेंसी, औरैया। उत्तर प्रदेश के औरैया जिले में एक युवक का शव मिलने से इलाके में सनसनी फैल गई। फफूंद-औरैया मार्ग पर सहाय आलमपुर गांव जाने वाले कट के सामने मंगलवार दोपहर राहगीरों ने एक प्लॉट में युवक का शव पड़ा देखा। सूचना मिलने पर फफूंद थाना पुलिस मौके पर पहुंची और शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया। पुलिस को घटनास्थल से मृतक के पास एक कीपैड मोबाइल फोन, शराब का क्वार्टर, बीयर की खाली कैन और जूते मिले। बाद में मृतक की पहचान मुरादगंज क्षेत्र के पूर्वा डेरा निवासी चंद्रशेखर के रूप में हुई। थानाध्यक्ष अजय कुमार ने बताया कि मौत का कारण अभी स्पष्ट नहीं है। पोस्टमार्टम रिपोर्ट के बाद स्थिति साफ होगी। पुलिस मामले की जांच कर रही है। पुलिस ने आसपास के लोगों से पूछताछ शुरू कर दी है और घटनास्थल से मिले सभी साक्ष्यों को जांच में शामिल किया जा रहा है। अधिकारियों का कहना है कि हर पहलू को ध्यान में रखकर मामले की पड़ताल की जा रही है। परिजनों से भी जानकारी जुटाई जा रही है, ताकि युवक की मौत के कारणों का पता लगाया जा सके।

लखनऊ में विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरकर पूर्व राज्यमंत्री की मौत

भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री थे नानक चंद्र भुर्जी, घटना से शोक की लहर

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में मंगलवार को एक दर्दनाक घटना सामने आई, जहां पूर्व राज्यमंत्री और भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री नानक चंद्र भुर्जी की विधायक निवास की सातवीं मंजिल से गिरने के बाद मौत हो गई। घटना हजरतगंज थाना क्षेत्र स्थित दारूलशफा नए विधायक निवास की बताई जा रही है। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर मामले की जांच शुरू कर दी है।

पुलिस के अनुसार, दारूलशफा नए विधायक निवास के व्यवस्था अधिकारी ने हजरतगंज पुलिस को सूचना दी थी कि विधायक निवास की सातवीं मंजिल से एक व्यक्ति गिरकर गंभीर रूप से घायल हो गया है। सूचना मिलने के बाद पुलिस टीम तत्काल मौके पर पहुंची और घायल नानक चंद्र भुर्जी को उपचार के लिए सिविल अस्पताल ले जाया गया। हालांकि डॉक्टरों ने जांच के बाद उन्हें मृत घोषित कर दिया।

घटना के बाद पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

पुलिस अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच सभी संभावित पहलुओं को ध्यान में रखकर की जा रही है। घटनास्थल का निरीक्षण किया गया है और वहां मौजूद लोगों से पूछताछ कर जानकारी जुटाई जा रही है। प्रारंभिक जांच में पुलिस को जानकारी मिली है कि नानक चंद्र भुर्जी पिछले कुछ समय से मानसिक तनाव और अवसाद से गुजर रहे थे। पुलिस इस पहलू को भी जांच में शामिल कर रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि घटना के वास्तविक कारणों का पता विस्तृत जांच और साक्ष्यों के आधार पर ही लगाया जा सकेगा।

घटना की जानकारी मिलते ही पुलिस ने उनके परिवार को सूचित कर दिया। परिजनों से बातचीत कर घटना से जुड़े अन्य तथ्यों की जानकारी जुटाई जा रही है। पुलिस ने बताया कि सभी जरूरी कानूनी प्रक्रियाएं पूरी की जा रही हैं। नानक चंद्र भुर्जी भारतीय जनता पार्टी से जुड़े वरिष्ठ नेता थे। वह भाजपा ओबीसी मोर्चा के प्रदेश मंत्री के पद पर कार्यरत थे। इससे पहले वह उत्तर प्रदेश सरकार में राज्यमंत्री की जिम्मेदारी भी संभाल चुके थे। उनके निधन की खबर सामने आने के बाद राजनीतिक क्षेत्र में शोक की लहर दौड़ गई।

पुलिस अधिकारियों के मुताबिक, घटना को लेकर जल्दबाजी में किसी निष्कर्ष पर नहीं पहुंचा जा रहा है। जांच टीम हर पहलू की बारीकी से पड़ताल कर रही है। घटनास्थल के आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा सकती है, ताकि पूरी घटना की स्थिति स्पष्ट हो सके। हजरतगंज पुलिस ने बताया कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है और परिवार तथा संबंधित लोगों से जानकारी एकत्र की जा रही है। अधिकारियों ने कहा कि जांच पूरी होने के बाद ही घटना की वास्तविक वजह सामने आ पाएगी।

महिला की एफडी से आठ लाख रुपए गायब, बैंक अधिकारियों पर उठे सवाल

एजेंसी, नोएडा

साइबर क्राइम थाना क्षेत्र में एक महिला ने बैंक मैनेजर और कर्मचारियों पर धोखाधड़ी कर उसकी एफडी तोड़कर आठ लाख रुपये निकालने का आरोप लगाया है। पीड़िता की शिकायत पर पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार, ग्राम कुरैब निवासी गोल्डी ने साइबर क्राइम थाने में शिकायत दी है। महिला ने बताया कि उसने जेवर स्थित इंडसइंड बैंक शाखा में अपना खाता खुलवाया था।

बैंक मैनेजर पर धोखाधड़ी का गंभीर आरोप

उसने पांच अप्रैल को बैंक में 30 लाख रुपये की एफडी कराई थी। आरोप है कि बैंक के मैनेजर और अन्य कर्मचारियों ने उसकी अनुमति के बिना एफडी को तोड़ दिया और खाते से आठ लाख रुपये निकाल लिए। महिला का कहना है कि जब उसे खाते से रकम निकाले जाने की जानकारी मिली तो उसने बैंक मैनेजर से इसकी शिकायत की। आरोप है कि इस दौरान मैनेजर ने उसके साथ सही व्यवहार नहीं किया और बदसलूकी की। साइबर क्राइम थाना पुलिस ने महिला की शिकायत के आधार पर रिपोर्ट दर्ज कर ली है। पुलिस अधिकारियों का कहना है कि मामले की जांच की जा रही है और बैंक रिकॉर्ड समेत अन्य दस्तावेजों की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस यह भी पता लगा रही है कि एफडी तोड़ने और रकम निकालने की प्रक्रिया में किन कर्मचारियों की भूमिका रही। जांच के बाद आरोपों की स्थिति स्पष्ट होगी।

पुलिस टीम मामले की सभी पहलुओं से जांच कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि शिकायत में लगाए गए आरोपों की पुष्टि के लिए बैंक अधिकारियों और कर्मचारियों से भी पूछताछ की जा सकती है। इसके अलावा एफडी से संबंधित दस्तावेज, ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड और बैंक की आंतरिक प्रक्रिया की जांच की जाएगी। जांच में यदि किसी की भूमिका सामने आती है तो उसके खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी।

लोन दिलाने का भरोसा देकर बुजुर्ग से हड़पे 53 लाख

एजेंसी, नोएडा

उत्तर प्रदेश के गौतमबुद्धनगर जिले में साइबर ठगी का एक बड़ा मामला सामने आया है। थाना साइबर क्राइम में एक बुजुर्ग व्यक्ति ने शिकायत दर्ज कराई है कि लोन दिलाने का झांसा देकर उनसे 53 लाख 15 हजार 930 रुपये की ठगी कर ली गई।

नोएडा के सेक्टर-119 स्थित आम्रपाली प्लेटिनम सोसाइटी निवासी 67 वर्षीय सुभाषित सरकार ने पुलिस को बताया कि उन्हें निजी कारणों से लोन की जरूरत थी। उम्र अधिक होने के कारण सरकारी बैंक से उन्हें लोन नहीं मिल पा रहा था। इसके बाद उन्होंने निजी बैंक से लोन लेने का प्रयास शुरू किया। इसी दौरान सोशल मीडिया के माध्यम से उनकी बातचीत मुनव्वर हुड्डा नामक व्यक्ति से हुई। आरोपी ने 12 प्रतिशत

सोशल मीडिया संपर्क बना ठगी का कारण बुजुर्ग हुआ शिकार, उड़ाई लाखों की रकम

वार्षिक ब्याज दर पर निजी बैंक से जल्द लोन दिलाने का भरोसा दिया। इसके बाद आरोपी ने अलग-अलग बहानों से कई बार में पीड़ित से कुल 53 लाख 15 हजार 930 रुपये अपने खातों में ट्रांसफर करवा लिए।

बाजरा लदी ट्रैक्टर ट्रॉली खाई में पलटी, किसान की मौत

एजेंसी, हाथरस। उत्तर प्रदेश के हाथरस जिले में सोमवार रात हुए सड़क हादसे में एक किसान की मौत हो गई, जबकि चार अन्य किसान घायल हो गए। हादसा थाना रिफाइनरी क्षेत्र के मथुरा-बरेली हाईवे पर हुआ। घायलों में तीन की हालत गंभीर बताई जा रही है, जिन्हें बेहतर इलाज के लिए आगरा और दिल्ली रेफर किया गया है। जानकारी के अनुसार, सादाबाद क्षेत्र के गांव सरौंठ निवासी सुक्खन सिंह अपने भाई हरपाल सिंह, रणधीर सिंह, लाखन सिंह और बघेना निवासी चंद्रवीर सिंह के साथ ट्रैक्टर-ट्रॉली में बाजरा लादकर भरतपुर मंडी जा रहे थे। सोमवार रात करीब आठ बजे राल चौकी क्षेत्र में हाईवे पर अचानक ट्रैक्टर अनियंत्रित होकर सड़क किनारे खाई में पलट गया। ट्रॉली पलटने से उसमें रखी बाजरे की बोरियां किसानों के ऊपर गिर गईं। हादसे में सुक्खन सिंह बोरियों के नीचे दब गए, जिससे उनकी मौके पर ही मौत हो गई। स्थानीय लोगों और राहगीरों ने अन्य किसानों को बाहर निकालकर अस्पताल पहुंचाया।

उप्र में लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त समेत 15 आईपीएस का तबादला

एजेंसी, लखनऊ

उत्तर प्रदेश शासन ने मंगलवार को बड़ा प्रशासनिक फेरबदल करते हुए 15 आईपीएस अधिकारियों के तबादले कर दिए। इसमें लखनऊ और प्रयागराज के पुलिस आयुक्त भी शामिल हैं। इससे पहले सोमवार देर रात 41 पीसीएस अधिकारियों का भी स्थानांतरण किया गया था।

शासन के आदेश के अनुसार मुथा अशोक जैन को पुलिस महानिदेशक अग्निशमन एवं आपात सेवाओं का नया प्रभार सौंपा गया है। वह इससे पहले गोरखपुर जोन के प्रभारी थे। वहीं लखनऊ पुलिस आयुक्त अमरेंद्र के. सेंगर को पुलिस महानिदेशक अभिसूचना के साथ पुलिस महानिदेशक सुरक्षा का अतिरिक्त प्रभार दिया गया है। तरुण गाबा को लखनऊ पुलिस

कमिश्नरेट का नया पुलिस आयुक्त बनाया गया है। वहीं पीयूष मोर्डिया को प्रयागराज का पुलिस आयुक्त नियुक्त किया गया है।

नवीन अरोरा को वाराणसी जोन का अपर पुलिस महानिदेशक बनाया गया है। इसके अलावा कई अन्य वरिष्ठ अधिकारियों को भी नई जिम्मेदारियां सौंपी गई हैं। शासन ने अधिकारियों के अनुभव और विभागीय जरूरतों को देखते हुए यह बदलाव किया है।

एचपीवी टीकाकरण सर्वाइकल कैंसर से सुरक्षा का मजबूत सामाजिक कवच : आनंदीबेन पटेल

एजेंसी, वाराणसी

उत्तर प्रदेश की राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि एचपीवी (ह्यूमन पैपिलोमा वायरस) टीकाकरण बालिकाओं को सर्वाइकल कैंसर से बचाने के लिए एक प्रभावी और सुरक्षित सामाजिक सुरक्षा कवच है। उन्होंने मंगलवार को वाराणसी के सिगरा स्थित रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में आयोजित महात्मा गांधी काशी विद्यापीठ के दीक्षांत समारोह में यह बात कही।

समारोह के दौरान राज्यपाल ने मेधावी विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए। इसके साथ ही सरकार द्वारा संचालित एचपीवी टीकाकरण अभियान के तहत 14 वर्ष पूर्ण एवं 15 वर्ष से कम आयु वर्ग की बालिकाओं को वैक्सीन लगाई गई। राज्यपाल ने टीकाकरण के बाद बालिकाओं को प्रमाण-पत्र देकर उनका उत्साहवर्धन किया। राज्यपाल आनंदीबेन पटेल ने कहा कि वैज्ञानिक शोधों से यह प्रमाणित हो चुका है कि एचपीवी वैक्सीन भविष्य में सर्वाइकल कैंसर के खतरे को कम करने में सुरक्षित और प्रभावी है। उन्होंने बालिकाओं और अभिभावकों से अपील की कि वे किसी भी प्रकार की अफवाह या भ्रांतियों से दूर रहें और समय पर अपनी बेटियों का टीकाकरण कराएं।

उन्होंने कहा कि स्वस्थ बेटी ही स्वस्थ परिवार, स्वस्थ समाज और विकसित राष्ट्र की नींव होती है। राज्यपाल ने समाज के सक्षम नागरिकों और संस्थाओं से भी इस अभियान में सहयोग करने की अपील की, ताकि कोई भी बेटी इस सुरक्षा कवच से वंचित न रहे। कार्यक्रम के दौरान कमिश्नरी सभागार में 155 और रुद्राक्ष कन्वेंशन सेंटर में 96 बालिकाओं का एचपीवी टीकाकरण किया गया। इस अवसर पर मुख्य विकास अधिकारी प्रखर कुमार सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. मुकेश कुमार, जिला प्रतिरक्षण अधिकारी डॉ. एसएस कन्नौजिया सहित कई अधिकारी मौजूद रहे।

कांवड़ यात्रा तैयारियों का जायजा लेने पहुंचे अधिकारी, सड़क के गड्ढों पर डीएम नाराज

एजेंसी, फर्रुखाबाद

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में जिलाधिकारी अंकुर लाठर और पुलिस अधीक्षक आरती सिंह ने मंगलवार को श्रृंगीरामपुर गंगा घाट पहुंचकर व्यवस्थाओं का जायजा लिया। निरीक्षण के दौरान सड़क पर गड्ढे मिलने पर जिलाधिकारी ने नाराजगी जताई और लोक निर्माण विभाग के अधिकारियों को तत्काल मरम्मत कराने के निर्देश दिए।

गंगा घाट पर व्यवस्थाओं की समीक्षा, डीएम ने अधिकारियों को दिए जरूरी निर्देश

श्रृंगीरामपुर गंगा घाट धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण स्थान है। मान्यता है कि यहां श्रृंगी ऋषि ने अखंड साधना की थी। सावन महीने में यहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु और कांवड़िए गंगा जल लेने पहुंचते हैं। कांवड़ियों की बढ़ती संख्या को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा और सुविधाओं की समीक्षा की। निरीक्षण के दौरान जिलाधिकारी ने कांवड़ियों के स्नान, ठहरने और आवागमन की व्यवस्थाओं की जानकारी ली। उन्होंने कहा कि गंगा घाट तक पहुंचने वाले कच्चे मार्ग को जल्द दुरुस्त कराया जाएगा, ताकि श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की परेशानी न हो। वहीं एसपी आरती सिंह ने बताया कि कांवड़ मेले के दौरान सुरक्षा व्यवस्था के लिए पर्याप्त पुलिस बल तैनात किया गया है।

पुलिस अधिकारियों को लगातार क्षेत्र में सक्रिय रहने और किसी भी आपात स्थिति से निपटने के निर्देश दिए गए हैं। प्रशासन ने यातायात व्यवस्था को सुचारु बनाए रखने के लिए भी आवश्यक कदम उठाने की बात कही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए सभी विभागों को बेहतर समन्वय के साथ कार्य करने के निर्देश दिए हैं।

ऑडिट में रिपोर्ट लगाने के बदले मांगे पैसे, अधिकारी पहुंचा जेल

एजेंसी, फतेहपुर। उत्तर प्रदेश के फतेहपुर जिले में भ्रष्टाचार निवारण संगठन (एंटी करप्शन) की टीम ने बड़ी कार्रवाई करते हुए स्थानीय निधि लेखा परीक्षा विभाग के वरिष्ठ लेखा परीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह को एक लाख रुपये की रिश्वत लेते रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोपी अधिकारी को सदर कोतवाली पुलिस के हवाले कर दिया गया है। जानकारी के अनुसार खागा क्षेत्र के नई बस्ती चौड़ाखेर निवासी अभय प्रताप सिंह ने एंटी करप्शन विभाग में शिकायत की थी कि बुदवन इंटर कॉलेज की भूमि अधिग्रहण से मिली धनराशि से कराए गए निर्माण कार्य की ऑडिट रिपोर्ट लगाने के लिए वरिष्ठ लेखा परीक्षक रविंद्र प्रताप सिंह ने 1.60 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी।

शिकायत का सत्यापन कराने के बाद प्रयागराज भ्रष्टाचार निवारण संगठन की 13 सदस्यीय ट्रैप टीम ने योजना बनाकर कार्रवाई की। टीम ने जिला विद्यालय निरीक्षक कार्यालय के सामने आबूनगर स्थित समर चाय भंडार के पास जाल बिछाया। जैसे ही वरिष्ठ लेखा परीक्षक ने रिश्वत की पहली किस्त के रूप में एक लाख रुपये लिए, टीम ने उन्हें मौके पर ही पकड़ लिया। सदर कोतवाली प्रभारी हेमंत कुमार मिश्र ने बताया कि आरोपी अधिकारी के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया है। मामले में आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। एंटी करप्शन टीम की इस कार्रवाई से विभाग में हड़कंप मचा हुआ है। जांच टीम आरोपी अधिकारी से पूछताछ कर रही है। रिश्वत मामले में अन्य पहलुओं की भी जांच की जा रही है। विभागीय स्तर पर भी कार्रवाई की संभावना जताई जा रही है।

चकमार्ग पर अवैध कब्जे का आरोप ग्रामीणों ने एसडीएम से लगाई गुहार

एजेंसी, वाराणसी

पिंडरा तहसील क्षेत्र के खटौरा गांव में चकमार्ग पर अवैध कब्जे का मामला सामने आया है। गांव निवासी रविनाथ सिंह ने मंगलवार को उपजिलाधिकारी पिंडरा से मुलाकात कर रास्ते पर कब्जा किए जाने की शिकायत की। उन्होंने आरोप लगाया कि कुछ दबंग लोगों ने चकमार्ग को बाधित कर दिया है, जिससे ग्रामीणों को आवागमन में परेशानी का सामना करना पड़ रहा है।

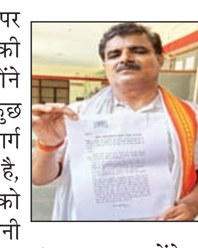

रविनाथ सिंह ने बताया कि आराजी संख्या 85 के दक्षिण में आराजी संख्या 83 चकमार्ग स्थित है, जबकि पूरब दिशा में आराजी संख्या 89 चकमार्ग है। आरोप है कि आराजी संख्या 83 से सटी पुरानी आबादी में रहने वाले इंद्रबली और श्यामबली ने चकमार्ग पर कब्जा कर लिया है। उन्होंने बताया कि रास्ते पर सोख्ता बनाकर, चारा मशीन और ईंट आदि सामान रख दिए गए हैं, जिससे पूरा मार्ग अवरुद्ध हो गया है। शिकायतकर्ता ने यह भी आरोप लगाया कि रास्ते पर नाली और नाबदान का पानी बहाया जा रहा है, जो चकरोड़ के रास्ते खेतों तक पहुंच रहा है। इससे खेतों में कीचड़ जमा हो रहा है और खेती प्रभावित हो रही है। इसके अलावा खेतों में कूड़ा-कचरा फेंके जाने से भी परेशानी बढ़ रही है। उपजिलाधिकारी पिंडरा ने शिकायत सुनने के बाद मामले की जांच कराने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि जांच रिपोर्ट आने के बाद नियमानुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

पिंडरा तहसील प्रशासन ने मामले को गंभीरता से लेते हुए जांच की प्रक्रिया शुरू कर दी है। अधिकारियों के अनुसार मौके का निरीक्षण कर चकमार्ग की स्थिति और लगाए गए आरोपों की सत्यता की जांच की जाएगी। जांच में दोषी पाए जाने वालों के खिलाफ नियमानुसार कार्रवाई की जाएगी। वहीं ग्रामीणों ने जल्द रास्ता खाली कराने की मांग की है।

नियुक्ति — कोन विकासखंड में आयोजित कार्यक्रम में चयनित सहायिकाओं को सौंपे गए नियुक्ति पत्र

मीरजापुर में 31 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को मिले नियुक्ति पत्र

एजेंसी, मीरजापुर

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में महिला सशक्तीकरण को बढ़ावा देने की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल की गई। विकासखंड कोन के सभागार में मंगलवार को बाल विकास परियोजना के तहत चयनित 31 आंगनबाड़ी सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र वितरित किए गए। कार्यक्रम में नगर विधायक रत्नाकर मिश्र और समाजसेवी अनिल कुमार सिंह ने चयनित सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र सौंपते हुए उन्हें अपने दायित्वों का निर्वहन पूरी निष्ठा, ईमानदारी और जिम्मेदारी के साथ करने की अपील की।

बाल विकास परियोजना कोन के अंतर्गत कुल 32 आंगनबाड़ी सहायिकाओं का चयन किया गया था। इनमें से 31 चयनित सहायिकाओं को नियुक्ति पत्र प्रदान किए गए, जबकि मनौवा गांव की एक चयनित सहायिका के खिलाफ शिकायत मिलने के कारण उसका नियुक्ति पत्र अग्रिम आदेश तक रोक दिया गया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले की जांच के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी।

कार्यक्रम का शुभारंभ नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने मां सरस्वती के चित्र पर माल्यार्पण और दीप प्रज्ज्वलित कर किया।

इस अवसर पर आंगनबाड़ी सहायिकाओं ने सरस्वती वंदना प्रस्तुत की। कार्यक्रम में मौजूद लोगों ने नई नियुक्ति पाने वाली सहायिकाओं को शुभकामनाएं दीं और उनके उज्ज्वल भविष्य की कामना की। नगर विधायक रत्नाकर मिश्र ने कहा कि प्रदेश सरकार महिलाओं को आत्मनिर्भर और सशक्त बनाने के लिए लगातार कार्य कर रही है। उन्होंने कहा कि महिलाओं को सरकारी सेवाओं में अवसर उपलब्ध कराने के साथ ही कई जनकल्याणकारी योजनाएं संचालित की जा रही हैं, जिनका उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक और सामाजिक रूप से मजबूत बनाना है।

उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी कार्यकर्ता और सहायिकाएं समाज के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। वे बच्चों के पोषण, प्रारंभिक शिक्षा और स्वास्थ्य संबंधी जागरूकता फैलाने जैसे महत्वपूर्ण कार्यों से जुड़ी होती हैं। उन्होंने नवनियुक्त सहायिकाओं से अपील की कि वे पूरी लगन और समर्पण के साथ अपनी जिम्मेदारियों का निर्वहन करें, ताकि समाज के कमजोर वर्गों को योजनाओं का बेहतर लाभ मिल सके।

समाजसेवी अनिल कुमार सिंह ने कहा कि आंगनबाड़ी सहायिकाओं की नियुक्ति महिलाओं के आत्मविश्वास और आर्थिक सशक्तीकरण की दिशा में एक अहम कदम है। उन्होंने कहा कि रोजगार मिलने से महिलाओं में आत्मनिर्भरता बढ़ती है और वे अपने परिवार तथा समाज के विकास में अधिक प्रभावी भूमिका निभा सकती हैं। उन्होंने कहा कि आंगनबाड़ी केंद्र ग्रामीण क्षेत्रों में बच्चों और महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण सेवाएं उपलब्ध कराते हैं। ऐसे में नई सहायिकाओं की नियुक्ति से इन केंद्रों की कार्यप्रणाली और अधिक मजबूत होगी। कार्यक्रम में खंड विकास अधिकारी शैलेंद्र सिंह, बाल विकास परियोजना अधिकारी ज्योतिमा सिंह, एडीओ आईएसबी राजेश सिंह सहित कई अधिकारी और जनप्रतिनिधि मौजूद रहे।

जीआरपी मीरजापुर ने ट्रेन से सांसी गैंग के चार शातिर चोर किए गिरफ्तार, मोबाइल फोन,जेवर व नकदी भी बरामद

एजेंसी, मीरजापुर

उत्तर प्रदेश के मीरजापुर जिले में जीआरपी पुलिस ने ट्रेनों में यात्रियों को निशाना बनाकर चोरी करने वाले अंतरराज्यीय सांसी गैंग का पर्दाफाश किया है। संयुक्त कार्रवाई में पुलिस ने गैंग के चार शातिर सदस्यों को गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपियों के कब्जे से चोरी के मोबाइल फोन, सोने चांदी के आभूषण और नकदी बरामद की गई है।

जीआरपी ने पकड़ा ट्रेन यात्रियों को निशाना बनाने वाला शातिर गिरोह

एसी कोच के चोरों पर जीआरपी का करारा प्रहार, चार गिरफ्तार

जीआरपी मीरजापुर के थानाध्यक्ष राजेश कुमार वर्मा ने बताया कि जीआरपी, आरपीएफ और सीआईबी की संयुक्त टीम को मुखबिर से सूचना मिली थी कि कुछ संदिग्ध लोग ट्रेन में चोरी की वारदात को अंजाम देने की फिराक में हैं। सूचना के आधार पर टीम ने राजगीर जनता एक्सप्रेस के एसी कोच बी-2 में छापेमारी कर चार आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी हरियाणा के रोहतक जिले के निवासी हैं। पूछताछ में आरोपियों ने स्वीकार किया कि वे सांसी गैंग के सदस्य हैं और कई राज्यों में ट्रेनों के अंदर चोरी की घटनाओं को अंजाम देते हैं।

गैंग में सात से आठ सदस्य शामिल होकर वारदात करते हैं। गिरोह के सदस्य यात्रियों की रेकी करने के बाद मौका मिलते ही चोरी कर लेते थे। पुलिस जांच में सामने आया कि गैंग का एक सदस्य सूजे की मदद से ट्रॉली बैग और सूटकेस की चेन खोलता था और उसमें रखे कीमती सामान को निकाल लेता था। इसके बाद गिरोह के अन्य सदस्य सामान लेकर अलग-अलग कोच में चले जाते थे, जिससे किसी को शक न हो। स्टेशन पर उतरते समय भी सभी सदस्य अलग-अलग होकर सीसीटीवी कैमरों से बचते हुए फरार हो जाते थे।

पुलिस ने बताया कि यह गिरोह खासतौर पर एसी कोच में सफर करने वाले परिवारों और रात के समय सो रहे यात्रियों को अपना निशाना बनाता था। चोरी किए गए जेवरों को स्थानीय सर्राफों के माध्यम से बेचकर मिलने वाली रकम को आपस में बांट लिया जाता था। जीआरपी ने गिरफ्तार आरोपियों के खिलाफ संबंधित धाराओं में मुकदमा दर्ज कर उन्हें न्यायालय भेज दिया है। पुलिस अब गिरोह के अन्य सदस्यों और चोरी के सामान की खरीद-फरोख्त में शामिल लोगों की तलाश कर रही है।

हाई कोर्ट का बड़ा आदेश, जान का खतरा होने पर आरोपियों की वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से होगी पेशी

जेल से अदालत तक ले जाने में खतरे को देखते हुए हाई कोर्ट ने दिया विकल्प

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

आरोपियों की सुरक्षा को लेकर पंजाब-हरियाणा हाई कोर्ट का अहम निर्देश

पंजाब एवं हरियाणा हाई कोर्ट ने हरियाणा की जेलों में बंद ऐसे आरोपियों की सुरक्षा को लेकर महत्वपूर्ण आदेश जारी किया है, जिन्हें अदालत में पेशी के दौरान जान का खतरा होने की आशंका हो। कोर्ट ने स्पष्ट किया है कि यदि किसी आरोपी की सुरक्षा को लेकर वास्तविक खतरा पाया जाता है तो उसकी नियमित पेशी वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से कराई जा सकती है।

इस व्यवस्था का उद्देश्य न्यायिक प्रक्रिया को सुचारू बनाए रखने के साथ-साथ आरोपियों की सुरक्षा सुनिश्चित करना है। हाई कोर्ट ने यह आदेश नरेश यादव की ओर से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। याचिका में आरोपी की पेशी के दौरान सुरक्षा संबंधी चिंताओं को उठाया गया था। मामले की सुनवाई के दौरान अदालत ने कहा कि किसी भी आरोपी को अदालत में पेश करना न्यायिक प्रक्रिया का हिस्सा है, लेकिन यदि उसकी जान को खतरा है तो सुरक्षा को प्राथमिकता देते हुए वैकल्पिक व्यवस्था अपनाई जा सकती है।

अदालत ने कहा कि ऐसे मामलों में आरोपी को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए अदालत के समक्ष पेश किया जा सकता है।

इससे एक ओर जहां न्यायिक कार्यवाही जारी रहेगी, वहीं आरोपी को जेल से अदालत तक लाने-ले जाने के दौरान होने वाले संभावित खतरे को भी कम किया जा सकेगा। कोर्ट ने यह भी स्पष्ट किया कि वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग की सुविधा नियमित आधार पर दी जा सकती है, यदि सुरक्षा एजेंसियों और संबंधित अधिकारियों की रिपोर्ट में खतरे की पुष्टि होती है। हालांकि, हाई कोर्ट ने यह भी कहा कि यदि किसी विशेष मामले में आरोपी की पहचान सुनिश्चित करने या किसी अन्य न्यायिक आवश्यकता के लिए व्यक्तिगत उपस्थिति जरूरी समझी जाती है तो उसे अदालत में शारीरिक रूप से पेश किया जाएगा।

ऐसी स्थिति में राज्य सरकार और संबंधित सुरक्षा एजेंसियों की जिम्मेदारी होगी कि आरोपी को पर्याप्त सुरक्षा उपलब्ध कराई जाए। हाई कोर्ट के इस आदेश को जेलों में बंद संवेदनशील मामलों के आरोपियों की सुरक्षा व्यवस्था को मजबूत करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम माना जा रहा है। कई बार गंभीर आपराधिक मामलों में शामिल आरोपियों को अदालत तक लाने के दौरान सुरक्षा चुनौतियां सामने आती हैं।

फरीदाबाद में गैस कटर से एटीएम काटकर चोरों ने उड़ाए 5.5 लाख

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

हरियाणा के फरीदाबाद में एक ही दिन के भीतर चोरी की दो अलग-अलग वारदातों ने पुलिस की सुरक्षा व्यवस्था पर सवाल खड़े कर दिए हैं। पहली घटना सेक्टर-58 थाना क्षेत्र में जेसीबी कंपनी के सामने स्थित कॉलोनी में लगे हिताची एटीएम में हुई, जहां बदमाश गैस कटर की मदद से एटीएम मशीन काटकर करीब 5.5 लाख की नकदी लेकर फरार हो गए। घटना के बाद इलाके में हड़कंप मच गया और पुलिस ने मौके पर पहुंचकर जांच शुरू कर दी।

प्रारंभिक जानकारी के अनुसार चोर देर रात एटीएम तक पहुंचे और गैस कटर से मशीन को काटकर उसके भीतर रखी नकदी निकाल ली। वारदात को अंजाम देने के बाद आरोपी मौके से फरार हो गए। सुबह लोगों ने एटीएम की हालत देखकर पुलिस को सूचना दी। सूचना मिलते ही पुलिस और फोरेंसिक टीम घटनास्थल पर पहुंची तथा साक्ष्य जुटाए। आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाली जा रही है, ताकि आरोपियों की पहचान की जा सके।

इसी दिन चोरी की दूसरी घटना में चोरों ने एक दुकान का ताला तोड़कर भीतर प्रवेश किया और वहां से 25 हजार की नकदी चुरा ली। वारदात के बाद आरोपी आसानी से फरार हो गए। दोनों घटनाओं से व्यापारियों और स्थानीय लोगों में चिंता का माहौल है।

पुलिस का कहना है कि दोनों मामलों में अलग-अलग प्राथमिकी दर्ज कर जांच शुरू कर दी गई है। सीसीटीवी फुटेज, तकनीकी साक्ष्यों और अन्य सुरागों के आधार पर आरोपियों की तलाश की जा रही है। अधिकारियों का दावा है कि जल्द ही वारदातों का खुलासा कर दोषियों को गिरफ्तार किया जाएगा। वहीं, स्थानीय लोगों ने पुलिस से रात्रि गश्त बढ़ाने और एटीएम व बाजार क्षेत्रों की सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की है, ताकि भविष्य में ऐसी घटनाओं पर प्रभावी रोक लगाई जा सके।

न्यूज ब्रीफ

निर्धारित समय-सीमा में पूरी हों भवन एवं सड़क परियोजनाएं: रणबीर गंगवा

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़। हरियाणा के लोक निर्माण मंत्री रणबीर गंगवा ने प्रदेश में चल रही भवन एवं सड़क परियोजनाओं को तय समय-सीमा में पूरा करने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने कहा कि विकास कार्यों की गुणवत्ता से किसी भी प्रकार का समझौता स्वीकार नहीं किया जाएगा। पंचकूला में विभागीय अधिकारियों के साथ समीक्षा बैठक में मंत्री ने लंबित परियोजनाओं में तेजी लाने, अंतर विभागीय मामलों का शीघ्र समाधान करने तथा लापरवाही बरतने वाले ठेकेदारों पर कार्रवाई के निर्देश दिए। बरसात के मौसम में सड़कों के गड्ढों को तुरंत भरने, अधिकारियों को अलर्ट मोड में रहने और 'म्हारी सड़क' ऐप पर आने वाली शिकायतों का प्राथमिकता से निस्तारण करने को कहा। साथ ही 10 करोड़ रुपये से अधिक लागत वाली परियोजनाओं के स्थलों पर सूचना बोर्ड लगाने के भी निर्देश दिए, ताकि जनता को परियोजना संबंधी जानकारी आसानी से मिल सके।

करनाल में चोर बेखौफ, व्यापारियों ने काली पट्टी बांधकर जताया विरोध

भारतेन्दु संवाददाता, करनाल। हरियाणा के करनाल में लगातार बढ़ रही चोरी की घटनाओं से नाराज व्यापारियों ने मंगलवार को काली पट्टी बांधकर विरोध मार्च निकाला। व्यापारियों का आरोप है कि एक ही रात में चोरों ने 10 दुकानों के ताले तोड़कर चोरी की वारदातों को अंजाम दिया, जिससे बाजार में भय और असुरक्षा का माहौल है। प्रदर्शनकारियों ने प्रशासन और पुलिस के खिलाफ नाराजगी जताते हुए कहा कि लगातार शिकायतों के बावजूद अपराधों पर प्रभावी अंकुश नहीं लग पा रहा है। व्यापारियों ने दोषियों की शीघ्र गिरफ्तारी, बाजारों में रात्रि गश्त बढ़ाने और सुरक्षा व्यवस्था मजबूत करने की मांग की। प्रदर्शन के दौरान उन्होंने चेतावनी दी कि यदि जल्द कार्रवाई नहीं हुई तो आंदोलन को और तेज किया जाएगा। पुलिस ने मामले की जांच तेज करने और आरोपियों को जल्द गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है।

दो लाख रुपए के विवाद में रियल एस्टेट कर्मचारी की गोली मारकर हत्या

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद। उत्तर प्रदेश के फर्रुखाबाद में रियल एस्टेट कर्मचारी अरुण हुड्डा (30) की हत्या के मामले में नया मोड़ सामने आया है। परिजनों ने आरोप लगाया है कि जमीन के सौदे में 2 लाख के विवाद के चलते रिश्तेदार रोहित ने सुपारी देकर हत्या करवाई। परिवार के अनुसार, दोनों के बीच 400 गज के प्लॉट को लेकर विवाद चल रहा था और इसी रंजिश में वारदात को अंजाम दिया गया। बताया गया कि अरुण चार वर्ष पहले प्रेम विवाह कर चुका था और हाल ही में पत्नी व बच्चे के साथ वाराणसी से लौट रहा था। रास्ते में कोल्ड ड्रिंक लेने के दौरान बदमाशों ने उस पर ताबड़तोड़ गोलियां चला दीं। पुलिस ने आरोपी रोहित को हिरासत में लेकर पूछताछ शुरू कर दी है। मामले की जांच जारी है।

रिश्वत मामले में होमगार्ड अधिकारी की अग्रिम जमानत याचिका खारिज

भारतेन्दु संवाददाता, नारनौल। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने महेंद्रगढ़ में ड्यूटी और पोस्टिंग के बदले कथित रिश्वत लेने के मामले में होमगार्ड विभाग के अधिकारी विजयपाल सिंह की अग्रिम जमानत याचिका खारिज कर दी है। न्यायमूर्ति सुमीत गोयल की अदालत ने अपने आदेश में कहा कि मामले की निष्पक्ष जांच आवश्यक है और जांच एजेंसी को कानून के अनुसार कार्रवाई करने की पूरी छूट दी जानी चाहिए। अदालत ने प्रथम दृष्टया आरोपों की गंभीरता को देखते हुए अग्रिम जमानत देने से इनकार कर दिया। मामला ड्यूटी और पोस्टिंग में अनियमितताओं तथा कथित रिश्वतखोरी से जुड़ा है। जांच एजेंसी अब मामले में आगे की पूछताछ और साक्ष्य जुटाने की कार्रवाई करेगी। हाईकोर्ट के इस फैसले को भ्रष्टाचार के मामलों में सख्त रुख के रूप में देखा जा रहा है।

राष्ट्रमंडल खेलों में सुमित कुंडू को बड़ा झटका, पदक की दौड़ समाप्त

भारतेन्दु संवाददाता, जींद

हरियाणा के जींद जिले के ढाकल गांव के मुक्केबाज सुमित कुंडू का राष्ट्रमंडल खेल 2026 में पदक जीतने का सपना पहले ही मुकाबले में टूट गया। 70 किलोग्राम भार वर्ग में उन्हें उत्तरी आयरलैंड के मुक्केबाज जॉन मैकानेल के हाथों हार का सामना करना पड़ा। इस हार के साथ ही सुमित प्रतियोगिता से बाहर हो गए और उनका अभियान समाप्त हो गया।

सुमित कुंडू से इस बार पदक की काफी उम्मीदें थीं। उन्होंने लंबे समय तक कठिन प्रशिक्षण किया था और अंतरराष्ट्रीय स्तर पर वापसी के बाद बेहतर प्रदर्शन भी किया था। हालांकि पहले मुकाबले में वह अपनी लय कायम नहीं रख सके और आयरलैंड के प्रतिद्वंद्वी के खिलाफ मुकाबला हार गए। इससे उनके समर्थकों और कोचिंग स्टाफ को भी निराशा हुई। सुमित का खेल सफर पिछले कुछ वर्षों में चुनौतियों से भरा

आयरलैंड के मुक्केबाज ने सुमित को हराया

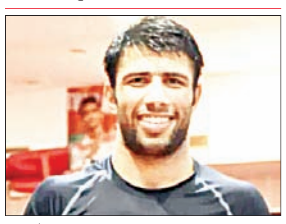

रहा है। पेरिस ओलिंपिक क्वालीफायर से पहले लगी गंभीर चोट के कारण उनका ओलिंपिक खेलने का सपना अधूरा रह गया था।

चोट के चलते वह लगभग दो वर्षों तक प्रतियोगी मुक्केबाजी से दूर रहे। इस दौरान उन्होंने संन्यास लेने तक का विचार किया, लेकिन कठिन मेहनत और लंबे पुनर्वास के बाद उन्होंने दमदार वापसी की। पिछले वर्ष सुमित ने विश्व मुक्केबाजी चैंपियनशिप के प्री-क्वार्टर फाइनल तक पहुंचकर अपनी वापसी का संकेत दिया था।

20 हजार रुपए रिश्वत लेते सब इंस्पेक्टर एसीबी के हत्थे चढ़ा

भारतेन्दु संवाददाता, फतेहाबाद। हरियाणा के फतेहाबाद जिले में एंटी करप्शन ब्यूरो (एसीबी) ने रिश्वतखोरी के आरोप में भट्टू थाना में तैनात सब इंस्पेक्टर रामपाल को 20 हजार रुपये की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया है। आरोप है कि उसने एक मामले में कार्रवाई के बदले शिकायतकर्ता से रिश्वत की मांग की थी। शिकायत मिलने के बाद एसीबी ने जाल बिछाकर कोर्ट परिसर में कार्रवाई की और आरोपी अधिकारी को रिश्वत की रकम के साथ दबोच लिया। गिरफ्तारी के बाद एसीबी टीम आरोपी से पूछताछ कर रही है तथा मामले से जुड़े अन्य तथ्यों की जांच भी की जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि भ्रष्टाचार के मामलों में किसी भी दोषी को बख्शा नहीं जाएगा और कानून के अनुसार आगे की कार्रवाई की जाएगी।

हरियाणा में फिजी वायरस के कहर से 1500 एकड़ धान की फसल प्रभावित, किसान चिंतित

भारतेन्दु संवाददाता, कैथल

हरियाणा में धान की फसल पर फिजी वायरस (बौना पन रोग) का प्रकोप तेजी से बढ़ने लगा है। कैथल सहित प्रदेश के कई जिलों में इस बीमारी ने किसानों की चिंता बढ़ा दी है। कृषि विभाग ने धान की फसल में फिजी वायरस की पुष्टि की है। विभाग के अनुसार अब तक केवल कैथल जिले में ही 1500 एकड़ से अधिक धान की फसल इस वायरस की चपेट में आ चुकी है, जिससे किसानों को भारी आर्थिक नुकसान की आशंका सता रही है।

जानकारी के अनुसार फिजी वायरस का असर केवल कैथल तक सीमित नहीं है, बल्कि कुरुक्षेत्र, करनाल और अंबाला जिलों में भी धान की फसल प्रभावित होने की खबरें सामने आई हैं। बीमारी की चपेट में आने के बाद धान के पौधों का सामान्य विकास रुक जाता है और वे बौने रह जाते हैं। इससे फसल की बढ़वार प्रभावित होती है और उत्पादन में भारी गिरावट आने की संभावना रहती है।

किसानों का कहना है कि खेतों में धान के पौधे सामान्य ऊंचाई तक नहीं बढ़ रहे हैं, जिससे पैदावार पर प्रतिकूल असर पड़ सकता है। उन्होंने कृषि विभाग से प्रभावित क्षेत्रों में व्यापक सर्वेक्षण और सैंपलिंग कराने की मांग की है, ताकि बीमारी के वास्तविक कारणों की पहचान कर समय रहते उचित नियंत्रण उपाय अपनाए जा सकें। कृषि विभाग के अधिकारियों का कहना है कि प्रभावित क्षेत्रों पर लगातार निगरानी रखी जा रही है।

किसानों को समय-समय पर खेतों का निरीक्षण करने, रोगग्रस्त पौधों की जानकारी तुरंत विभाग को देने तथा विशेषज्ञों की सलाह के अनुसार फसल प्रबंधन अपनाने की अपील की गई है। विभाग ने यह भी कहा है कि वायरस के प्रसार को रोकने के लिए आवश्यक तकनीकी उपाय किए जा रहे हैं।

हरियाणा में हेपेटाइटिस सी मरीजों को अब जिले के अस्पतालों में मुफ्त इलाज की सुविधा

भारतेन्दु संवाददाता, रोहतक

अब हेपेटाइटिस-सी मरीजों को इलाज के लिए रोहतक नहीं, अपने जिले में सुविधा मिलेगी।

हरियाणा में हेपेटाइटिस-सी जैसी गंभीर बीमारी के उपचार को अधिक सुलभ और प्रभावी बनाने की दिशा में पंडित भगवत दयाल शर्मा स्नातकोत्तर आयुर्विज्ञान संस्थान (पीजीआईएमएस), रोहतक ने एक अनूठी पहल शुरू की है। संस्थान के गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विभाग ने 'हेपेटाइटिस सी फ्री हरियाणा' मॉडल के तहत एक विशेष व्हाट्सएप नेटवर्क तैयार किया है, जिसके माध्यम से मरीजों को अब उपचार के लिए बार-बार रोहतक आने की आवश्यकता नहीं पड़ रही है।

उन्हें अपने ही जिले के सरकारी अस्पताल में विशेषज्ञों की देखरेख में मुफ्त इलाज उपलब्ध कराया जा रहा है। इस नेटवर्क में हरियाणा के चार मेडिकल कॉलेजों और 22 सरकारी सिविल अस्पतालों के कुल 27 गैस्ट्रोएंटरोलॉजी विशेषज्ञ चिकित्सकों को जोड़ा गया है। किसी भी मरीज की जटिल चिकित्सा संबंधी समस्या होने पर संबंधित चिकित्सक इस नेटवर्क के माध्यम से विशेषज्ञों से तत्काल सलाह लेते हैं।

इसके बाद मरीज को आवश्यक जांच, दवाएं और उपचार उसके जिले में ही उपलब्ध कराया जाता है। इस व्यवस्था से मरीजों का समय और धन दोनों बच रहे हैं। साथ ही दूरदराज के क्षेत्रों में रहने वाले लोगों को भी गुणवत्तापूर्ण स्वास्थ्य सेवाओं का लाभ आसानी से मिल रहा है। विभाग के विशेषज्ञों के अनुसार, समय पर जांच और आधुनिक दवाओं के उपयोग से हेपेटाइटिस-सी के लगभग 95 प्रतिशत मरीज पूरी तरह स्वस्थ हो रहे हैं। यही कारण है कि यह मॉडल राज्य में प्रभावी स्वास्थ्य सेवा का उदाहरण बनकर उभरा है। स्वास्थ्य विशेषज्ञों का मानना है कि डिजिटल तकनीक और विशेषज्ञों के समन्वय से तैयार यह नेटवर्क गंभीर बीमारियों के उपचार की दिशा में नई संभावनाएं खोल रहा है।

इससे मरीजों को समय पर चिकित्सकीय परामर्श मिल रहा है और अनावश्यक रेफरल की स्थिति भी कम हुई है। पीजीआईएमएस की यह पहल भविष्य में अन्य गंभीर रोगों के उपचार के लिए भी उपयोगी मॉडल साबित हो सकती है। राज्य सरकार और स्वास्थ्य विभाग को उम्मीद है कि इस पहल से हरियाणा को 'हेपेटाइटिस-सी मुक्त राज्य' बनाने के लक्ष्य को हासिल करने में महत्वपूर्ण सफलता मिलेगी।

आर्य समाज रोड पर हथियारबंद बदमाशों का हमला, युवक की हालत गंभीर

भारतेन्दु संवाददाता, सिरसा

हरियाणा के सिरसा शहर में सोमवार देर रात आर्य समाज रोड स्थित डॉ. इंद्रजीत वाली गली में एक लेमिनेशन दुकानदार पर तेजधार हथियारों से जानलेवा हमला किए जाने का मामला सामने आया है। हमले में गंभीर रूप से घायल दुकानदार का निजी अस्पताल में उपचार चल रहा है। घटना के बाद क्षेत्र में दहशत का माहौल है, जबकि पुलिस आरोपितों की तलाश में जुट गई है।

जानकारी के अनुसार रानियां चुंगी निवासी रमेश सिंह अपनी दुकान पर काम कर रहे थे। इसी दौरान देर रात आठ से दस अज्ञात बदमाश तेजधार हथियार लेकर वहां पहुंचे और उन पर अचानक हमला कर दिया। हमलावरों ने रमेश सिंह की गर्दन पर वार किया, जिससे वह गंभीर रूप से घायल होकर मौके पर गिर पड़े। घटना को अंजाम देने के बाद सभी आरोपित मौके से फरार हो गए। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोग मौके पर पहुंचे और घायल को तुरंत निजी अस्पताल

पहुंचाया, जहां चिकित्सकों की निगरानी में उनका उपचार जारी है। डॉक्टरों के अनुसार उनकी हालत गंभीर बनी हुई है।

प्रारंभिक जांच में पुलिस प्रेम प्रसंग को हमले की संभावित वजह मानकर जांच कर रही है। हालांकि अधिकारियों का कहना है कि सभी पहलुओं को ध्यान में रखकर जांच की जा रही है और अभी किसी निष्कर्ष पर पहुंचना जल्दबाजी होगी। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज खंगाल रही है तथा प्रत्यक्षदर्शियों से पूछताछ कर हमलावरों की पहचान करने का प्रयास कर रही है। अधिकारियों का कहना है कि आरोपितों की गिरफ्तारी के लिए टीमों का गठन कर छापेमारी की जा रही है और जल्द ही पूरे मामले का खुलासा किया जाएगा।

चरखी दादरी में रोडवेज बस की टक्कर से मोपेड सवार की मौके पर दर्दनाक मौत

भारतेन्दु संवाददाता, चरखी दादरी

हरियाणा के चरखी दादरी जिले में मंगलवार सुबह नेशनल हाईवे-148बी पर एक दर्दनाक सड़क हादसे में मोपेड सवार व्यक्ति की मौत हो गई। यह हादसा गांव पालड़ी बस अड्डे के समीप उस समय हुआ, जब हरियाणा रोडवेज की एक बस ने मोपेड को टक्कर मार दी। टक्कर इतनी तेज थी कि मोपेड सवार ने घटनास्थल पर ही दम तोड़ दिया। हादसे के बाद मौके पर लोगों की भीड़ जमा हो गई और पुलिस को सूचना दी गई।

मृतक की पहचान गांव पालड़ी निवासी महिपाल, पुत्र छाजूराम, के रूप में हुई है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार महिपाल अपनी विक्की मोपेड पर सवार होकर गांव से मुख्य सड़क की ओर जा रहे थे। इसी दौरान नेशनल हाईवे-148बी पर सामने से आ रही हरियाणा रोडवेज की बस की चपेट में आ गए। हादसा इतना भीषण था कि उन्हें गंभीर चोटें आईं और उनकी मौके पर ही मृत्यु हो गई। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय पुलिस मौके पर पहुंची और

चरखी दादरी हादसे में घटनास्थल पर ही व्यक्ति की मौत

घटनास्थल का निरीक्षण किया। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर आवश्यक कानूनी प्रक्रिया पूरी की तथा पोस्टमार्टम के लिए अस्पताल भिजवाया।

हादसे के कारण कुछ समय के लिए हाईवे पर यातायात भी प्रभावित रहा, जिसे बाद में पुलिस ने सामान्य कराया। मामले की गंभीरता को देखते हुए फोरेंसिक साइंस लैब (एफएसएल) की टीम को भी घटनास्थल पर बुलाया गया। टीम ने दुर्घटना स्थल से आवश्यक साक्ष्य जुटाए और हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस आसपास लगे सीसीटीवी कैमरों की फुटेज भी खंगाल रही है, ताकि दुर्घटना की वास्तविक परिस्थितियों का पता लगाया जा सके।

पुलिस अधिकारियों का कहना है कि प्रत्यक्षदर्शियों के बयान दर्ज किए जा रहे हैं और जांच रिपोर्ट के आधार पर आगे की कानूनी कार्रवाई की जाएगी। हादसे के बाद मृतक के परिवार में शोक की लहर है। स्थानीय लोगों ने भी इस दुर्घटना पर दुख व्यक्त करते हुए हाईवे पर यातायात नियमों के कड़ाई से पालन और सड़क सुरक्षा उपायों को और प्रभावी बनाने की मांग की है। पुलिस ने लोगों से वाहन चलाते समय सतर्कता बरतने और यातायात नियमों का पालन करने की अपील भी की है। स्थानीय प्रशासन ने कहा कि सड़क दुर्घटनाओं को रोकने के लिए जागरूकता अभियान लगातार चलाए जा रहे हैं। अधिकारियों ने वाहन चालकों से गति सीमा का पालन करने, हेलमेट व सीट बेल्ट का उपयोग करने तथा यातायात नियमों का सख्ती से पालन करने की अपील की है।

हरियाणा में खेल चयन प्रक्रिया होगी पारदर्शी, तय होंगे नए मानक

आधिकारिक वेबसाइट के जरिए खिलाड़ियों को सभी महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध होंगी

भारतेन्दु संवाददाता, चंडीगढ़

हरियाणा में खेल प्रशासन को अधिक पारदर्शी, जवाबदेह और आधुनिक बनाने की दिशा में हरियाणा ओलिंपिक संघ (एचओए) ने कई महत्वपूर्ण निर्णय लिए हैं। पंचकूला स्थित ओलिंपिक भवन में संघ के अध्यक्ष कैप्टन जसविंदर मीनू बेनीवाल की अध्यक्षता में आयोजित वार्षिक आम सभा में खिलाड़ियों के चयन, खेल प्रतियोगिताओं के आयोजन और खेल विज्ञान के उपयोग को लेकर व्यापक सुधारों पर सहमति बनी। इन फैसलों का उद्देश्य खिलाड़ियों को निष्पक्ष अवसर उपलब्ध कराना तथा खेल व्यवस्था को अधिक व्यवस्थित और विश्वसनीय बनाना है।

बैठक में निर्णय लिया गया कि राष्ट्रीय प्रतियोगिताओं और राष्ट्रीय खेलों में भागीदारी के लिए खिलाड़ियों के चयन ट्रायल अब निर्धारित और पारदर्शी मानकों के आधार पर आयोजित किए जाएंगे। चयन प्रक्रिया में किसी प्रकार की अस्पष्टता न रहे, इसके लिए खिलाड़ियों के दस्तावेज पंजीकरण के समय ही सत्यापित किए जाएंगे। साथ ही ट्रायल यथासंभव अलग-अलग स्थानों पर आयोजित किए जाएंगे, ताकि प्रदेश के विभिन्न क्षेत्रों के खिलाड़ियों को समान अवसर मिल सके।

ट्रायल प्रतियोगिताओं से लगभग 20 से 25 दिन पहले पूरे कराने का भी निर्णय लिया गया है, जिससे चयनित खिलाड़ियों को तैयारी के लिए पर्याप्त समय मिल सके।

वार्षिक आम सभा में खेल प्रशासन को आधुनिक स्वरूप देने के लिए कई नए आयोग गठित करने का भी फैसला लिया गया। इनमें एथलीट आयोग, महिला खेल आयोग, एथिक्स आयोग और स्पोर्ट्स साइंस आयोग प्रमुख हैं। इन आयोगों का उद्देश्य खिलाड़ियों के हितों की रक्षा करना, महिला खिलाड़ियों को बेहतर अवसर उपलब्ध कराना, खेलों में नैतिक मूल्यों को बढ़ावा देना तथा वैज्ञानिक प्रशिक्षण और आधुनिक तकनीकों के उपयोग को प्रोत्साहित करना है। माना जा रहा है कि इन आयोगों के गठन से खेलों के संचालन में पेशेवर दृष्टिकोण को बढ़ावा मिलेगा। बैठक में 28वें हरियाणा राज्य खेलों की तैयारियों पर भी विस्तार से चर्चा हुई।

प्रस्तावित खेल विधाओं, संभावित आयोजन स्थलों, प्रतियोगिता कैलेंडर, संचालन व्यवस्था और बजट को लेकर विचार-विमर्श किया गया। इन तैयारियों को अंतिम रूप देने और आवश्यक निर्णय लेने के लिए कार्यकारिणी को अधिकृत किया गया है। अधिकारियों का मानना है कि समयबद्ध योजना के साथ राज्य खेलों का सफल आयोजन सुनिश्चित किया जाएगा। हरियाणा ओलिंपिक संघ ने अपनी आधिकारिक वेबसाइट का भी शुभारंभ किया। इस वेबसाइट के माध्यम से खिलाड़ियों, प्रशिक्षकों, खेल संघों और आम नागरिकों को चयन प्रक्रिया, प्रतियोगिताओं, दिशा-निर्देशों, कार्यक्रमों तथा

हरियाणा में एथलीट, महिला खेल एथिक्स व स्पोर्ट्स साइंस आयोग बनेंगे

अन्य महत्वपूर्ण सूचनाएं ऑनलाइन उपलब्ध कराई जाएंगी। इससे सूचना तक आसान पहुंच सुनिश्चित होगी और खेल प्रशासन में पारदर्शिता को और मजबूती मिलेगी।

बैठक में इस बात पर भी जोर दिया गया कि खिलाड़ियों को केवल प्रतियोगिताओं तक सीमित न रखकर उनके समग्र विकास पर ध्यान दिया जाए। स्पोर्ट्स साइंस, पोषण, खेल मनोविज्ञान, फिजियोथेरेपी और चोट प्रबंधन जैसी आधुनिक सुविधाओं का अधिकतम लाभ खिलाड़ियों तक पहुंचाने की दिशा में काम किया जाएगा। विशेषज्ञों का मानना है कि वैज्ञानिक प्रशिक्षण पद्धति अपनाने से खिलाड़ियों का प्रदर्शन बेहतर होगा और वे राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय स्तर पर अधिक प्रभावी ढंग से प्रतिस्पर्धा कर सकेंगे। हरियाणा लंबे समय से देश को बड़ी संख्या में अंतरराष्ट्रीय और राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी देता रहा है। ऐसे में खेल प्रशासन में पारदर्शिता, जवाबदेही और आधुनिक तकनीकों का समावेश राज्य के खेल ढांचे को और मजबूत बना सकता है।

सीवर लाइन कार्य रुका तो नाराज पार्षद ने नगर निगम अधिकारी के दफ्तर पर जड़ा ताला

भारतेन्दु संवाददाता, फरीदाबाद

हरियाणा के फरीदाबाद में विकास कार्यों में देरी को लेकर नगर निगम और जनप्रतिनिधियों के बीच टकराव खुलकर सामने आ गया। वार्ड-43 के पार्षद दीपक यादव ने सीवर लाइन और सड़क निर्माण कार्य शुरू न होने से नाराज होकर नगर निगम के कार्यकारी अभियंता के कार्यालय पर ताला जड़ दिया। इस दौरान उनके साथ वार्ड-40 के पार्षद पवन कुमार सहित कई स्थानीय लोग भी मौजूद रहे। घटना के बाद निगम कार्यालय में कुछ समय के लिए हलचल का माहौल बन गया।

पार्षद दीपक यादव का कहना है कि उनके वार्ड में तिगांव रोड से लेकर सेक्टर-दो स्थित श्रीमती सुषमा स्वराज राजकीय महिला कॉलेज तक सीवर लाइन बिछाने और सीमेंटेड सड़क बनाने का कार्य प्रस्तावित है। इस परियोजना का उद्देश्य क्षेत्र के लोगों, विशेषकर कॉलेज आने-जाने वाली छात्राओं को बेहतर सुविधा उपलब्ध कराना है। उन्होंने बताया कि ठेकेदार निर्माण सामग्री और सीवर पाइप मौके पर पहुंचा चुका है, लेकिन इसके बावजूद काम शुरू नहीं कराया गया। पार्षद के अनुसार, जब उन्होंने ठेकेदार से देरी का कारण पूछा तो बताया गया कि कार्यकारी अभियंता डाल चंद शर्मा के निर्देश पर काम रोक दिया गया है। इससे नाराज होकर उन्होंने अभियंता के कार्यालय पर ताला लगा दिया और कहा कि यदि विकास कार्य ही नहीं कराने हैं तो अधिकारी के कार्यालय में बैठने का कोई औचित्य नहीं है।

काम में देरी पर पार्षद का अनोखा विरोध

वहीं, कार्यकारी अभियंता का कहना है कि लगातार बारिश के कारण निर्माण कार्य शुरू नहीं कराया गया है। उनका तर्क है कि बरसात के दौरान सीवर लाइन और सड़क निर्माण कराने से गुणवत्ता प्रभावित हो सकती है, इसलिए मौसम सामान्य होने के बाद कार्य शुरू किया जाएगा।

घटना की जानकारी मिलते ही नगर निगम के वरिष्ठ अधिकारियों ने स्थिति का संज्ञान लिया और दोनों पक्षों से बातचीत की। अधिकारियों ने आश्वासन दिया कि मौसम अनुकूल होते ही निर्माण कार्य शुरू कराया जाएगा। इस घटना के बाद विकास कार्यों में देरी और प्रशासनिक समन्वय को लेकर एक बार फिर सवाल उठने लगे हैं। स्थानीय लोगों ने भी मांग की है कि आवश्यक परियोजनाओं को बिना अनावश्यक देरी के पूरा कराया जाए, ताकि आम जनता को बेहतर बुनियादी सुविधाएं मिल सकें।

न्यूज ब्रीफ

दिल्ली स्वास्थ्य घोटाले की फाइलें गायब होने पर 'आप ' ने उठाए सवाल

एजेंसी, नई दिल्ली। आम आदमी पार्टी के दिल्ली प्रदेश अध्यक्ष सौरभ भारद्वाज ने दिल्ली सरकार पर 650 करोड़ रुपये के कथित स्वास्थ्य घोटाले से जुड़ी फाइलें गायब होने का आरोप लगाया है। उन्होंने कहा कि दवाइयों, चिकित्सा उपकरणों, बेडशीट, ओआरएस और एक्स-रे मशीनों की खरीद से जुड़े जरूरी दस्तावेज उपलब्ध नहीं हैं। भारद्वाज ने मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता से पूछा कि सुरक्षा व्यवस्था के बावजूद फाइलें कैसे गायब हुईं। उन्होंने खरीद प्रक्रिया में अनियमितताओं का आरोप लगाते हुए कहा कि कई वस्तुएं तय कीमत से कई गुना अधिक दरों पर खरीदी गईं। उन्होंने मामले की जांच की मांग की है।

महिला थप्पड़ मामले में डीसीपी तबादला मांग खारिज

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली हाई कोर्ट ने प्रदर्शन के दौरान महिला को थप्पड़ मारने के आरोपों का सामना कर रहे डीसीपी संदीप लांबा के तबादले की मांग वाली याचिका मंगलवार को खारिज कर दी। अदालत ने याची को संस्था की छवि खराब करने से बचने की हिदायत दी। कोर्ट ने कहा कि यदि अधिकारी ने कोई गलती की है तो उन्हें कानून के अनुसार परिणाम भुगतने होंगे, लेकिन निष्पक्ष जांच और सुनवाई के बिना किसी को दोषी नहीं ठहराया जा सकता। अदालत ने स्पष्ट किया कि केवल वीडियो के आधार पर अधिकारी को जिम्मेदारी से हटाना उचित नहीं होगा।

वेंडिंग प्लान पर हाई कोर्ट ने सरकार को घेरा

एजेंसी, नई दिल्ली। नई दिल्ली नगर पालिका परिषद के टाउन वेंडिंग प्लान को संशोधन के लिए वापस भेजने के दिल्ली सरकार के फैसले पर दिल्ली हाई कोर्ट ने सवाल उठाए हैं। न्यायमूर्ति प्रतिभा एम सिंह और न्यायमूर्ति विकास महाजन की पीठ ने कहा कि सरकार अंतिम निर्णय लेने से बचती नजर आ रही है। अदालत ने सरकार की उस दलील को भी खारिज कर दिया, जिसमें टाउन वेंडिंग कमेटी की क्षमता और कार्यकाल पर दोबारा विचार की बात कही गई थी। कोर्ट ने यह टिप्पणी स्ट्रीट वेंडर्स एक्ट और टाउन वेंडिंग प्लान लागू करने से जुड़ी याचिकाओं की सुनवाई के दौरान की।

दिल्ली रिज को मिलेगा प्राकृतिक स्वरूप, डीडीए शुरू करेगा सुधार अभियान

एजेंसी, नई दिल्ली। राजधानी के रिज क्षेत्र को पुराने प्राकृतिक स्वरूप में वापस लाने की तैयारी शुरू हो गई है। दिल्ली विकास प्राधिकरण (डीडीए) यहां पर्यावरण सुधार अभियान चलाएगा। पहले चरण में रिज के करीब 120 हेक्टेयर क्षेत्र को शामिल किया जाएगा। योजना का उद्देश्य केवल पौधारोपण करना नहीं, बल्कि देशी पेड़-पौधों और प्राकृतिक वातावरण को पुनर्जीवित करना है। उपराज्यपाल तरनजीत सिंह संधू ने डीडीए को वैज्ञानिक तरीके से रिज क्षेत्र के संरक्षण के निर्देश दिए हैं। डीडीए के अनुसार, जुलाई से शुरू पौधारोपण अभियान के तहत अब तक दिल्ली में 8,29,313 पौधे लगाए जा चुके हैं।

दिल्ली में लागू होगा इंदौर मॉडल, स्वच्छता अभियान को मिलेगी रफ्तार

एजेंसी, नई दिल्ली। दिल्ली को स्वच्छ और बेहतर बनाने के लिए उपराज्यपाल टीएस संधू ने इंदौर नगर निगम के स्वच्छता मॉडल को अपनाने के निर्देश दिए हैं। उन्होंने निगम अधिकारियों को एक जोन में इसे पायलट परियोजना के रूप में लागू करने की संभावनाएं तलाशने को कहा है। समीक्षा बैठक में स्वच्छता, प्रदूषण, जलभराव, नालों की सफाई, डेंगू-मलेरिया नियंत्रण और पीएम-उदय योजना की प्रगति पर चर्चा हुई। अधिकारियों को इंदौर के ठोस कचरा प्रबंधन मॉडल का अध्ययन करने के निर्देश दिए गए हैं। इंदौर में गीले और सूखे कचरे का स्रोत स्तर पर निस्तारण किया जाता है, जिससे लैंडफिल साइटों पर कचरा कम पहुंचता है।इस पहल से दिल्ली में कचरा प्रबंधन व्यवस्था को मजबूत करने और पर्यावरण संरक्षण को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है। अधिकारियों को जल्द कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए गए हैं।

बारिश से दिल्ली–एनसीआर बेहाल, जलभराव ने बढ़ाई परेशानी

मूसलाधार बारिश से दिल्ली-एनसीआर में जनजीवन प्रभावित, जलभराव और जाम से लोगों की बढ़ीं मुश्किलें

एजेंसी, नई दिल्ली

मंगलवार को हुई तेज बारिश के बाद दिल्ली एनसीआर के कई इलाकों में जलभराव की समस्या पैदा हो गई। बारिश ने जहां लोगों को गर्मी से राहत दी, वहीं दूसरी ओर सड़कों पर भरे पानी और यातायात जाम ने लोगों की परेशानियां बढ़ा दीं। दिल्ली के यमुनापार क्षेत्र से लेकर गुरुग्राम, नोएडा और गाजियाबाद तक कई स्थानों पर बारिश का असर देखने को मिला।

यमुनापार के कई इलाकों में बारिश के बाद सड़कें जलमग्न हो गईं। विकास मार्ग, कड़कड़डूमा, गांधी नगर, प्रीत विहार, लक्ष्मी नगर, अशोक नगर, दुर्गापुरी, शाहदरा, दिलशाद गार्डन, भजनपुरा, मौजपुर, सीलमपुर और खजूरी खास सहित कई क्षेत्रों में पानी भर गया। जलभराव के कारण कई वाहन बीच रास्ते में फंस गए और प्रमुख मार्गों पर लंबा जाम लग गया।

कार्यालय जाने वाले लोगों को सबसे ज्यादा परेशानी का सामना करना पड़ा। विकास मार्ग और लक्ष्मी नगर जैसे व्यस्त इलाकों में यातायात की रफ्तार काफी धीमी हो गई। कड़कड़डूमा, प्रीत विहार और गांधी नगर में सड़क पर पानी भरने से दोपहिया वाहन चालकों को काफी दिक्कत हुई। कई जगह लोग पानी के बीच से निकलने को मजबूर दिखाई दिए।

अशोक नगर, दुर्गापुरी, भजनपुरा और खजूरी खास जैसे इलाकों में जलनिकासी व्यवस्था पर सवाल उठने लगे। स्थानीय लोगों का कहना है कि हर साल मानसून के दौरान यही स्थिति बनती है, लेकिन स्थायी समाधान नहीं हो पा रहा है। लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि जलभराव वाले स्थानों की पहचान कर वहां बेहतर जलनिकासी व्यवस्था की जाए। बारिश का असर बाजारों पर भी देखने को मिला।

कई जगह यातायात हुआ प्रभावित

वहीं गुरुग्राम में भी करीब 35 से 40 मिनट की बारिश ने जल निकासी व्यवस्था की स्थिति उजागर कर दी। शहर के मदनपुरी, न्यू कॉलोनी, सेक्टर–47, सेक्टर–5, सेक्टर–9 और रेलवे रोड सहित कई इलाकों में सड़कें तालाब में बदल गईं। पानी भरने से वाहन चालकों को भारी परेशानी हुई और कई जगह यातायात प्रभावित हुआ।

कई अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया

गुरुग्राम प्रशासन ने बारिश के बाद स्थिति को देखते हुए सतर्कता बढ़ा दी है। अधिकारियों को फील्ड में भेजा गया और जलभराव वाले क्षेत्रों की निगरानी शुरू की गई।

दिल्ली के वीआईपी परिसरों में बंदरों का बढ़ता आतंक देखकर अब मंकी एक्सपर्ट संभालेंगे मोर्चा

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली के कई इलाकों में लोगों के लिए परेशानी का कारण बन चुके बंदरों का आतंक अब राजधानी के वीआईपी क्षेत्रों तक पहुंच गया है। सिविल लाइन्स इलाके में स्थित दिल्ली विधानसभा भवन, मुख्यमंत्री और कैबिनेट मंत्रियों के आवास समेत उपराज्यपाल के आवास लोक निवास परिसर में भी बंदरों की आवाजाही बढ़ गई है। इससे सुरक्षा व्यवस्था और सरकारी कामकाज दोनों प्रभावित हो रहे हैं।

सबसे ज्यादा समस्या दिल्ली विधानसभा भवन और लोक निवास परिसर में देखने को मिल रही है। सूत्रों के अनुसार कई बार यहां आने वाले मेहमानों और अधिकारियों की बैठकों के दौरान अतिरिक्त सुरक्षाकर्मियों को केवल बंदरों की गतिविधियों पर नजर रखने के लिए तैनात करना पड़ता है। बंदरों के झुंड परिसर में पहुंचकर कर्मचारियों और अधिकारियों के लिए परेशानी पैदा कर रहे हैं। स्थिति को देखते हुए लोक निर्माण विभाग ने लोक निवास परिसर में बंदरों को नियंत्रित करने के लिए मंकी एक्सपर्ट की सेवाएं लेने का फैसला किया है। इसके लिए विभाग की ओर से टेंडर जारी किया गया है। चयनित एजेंसी प्रशिक्षित विशेषज्ञ उपलब्ध कराएगी, जो बिना किसी नुकसान के बंदरों को परिसर से दूर रखने का काम करेंगे।

दरअसल, सिविल लाइन्स क्षेत्र के आसपास हरित क्षेत्र और रिज का जंगल होने के कारण यहां लंबे समय से बंदरों की मौजूदगी बनी हुई है। भोजन की तलाश में बंदर अक्सर सरकारी भवनों, कार्यालयों और आवासीय परिसरों में पहुंच जाते हैं। कई बार बंदर कर्मचारियों से खाने का सामान छीन लेते हैं और दस्तावेज या अन्य सामान लेकर भागने जैसी घटनाएं भी सामने आती रही हैं।

दिल्ली विधानसभा परिसर में पहले से ही मंकी एक्सपर्ट की व्यवस्था की गई है, जिससे वहां बंदरों की समस्या में कुछ कमी आई है। अब इसी व्यवस्था को लोक निवास परिसर में भी लागू करने की तैयारी है।

कांवड़ यात्रा को लेकर प्रशासन अलर्ट सुरक्षा और सुविधाओं पर विशेष ध्यान

एजेंसी, नई दिल्ली

क्यूआर कोड से मिलेगी जानकारी, नियमों के पालन पर प्रशासन सख्त

आगामी कांवड़ यात्रा और त्योहारों को शांतिपूर्ण और सुरक्षित तरीके से संपन्न कराने के लिए पुलिस–प्रशासन ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी क्रम में सोमवार शाम बाबूगढ़ थाने में सीओ सिटी अनीता चौहान की अध्यक्षता में एक महत्वपूर्ण बैठक आयोजित की गई। बैठक में कांवड़ यात्रा से जुड़े आयोजकों, जनप्रतिनिधियों और विभिन्न विभागों के अधिकारियों ने हिस्सा लिया।

बैठक में कांवड़ यात्रा के दौरान सुरक्षा व्यवस्था, यातायात प्रबंधन और श्रद्धालुओं की सुविधाओं को लेकर विस्तार से चर्चा की गई। अधिकारियों ने स्पष्ट किया कि यात्रा के दौरान नियमों का पालन हर हाल में सुनिश्चित किया जाएगा। बैठक में यह निर्णय लिया गया कि जमीन से 12 फीट से अधिक ऊंचाई वाले तेज ध्वनि यंत्रों के संचालन की अनुमति नहीं होगी।

सीओ सिटी अनीता चौहान ने कहा कि कांवड़ यात्रियों की सुरक्षा प्रशासन की पहली प्राथमिकता है। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि कांवड़ मार्गों पर सभी आवश्यक व्यवस्थाएं समय रहते पूरी कर ली जाएं। श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए मार्गों की जानकारी, पुलिस अधिकारियों के संपर्क नंबर, यातायात डायवर्जन और अन्य जरूरी सूचनाएं क्यूआर कोड के माध्यम से उपलब्ध कराई जाएंगी।

बैठक के दौरान ग्रामीणों ने कई समस्याएं भी अधिकारियों के सामने रखीं। ग्रामीणों ने उपेड़ा फ्लाईओवर से कुचेसर चौपला होते हुए बाबूगढ़ मार्ग पर बने गड्ढों को ठीक कराने की मांग की। इसके अलावा बड़ली गांव में 11 हजार वोल्ट की नीची हाइटेंशन लाइन को लेकर भी चिंता जताई गई। अधिकारियों ने संबंधित विभागों को इन समस्याओं का जल्द समाधान करने के निर्देश दिए।

सिकंदरपुर काकोड़ी में गोमुख पहुंचने के बाद बढ़ने वाली श्रद्धालुओं की भीड़ को देखते हुए विशेष इंतजाम करने पर भी चर्चा हुई। शिविर संचालकों को निर्देश दिए गए कि बिजली आपूर्ति के लिए अवैध कनेक्शन का इस्तेमाल न करें और अस्थायी बिजली कनेक्शन लेकर ही व्यवस्था करें।

दिल्ली विधानसभा सुरक्षा चूक मामले में आरोपी की मानसिक जांच का आदेश

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली विधानसभा में सुरक्षा चूक के मामले में आरोपित सरबजीत सिंह की मानसिक स्थिति का आकलन किया जाएगा। तीस हजारी कोर्ट ने इहबास अस्पताल को निर्देश दिया है कि वह मेडिकल बोर्ड गठित कर सरबजीत की मानसिक स्थिति की जांच करे और रिपोर्ट दे कि वह अदालत में अपना बचाव करने की स्थिति में है या नहीं। मामले की अगली सुनवाई 6 अगस्त को होगी।

अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश अंकुर जैन ने यह आदेश सरबजीत सिंह की नियमित जमानत याचिका पर सुनवाई करते हुए दिया। सुनवाई के दौरान सरबजीत की ओर से पेश वकील अंशुल शुक्ला ने अदालत को बताया कि आरोपी मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्या से जूझ रहा है। उन्होंने कहा कि मानसिक स्वास्थ्य देखभाल कानून के तहत याचिका दायर की गई है और जांच अधिकारी सरबजीत के चिकित्सा दस्तावेजों का सत्यापन कर चुके हैं।

वकील ने बताया कि सरबजीत बाइपोलर डिसऑर्डर से पीड़ित है और उसकी मानसिक स्थिति का सही आकलन करने के लिए मेडिकल बोर्ड गठित किया जाना जरूरी है। दिल्ली पुलिस की ओर से पेश वकील अतुल श्रीवास्तव ने इस मांग का विरोध नहीं किया। इसके बाद अदालत ने इहबास अस्पताल को मेडिकल बोर्ड बनाने का निर्देश दिया।

अदालत ने जेल प्रशासन को भी निर्देश दिए हैं कि जरूरत पड़ने पर सरबजीत को इहबास अस्पताल के चिकित्सकों के सामने पेश किया जाए। इससे पहले हुई सुनवाई में सरबजीत के वकील ने उसकी हिरासत का विरोध करते हुए कहा था कि उसकी मानसिक स्थिति सामान्य नहीं है।

वकील ने अदालत को बताया था कि सरबजीत अचानक बिना किसी को बताए अपनी बहन से मिलने चंडीगढ़ चला गया था। वहां वह एक गुरुद्वारे में भी गया था। बाद में जब उसे अपने भतीजे के लापता होने की जानकारी मिली तो वह दिल्ली वापस आया।

नई पाइपलाइन कार्य से जल आपूर्ति पर असर

एजेंसी, नई दिल्ली । पश्चिमी दिल्ली के कई इलाकों में जल आपूर्ति व्यवस्था को बेहतर बनाने के लिए नई पाइपलाइन बिछाने का काम पूरा किया गया है। अब इस 1100 मिमी व्यास वाली मुख्य पाइपलाइन को पुरानी व्यवस्था से जोड़ने के लिए इंटरकनेक्शन का कार्य किया जाएगा।

जल आपूर्ति विभाग के अनुसार, यह कार्य ख्याला बूस्टर पंपिंग स्टेशन के अंदर, ख्याला बीपीएस के गेट पर और रिंग रोड स्थित शिवाजी कॉलेज के पास दो स्थानों पर किया जाना है। इस काम के चलते 29 जुलाई को सुबह 10 बजे से 30 जुलाई को सुबह 2 बजे तक कई क्षेत्रों में पानी की आपूर्ति कम दबाव से होगी।

विभाग ने लोगों से अपील की है कि वे इस अवधि में पानी का उचित भंडारण कर लें और जरूरत के अनुसार पानी का इस्तेमाल करें। अधिकारियों का कहना है कि पाइपलाइन इंटरकनेक्शन का कार्य पूरा होने के बाद पश्चिमी दिल्ली के क्षेत्रों में जल आपूर्ति व्यवस्था और बेहतर हो जाएगी।

एनसीआर में दौड़ेंगे चार नए नमो भारत कॉरिडोर, बढ़ेगी क्षेत्रीय कनेक्टिविटी

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली से करनाल, नोएडा एयरपोर्ट तक तेज रफ्तार यात्रा का खुलेगा रास्ता

राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र में तेज और बेहतर रेल कनेक्टिविटी विकसित करने की दिशा में बड़ा कदम उठाया जा रहा है। राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र परिवहन निगम (एनसीआरटीसी) ने एनसीआर के विभिन्न हिस्सों को जोड़ने के लिए चार नए नमो भारत कॉरिडोर की विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार कर केंद्र सरकार को सौंप दी है। इन प्रस्तावित कॉरिडोर के शुरू होने से दिल्ली और आसपास के प्रमुख शहरों के बीच आवागमन आसान होने की उम्मीद है।

आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने सोमवार को राज्यसभा में एक लिखित उत्तर के माध्यम से यह जानकारी दी। उन्होंने बताया कि एनसीआरटीसी ने दिल्ली–करनाल, दिल्ली–बावल, बावल–बहरोड़ और गाजियाबाद–नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट नमो भारत कॉरिडोर के लिए डीपीआर तैयार की है। फिलहाल इन चारों परियोजनाओं पर केंद्र सरकार स्तर पर विचार किया जा रहा है।

प्रस्तावित कॉरिडोर के निर्माण से एनसीआर के कई महत्वपूर्ण शहरों के बीच तेज गति वाली परिवहन सुविधा उपलब्ध होगी। इससे सड़क मार्ग पर बढ़ते यातायात दबाव को कम करने में भी मदद मिलने की संभावना है। खासकर नोएडा इंटरनेशनल एयरपोर्ट को नमो भारत नेटवर्क से जोड़ने की योजना को क्षेत्रीय संपर्क के लिहाज से महत्वपूर्ण माना जा रहा है।

राज्य मंत्री ने बताया कि एनसीआर प्लानिंग बोर्ड ने एनसीआर–2032 के लिए तैयार परिवहन संबंधी कार्यात्मक योजना में क्षेत्र के प्रमुख शहरों को जोड़ने वाले आठ आरआरटीएस कॉरिडोर की पहचान की है। इन कॉरिडोर के माध्यम से दिल्ली को आसपास के राज्यों और शहरों से आधुनिक परिवहन नेटवर्क के जरिए जोड़ा जाएगा।

दिल्ली की महिलाओं को बड़ी सौगात, हर माह मिलेंगे 2500 रुपए

एजेंसी, नई दिल्ली

दिल्ली सरकार ने महिलाओं को आर्थिक रूप से मजबूत बनाने की दिशा में बड़ा कदम उठाया है। मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को कैबिनेट बैठक के बाद घोषणा की कि दिल्ली की पात्र महिलाओं के लिए 2500 रुपये प्रतिमाह वित्तीय सहायता योजना को मंजूरी दे दी गई है। इस योजना के तहत योग्य महिलाओं को हर महीने आर्थिक सहायता प्रदान की जाएगी।

मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने बताया कि योजना के लिए पंजीकरण प्रक्रिया 1 अगस्त से शुरू होगी। इसके लिए सरकार की ओर से पंजीकरण पोर्टल शुरू किया जाएगा, जहां पात्र महिलाएं आवेदन कर सकेंगी। आवेदन मिलने के बाद संबंधित विभागों द्वारा दस्तावेजों और पात्रता की जांच की जाएगी। जांच प्रक्रिया पूरी होने के बाद लाभार्थी महिलाओं को सहायता राशि जारी की जाएगी।

मुख्यमंत्री ने उम्मीद जताई कि रक्षाबंधन के आसपास योजना की पहली किस्त लाभार्थी महिलाओं के खातों में पहुंचाई जा सकती है। उन्होंने कहा कि सरकार ने महिलाओं से किए गए वादे को पूरा किया है और यह कदम दिल्ली की महिलाओं के लिए राहत और खुशी का अवसर है।

रेखा गुप्ता ने कहा कि दिल्ली सरकार महिलाओं के कल्याण और सशक्तीकरण के लिए लगातार काम कर रही है। उन्होंने कहा कि आर्थिक सहायता मिलने से महिलाओं को अपने दैनिक खर्चों को पूरा करने में मदद मिलेगी और वे अधिक आत्मनिर्भर बन सकेंगी।

सरकार का मानना है कि यह योजना महिलाओं की आर्थिक स्थिति को बेहतर बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएगी। वित्तीय सहायता से जरूरतमंद महिलाओं को घरेलू जरूरतों, शिक्षा, स्वास्थ्य और अन्य आवश्यक कार्यों में सहयोग मिलेगा।

दिल्ली सरकार की इस योजना को महिलाओं के लिए एक महत्वपूर्ण सामाजिक सुरक्षा पहल के रूप में देखा जा रहा है। योजना लागू होने के बाद बड़ी संख्या में महिलाओं को इसका लाभ मिलने की उम्मीद है। हालांकि लाभ प्राप्त करने के लिए महिलाओं को निर्धारित पात्रता मानकों को पूरा करना होगा।

दिल्ली में बढ़ा हेपेटाइटिस खतरा, लाखों लोग संक्रमण की चपेट में

बरसात में हेपेटाइटिस ए और ई का खतरा बढ़ा, विशेषज्ञों ने सावधानी बरतने की सलाह दी

एजेंसी, नई दिल्ली

राष्ट्रीय राजधानी दिल्ली में वायरल हेपेटाइटिस एक गंभीर स्वास्थ्य चुनौती बनता जा रहा है। वैज्ञानिक अध्ययनों के अनुसार दिल्ली में करीब 1.7 लाख लोग हेपेटाइटिस–बी और लगभग ढाई लाख लोग हेपेटाइटिस–सी संक्रमण से प्रभावित हैं। विशेषज्ञों का कहना है कि मानसून के दौरान हेपेटाइटिस–ए और हेपेटाइटिस–ई के मामलों में भी बढ़ोतरी की आशंका रहती है। दूषित पानी, खराब साफ–सफाई और संक्रमित भोजन इसके प्रमुख कारण माने जाते हैं।

दिल्ली के बड़े सरकारी अस्पतालों में हेपेटाइटिस–बी और सी से पीड़ित मरीज लगातार इलाज और जांच के लिए पहुंच रहे हैं। एम्स, सफदरजंग अस्पताल, जीबी पंत अस्पताल और लोकनायक अस्पताल सहित कई संस्थानों में ऐसे मरीजों की संख्या बनी हुई है। बरसात के मौसम में दूषित पानी के कारण पीलिया और हेपेटाइटिस–ए व ई के मामलों में वृद्धि देखी जाती है। बच्चों, गर्भवती महिलाओं और पहले से लीवर संबंधी बीमारी से जूझ रहे लोगों में इसका खतरा अधिक रहता है।

देश में हर साल लाखों मौतें : केंद्रीय स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय के राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम के अनुसार देश में वायरल हेपेटाइटिस के कारण हर वर्ष करीब 2.72 लाख लोगों की मौत होती है। इनमें अधिकतर मौतें लीवर सिरोसिस और लीवर कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों के कारण होती हैं।

स्वास्थ्य मंत्रालय के अनुसार देश में करीब चार करोड़ लोग लंबे समय से हेपेटाइटिस–बी संक्रमण से प्रभावित हैं, जबकि लगभग 1.2 करोड़ लोग हेपेटाइटिस–सी संक्रमण की चपेट में हैं। विशेषज्ञों के अनुसार भारत में हेपेटाइटिस–बी और सी के मामलों की बड़ी चुनौती यह है कि शुरुआती चरण में इसके लक्षण स्पष्ट नहीं दिखाई देते।

हेपेटाइटिस को कहा जाता है साइलेंट किलर : चिकित्सकों का कहना है कि कई मरीजों को संक्रमण की जानकारी तब मिलती है, जब उनका लीवर काफी प्रभावित हो चुका होता है। इसी कारण हेपेटाइटिस–बी और सी को साइलेंट किलर भी कहा जाता है। समय पर जांच और इलाज नहीं मिलने पर लीवर सिरोसिस, लीवर फेलियर और लीवर कैंसर का खतरा बढ़ जाता है।

हेपेटाइटिस–बी संक्रमित रक्त, असुरक्षित इंजेक्शन, असुरक्षित यौन संबंध और संक्रमित मां से बच्चे में फैल सकता है। वहीं हेपेटाइटिस–ए और ई मुख्य रूप से दूषित पानी और भोजन के जरिए फैलते हैं। विशेषज्ञों के अनुसार हेपेटाइटिस–बी से बचाव के लिए प्रभावी टीका उपलब्ध है, जबकि हेपेटाइटिस–सी का आधुनिक दवाओं से इलाज संभव है।

सरकार चला रही नियंत्रण कार्यक्रम : भारत सरकार ने वर्ष 2018 में राष्ट्रीय वायरल हेपेटाइटिस नियंत्रण कार्यक्रम शुरू किया था। इसका उद्देश्य वर्ष 2030 तक वायरल हेपेटाइटिस को सार्वजनिक स्वास्थ्य के लिए बड़ा खतरा नहीं रहने देना है। कार्यक्रम के तहत हेपेटाइटिस–बी टीकाकरण, गर्भवती महिलाओं की जांच, जोखिम वाले समूहों की स्क्रीनिंग और निशुल्क जांच व इलाज की सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है।

विशेषज्ञों का कहना है कि समय पर जांच, टीकाकरण, स्वच्छ पेयजल, बेहतर साफ–सफाई और नियमित स्वास्थ्य जांच के माध्यम से हेपेटाइटिस से होने वाली मौतों को काफी हद तक रोका जा सकता है। लोगों में जागरूकता बढ़ाना और शुरुआती स्तर पर संक्रमण की पहचान करना इस बीमारी पर नियंत्रण पाने के लिए सबसे जरूरी कदम हैं।

स्वास्थ्य विशेषज्ञों ने लोगों से अपील की है कि वे किसी भी तरह के लक्षण नजर आने पर तुरंत चिकित्सकीय सलाह लें। नियमित जांच और सावधानी बरतकर हेपेटाइटिस संक्रमण को गंभीर रूप लेने से रोका जा सकता है। खासकर मानसून के दौरान साफ पानी पीना और स्वच्छ भोजन का सेवन बेहद जरूरी है।

उमर अब्दुल्ला ने विभागों को पूंजीगत व्यय बढ़ाने के निर्देश दिए

मुख्यमंत्री ने कहा- उपलब्ध धनराशि का समय पर उपयोग नहीं करना प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है

◆ एसएएससीआई योजना की समीक्षा, हर रुपए के सदुपयोग के निर्देश

निधियों के उपयोग में देरी पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जताई चिंता

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने मंगलवार को सिविल सचिवालय में पूंजीगत व्यय को लेकर उच्च स्तरीय समीक्षा बैठक की अध्यक्षता की। बैठक में उन्होंने सभी विभागों को विकास कार्यों में तेजी लाने और उपलब्ध निधियों का समय पर उपयोग सुनिश्चित करने के निर्देश दिए।

मुख्यमंत्री ने कहा कि बुनियादी ढांचे के विकास, सार्वजनिक सेवाओं की बेहतर आपूर्ति और आर्थिक प्रगति के लिए धनराशि का सही समय पर इस्तेमाल बेहद जरूरी है। मुख्यमंत्री ने कहा कि कई बार विभागों में धन उपलब्ध होने के बावजूद उसका उपयोग समय पर नहीं हो पाता, जो प्रशासनिक अक्षमता को दर्शाता है।

उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिए कि वित्तीय वर्ष के अंतिम महीनों तक खर्च को टालने की परंपरा को खत्म किया जाए और योजनाओं को समयबद्ध तरीके से पूरा किया जाए। उमर अब्दुल्ला ने कहा कि समीक्षा बैठक वित्तीय वर्ष की शुरुआत में ही इसलिए आयोजित की गई है, ताकि कमियों की पहचान कर समय रहते सुधारात्मक कदम उठाए जा सकें। उन्होंने कहा कि जम्मू और कश्मीर के विभिन्न क्षेत्रों में विकास कार्यों के लिए पर्याप्त समय उपलब्ध है और जारी की गई धनराशि का बेहतर उपयोग किया जाना चाहिए। बैठक में मुख्यमंत्री ने राज्यों को पूंजी निवेश के लिए विशेष सहायता योजना (एसएएससीआई) की भी समीक्षा की।

उन्होंने विभागों को निर्देश दिया कि योजना के तहत उपलब्ध धनराशि का पूरी तरह इस्तेमाल सुनिश्चित किया जाए। उन्होंने चेतावनी दी कि यदि चालू वित्त वर्ष में आवंटित राशि का उपयोग नहीं किया गया तो भविष्य में जम्मू-कश्मीर को मिलने वाले आवंटन पर असर पड़ सकता है। उन्होंने कहा कि एसएएससीआई भाग-1 के तहत उपलब्ध प्रत्येक रुपये का उपयोग विकास कार्यों में किया जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने विभागों को पात्र परियोजनाओं की पहचान करने और उन्हें जल्द शुरू करने के निर्देश दिए। उन्होंने मंत्रियों से भी कहा कि वे योजना के सुधार संबंधी लक्ष्यों की नियमित समीक्षा करें, ताकि जम्मू-कश्मीर अतिरिक्त वित्तीय सहायता प्राप्त करने के योग्य बन सके।

बेहतर तालमेल से विकास कार्यों को आगे बढ़ाने का आह्वान

मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने कहा कि विभागों को केवल धनराशि की उपलब्धता का इंतजार करने के बजाय भविष्य की परियोजनाओं के लिए पहले से बेहतर योजना तैयार करनी चाहिए। उन्होंने कहा कि प्रशासनिक स्वीकृति और निविदा प्रक्रिया पूरी हो चुकी योजनाओं पर तुरंत काम शुरू किया जाए। बैठक में अधिकारियों को निर्देश दिए गए कि विकास कार्यों की गति बढ़ाने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ कार्य करें।

बारामूला गैंगरेप और वीडियो मामले में दो आरोपी गिरफ्तार

भारतेंदु संवाददाता, बारामूला। जम्मू-कश्मीर के बारामूला जिले में युवती से कथित गैंगरेप और हमले का वीडियो बनाने के मामले में पुलिस ने दो आरोपियों को गिरफ्तार किया है। पुलिस के अनुसार, यह कार्रवाई तकनीकी सबूतों और ह्यूमन इंटेलिजेंस के आधार पर की गई लंबी जांच के बाद हुई। बारामूला के एसएसपी गुरिंदरपाल सिंह ने बताया कि पीड़िता ने 25 जुलाई को पुलिस स्टेशन पहुंचकर शिकायत दर्ज कराई थी। उसने आरोप लगाया कि वह अपने एक पुरुष मित्र के साथ जलशेरी ड्रंगबल घूमने गई थी, जहां दो लोगों ने उन्हें रोककर मारपीट की और युवती के साथ यौन उत्पीड़न किया। आरोपियों ने घटना का वीडियो भी बनाया था। पुलिस ने जांच के दौरान आरोपियों की पहचान शाकिर अहमद लोन और मोहम्मद अशरफ के रूप में की। दोनों जलशेरी के रहने वाले हैं। पुलिस ने बताया कि दोनों आरोपियों को हिरासत में लेकर आगे की कानूनी कार्रवाई की जा रही है। मामले की जांच जारी है।

अनियंत्रित होकर 150 फीट नीचे गिरा ट्रैक्टर

रियासी में ट्रैक्टर खाई में गिरने से 17 साल के लड़के की मौत

चसाना से सांगलीकोट जा रहा ट्रैक्टर हुआ हादसे का शिकार।

भारतेंदु संवाददाता, रियासी। जम्मू-कश्मीर के रियासी जिले में मंगलवार को एक दर्दनाक सड़क हादसे में 17 वर्षीय किशोर की मौत हो गई। हादसा उस समय हुआ जब किशोर ट्रैक्टर चला रहा था और अचानक वाहन अनियंत्रित होकर सड़क से फिसलते हुए खाई में जा गिरा। अधिकारियों के अनुसार, यह दुर्घटना जिले के चसाना इलाके में चमालू मढ़ के पास हुई।

ट्रैक्टर चसाना से सांगलीकोट की ओर जा रहा था, तभी चालक का वाहन पर नियंत्रण नहीं रहा। इसके बाद ट्रैक्टर पहाड़ी से करीब 150 फीट नीचे लुढ़क गया। हादसे में ट्रैक्टर चालक मोहम्मद अशरफ की मौके पर ही मौत हो गई। मृतक चसाना क्षेत्र के हमोसन गांव का रहने वाला था। घटना की सूचना मिलते ही स्थानीय लोगों और पुलिस की टीम मौके पर पहुंची। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए चसाना स्थित प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र भेज दिया है। अधिकारियों ने बताया कि मामले का संज्ञान लेते हुए जांच शुरू कर दी गई है। पुलिस हादसे के कारणों का पता लगाने में जुटी है।

श्रीनगर रोजगार मेले में मनोज सिन्हा ने युवाओं से बड़े सपने देखने और नवाचार अपनाने का किया आह्वान

◆ रोजगार मेले में युवाओं को मिला सफलता का मंत्र सीखते रहने की दी सीख

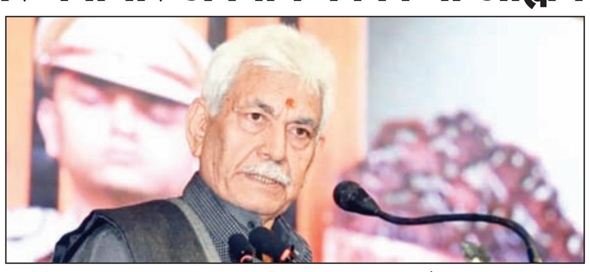

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने युवाओं से जीवन में बड़े लक्ष्य निर्धारित करने, लगातार सीखते रहने और नई सोच के साथ आगे बढ़ने का आह्वान किया है। श्रीनगर में आयोजित रोजगार मेले को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि युवा केवल रोजगार तलाशने वाले नहीं हैं, बल्कि वे देश के भविष्य के निर्माता हैं।

भारत के विकास की दिशा तय करने में युवाओं की भूमिका सबसे महत्वपूर्ण है। उपराज्यपाल ने युवाओं को सफलता के तीन प्रमुख मंत्र देते हुए कहा कि पहला मंत्र है बड़े सपने देखना, दूसरा जीवनभर सीखने की आदत बनाए रखना और तीसरा नवाचार को अपनाना। उन्होंने कहा कि बदलते समय में वही लोग आगे बढ़ते हैं, जो नई तकनीक, नए विचार और नए अवसरों को स्वीकार करते हैं।

मनोज सिन्हा ने कहा कि आज के युवा अपनी प्रतिभा, मेहनत और रचनात्मक सोच के बल पर नई ऊंचाइयों को छू सकते हैं। उन्होंने कहा कि रोजगार केवल नौकरी पाने तक सीमित नहीं होना चाहिए, बल्कि युवाओं को आत्मनिर्भर बनने और नए अवसर पैदा करने की दिशा में भी आगे बढ़ना चाहिए। उन्होंने कहा कि सरकार युवाओं के कौशल विकास और रोजगार के अवसर बढ़ाने के लिए लगातार प्रयास कर रही है। रोजगार मेले इसी दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल हैं, जहां युवाओं को अपनी योग्यता के अनुसार अवसर मिल रहे हैं।

उन्होंने चयनित युवाओं को शुभकामनाएं देते हुए कहा कि वे ईमानदारी और समर्पण के साथ अपने दायित्वों का निर्वहन करें। उपराज्यपाल ने कहा कि नवाचार किसी भी देश की प्रगति की आधारशिला होता है। युवाओं को समस्याओं के समाधान के लिए नई सोच विकसित करनी चाहिए और अपने विचारों को धरातल पर उतारने का प्रयास करना चाहिए।

जम्मू-कश्मीर में 9.70 लाख से ज्यादा स्मार्ट मीटर स्थापित

◆ राज्य में 64.8% स्मार्ट मीटर स्थापित, बिजली चोरी में कमी

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। बिजली वितरण व्यवस्था को बेहतर बनाने की दिशा में जम्मू-कश्मीर ने बड़ी उपलब्धि हासिल की है। केंद्र सरकार की पुनरुत्थान वितरण क्षेत्र योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने के मामले में जम्मू-कश्मीर ने राष्ट्रीय औसत को पीछे छोड़ दिया है।

केंद्रीय ऊर्जा मंत्रालय के ताजा आंकड़ों के अनुसार, 30 जून 2026 तक जम्मू-कश्मीर में स्वीकृत 14.97 लाख से अधिक स्मार्ट मीटरों में से 9,70,776 मीटर सफलतापूर्वक लगाए जा चुके हैं। यह कुल लक्ष्य का 64.8 प्रतिशत है। वहीं देशभर में आरडीएसएस योजना के तहत स्मार्ट मीटर लगाने की औसत दर केवल 28.2 प्रतिशत है।

केंद्रीय ऊर्जा राज्य मंत्री श्रीपाद नाईक की ओर से राज्यसभा में प्रस्तुत आंकड़ों में जम्मू-कश्मीर के इस प्रदर्शन की जानकारी दी गई। अधिकारियों के अनुसार, स्मार्ट मीटर लगने से बिजली वितरण प्रणाली में पारदर्शिता आएगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं मिल सकेंगी। स्मार्ट मीटर के जरिए उपभोक्ता मोबाइल ऐप के माध्यम से बिजली खपत की जानकारी आसानी से देख सकेंगे। इसके अलावा प्रीपेड सुविधा, बिजली बिल प्रबंधन और ऊर्जा बचत में भी मदद मिलेगी। माना जा रहा है कि स्मार्ट मीटर व्यवस्था लागू होने से बिजली चोरी पर नियंत्रण लगाने में भी सहायता मिलेगी।

जम्मू-पुंछ हाईवे पर टाटा मोबाइल और ऑटो की टक्कर, चार घायल

भारतेंदु संवाददाता, राजौरी। जम्मू-पुंछ नेशनल हाईवे पर मंगलवार को सड़क हादसे में चार लोग घायल हो गए। यह दुर्घटना राजौरी जिले के मुरादपुर क्षेत्र में हुई, जहां टाटा मोबाइल और लोड कैरियर ऑटो के बीच जोरदार टक्कर हो गई। हादसे में घायल चारों लोगों को उपचार के लिए गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज से जुड़े राजौरी अस्पताल में भर्ती कराया गया। घायलों की पहचान भवानी नौशेरा निवासी नीरज कुमार (25), खोट धारा निवासी समीर अहमद (24), पालामा निवासी शुभम शर्मा (22) और खोट धारा निवासी मोहम्मद सलीम (20) के रूप में हुई है। अस्पताल सूत्रों के अनुसार, टाटा मोबाइल चालक नीरज कुमार को गंभीर चोटें आई हैं। हादसे में शामिल वाहनों में टाटा मोबाइल (जेके 11ई-5172) और लोड कैरियर ऑटो (जेके 11एफ-9233) शामिल थे।

न्यूज ब्रीफ

जम्मू-कश्मीर में 5 अगस्त को पीडीपी का शक्ति प्रदर्शन, महबूबा ने किया ऐलान

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) ने अनुच्छेद 370 की बहाली समेत विभिन्न मांगों को लेकर केंद्र सरकार के खिलाफ प्रदर्शन का ऐलान किया है। पार्टी अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने कहा कि 5 अगस्त को जम्मू-कश्मीर के सभी जिलों में जोरदार प्रदर्शन किया जाएगा। महबूबा मुफ्ती ने कहा कि यह प्रदर्शन अनुच्छेद 370 को निरस्त किए जाने के विरोध में आयोजित किया जाएगा। उन्होंने राजनीतिक बंदियों की रिहाई, एलओसी पार संपर्क बहाली और बिजली परियोजनाओं की वापसी जैसी मांगों को भी उठाया। पीडीपी अध्यक्ष ने केंद्र सरकार की नीतियों पर सवाल उठाते हुए कहा कि पार्टी अपने मुद्दों को जनता के बीच लेकर जाएगी। उन्होंने कार्यकर्ताओं से प्रदर्शन को सफल बनाने की अपील की। पीडीपी के इस ऐलान के बाद जम्मू-कश्मीर में राजनीतिक गतिविधियां तेज होने की संभावना है। प्रशासन की ओर से कानून व्यवस्था बनाए रखने के लिए सुरक्षा इंतजामों पर नजर रखी जा रही है।

जम्मू-कश्मीर के माजिद मागरे बने भारतीय दिव्यांग क्रिकेट टीम के कप्तान

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। भारतीय दिव्यांग क्रिकेट परिषद (डीसीसीआई) ने इंग्लैंड के खिलाफ होने वाली मिश्रित दिव्यांगता क्रिकेट श्रृंखला के लिए भारतीय टीम की घोषणा कर दी है। 5 से 19 अगस्त तक आयोजित होने वाली इस श्रृंखला के लिए 16 सदस्यीय टीम में जम्मू-कश्मीर के माजिद मागरे को कप्तान बनाया गया है। वहीं साई आकाश सैवमणि को उप-कप्तान की जिम्मेदारी सौंपी गई है। डीसीसीआई सचिव रवि कांत चौहान ने कहा कि माजिद मागरे का कप्तान बनना जम्मू-कश्मीर और दिव्यांग क्रिकेट जगत के लिए गर्व की बात है। उन्होंने उम्मीद जताई कि माजिद के नेतृत्व में टीम शानदार प्रदर्शन करेगी और नए खिलाड़ियों को प्रेरणा मिलेगी। डीसीसीआई उपाध्यक्ष सुमित जैन ने भी टीम को इंग्लैंड दौरे के लिए शुभकामनाएं दीं।

जम्मू-श्रीनगर हाईवे पर वाहन की टक्कर से 65 वर्षीय बुजुर्ग गंभीर घायल, अस्पताल रेफर

भारतेंदु संवाददाता, बनिहाल। जम्मू-कश्मीर के बनिहाल में मंगलवार को जम्मू-श्रीनगर राष्ट्रीय राजमार्ग पर सड़क हादसे में 65 वर्षीय व्यक्ति गंभीर रूप से घायल हो गया। हादसा लांबर टोल प्लाजा के पास हुआ, जहां एक इनोवा वाहन ने पैदल जा रहे व्यक्ति को टक्कर मार दी। घायल की पहचान बनिहाल के अशर निवासी अब्दुल रशीद के रूप में हुई है। दुर्घटना के बाद उसे तत्काल उप-जिला अस्पताल बनिहाल पहुंचाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसके सिर में गंभीर चोट और बाएं पैर में फ्रैक्चर पाया। प्राथमिक उपचार के बाद हालत को देखते हुए उसे बेहतर इलाज के लिए सरकारी मेडिकल कॉलेज अनंतनाग रेफर कर दिया गया। पुलिस ने घटना का संज्ञान लेते हुए मामले की जांच शुरू कर दी है।

झेलम नदी में छलांग लगाने वाले युवक का शव पांच दिन के बाद बरामद

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के श्रीनगर में झेलम नदी में छलांग लगाने वाले 25 वर्षीय युवक का शव मंगलवार को पांच दिन के खोज अभियान के बाद बरामद कर लिया गया। घटना पंपा चौक इलाके के सेम्पोरा क्षेत्र की है। अधिकारियों के अनुसार, राज्य आपदा प्रतिक्रिया बल (एसडीआरएफ) की टीमों ने लगातार तलाश अभियान चलाया, जिसके दौरान युवक का शव नदी से बरामद हुआ। इस अभियान में एसडीआरएफ श्रीनगर की टीमों के साथ स्थानीय स्वयंसेवकों ने भी सहयोग किया। मृतक की पहचान श्रीनगर के बलहामा निवासी सज्जाद अहमद मीर (25) के रूप में हुई है। शव को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस ने बताया कि चिकित्सा-कानूनी प्रक्रिया पूरी करने के बाद आगे की कार्रवाई की जाएगी। पुलिस ने बताया कि घटना की जांच जारी है और युवक की मौत के कारणों का पता लगाया जा रहा है।

जम्मू-कश्मीर में दो बड़े सड़क हादसे, एक अधिकारी समेत 11 सुरक्षाकर्मी घायल

◆ पहलगाम में पिक-अप वैन ने आईटीबीपी बंकर को मारी टक्कर

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर में सोमवार रात दो अलग-अलग सड़क हादसों में सीआरपीएफ, जम्मू-कश्मीर पुलिस और आईटीबीपी के 11 सुरक्षाकर्मी घायल हो गए। घायलों में एक अधिकारी भी शामिल है। अधिकारियों ने मंगलवार को बताया कि दोनों घटनाओं में किसी साजिश की आशंका नहीं है और प्रारंभिक जांच में हादसे दुर्घटना के कारण हुए हैं।

पहला हादसा शोपियां जिले के जैनापोरा इलाके में हुआ। जानकारी के अनुसार सीआरपीएफ की 178वीं बटालियन का बीपी बंकर वाहन पुलिस पोस्ट वाची में तैनात था। गश्त के दौरान अचानक चालक का वाहन से नियंत्रण बिगड़ गया, जिससे वाहन सड़क से फिसलकर नीचे पलट गया। इस हादसे में सीआरपीएफ के आठ जवान घायल हो गए। सभी घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया, जहां उनका उपचार जारी है। वहीं दूसरा हादसा अनंतनाग जिले के पहलगाम इलाके में हुआ। यहां एक पिकअप वैन ने आईटीबीपी के बंकर वाहन को टक्कर मार दी। इस दुर्घटना में आईटीबीपी और जम्मू-कश्मीर पुलिस के जवान घायल हुए हैं। हादसे के बाद मौके पर राहत एवं बचाव अभियान चलाया गया।

पुलिस और सुरक्षा अधिकारियों ने दोनों घटनाओं की जानकारी जुटाई है। घायलों की हालत पर भी लगातार नजर रखी जा रही है। अधिकारियों का कहना है कि सड़क सुरक्षा और वाहन संचालन में सावधानी बरतने के निर्देश दिए गए हैं। घटनाओं के बाद सुरक्षा बलों ने सभी आवश्यक कदम उठाए और जांच तेज कर दी गई है।

अरनिया में 50 लाख के जाली नोट नेटवर्क का खुलासा

भारतेंदु संवाददाता, आरएसपुरा। जम्मू-कश्मीर के अरनिया क्षेत्र में सक्रिय बताए जा रहे 50 लाख रुपये के जाली भारतीय करेंसी नेटवर्क को लेकर सुरक्षा एजेंसियां अलर्ट हो गई हैं। खुफिया इनपुट मिलने के बाद इस मामले की जांच तेज कर दी गई है। एजेंसियां मुख्य आरोपी तरसेम और उसके साथियों की तलाश में जुटी हैं। अधिकारियों का मानना है कि तरसेम की गिरफ्तारी के बाद पूरे नेटवर्क का खुलासा हो सकता है। सूत्रों के अनुसार, सेना की सुरक्षा एजेंसी को अरनिया इलाके में जाली नोटों के बड़े नेटवर्क के सक्रिय होने की जानकारी मिली थी।

इनपुट की पुष्टि के बाद इसे जम्मू-कश्मीर पुलिस के साथ साझा किया गया। इसके आधार पर पुलिस ने मामले में संदिग्धों से पूछताछ शुरू की। जांच के दौरान सामने आया है कि इस नेटवर्क के तार दिल्ली और कश्मीर तक जुड़े हो सकते हैं। सुरक्षा एजेंसियां कॉल डिटेल रिकॉर्ड (सीडीआर) और अन्य तकनीकी साक्ष्यों की मदद से पूरे नेटवर्क की कड़ियां जोड़ने में जुटी हैं। मामले में कुछ लोगों से पूछताछ की गई है, जिनसे महत्वपूर्ण जानकारियां मिलने की बात सामने आई है। हालांकि मुख्य आरोपी की गिरफ्तारी नहीं होने के कारण जांच अभी आगे बढ़ रही है।

महबूबा का पेलेट गन बयान पर यू टर्न, कहा- अधूरी लाइन से हुआ भ्रम

◆ कहा, 'बहाना' शब्द छूटने से गलतफहमी पैदा हुई

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीपुल्स डेमोक्रेटिक पार्टी (पीडीपी) की अध्यक्ष महबूबा मुफ्ती ने पेलेट गन को लेकर दिए गए अपने विवादित बयान पर सफाई देते हुए माफी मांगी है। उन्होंने कहा कि बयान के दौरान 'बहाना' शब्द छूट जाने की वजह से गलत अर्थ निकाला गया और लोगों में गलतफहमी पैदा हुई।

महबूबा मुफ्ती ने श्रीनगर में आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा कि उनका उद्देश्य किसी की भावनाओं को ठेस पहुंचाना नहीं था। उन्होंने स्पष्ट किया कि उनका मतलब यह था कि कानिवादद को सरकार पेलेट गन के इस्तेमाल के लिए बहाने के रूप में इस्तेमाल करती है। उन्होंने कहा कि अधूरी लाइन और जुबान फिसलने के कारण उनका बयान विवादों में आ गया।

पीडीपी प्रमुख ने कहा कि जम्मू-कश्मीर के हालात और लोगों की पीड़ा को लेकर वह हमेशा अपनी बात रखती रही हैं। उन्होंने दोहराया कि उनका मकसद सुरक्षा बलों या किसी समुदाय के खिलाफ टिप्पणी करना नहीं था। बयान को लेकर उठे विवाद के बाद उन्होंने अपनी बात स्पष्ट करते हुए खेद जताया। और कहा कि उनकी टिप्पणी का गलत अर्थ निकाला गया उन्होंने कहा कि उनका बयान किसी के खिलाफ नहीं था।

मुलाकात गांदरबल बस हादसे के बाद राहत और बचाव कार्य तेज, सुरक्षा व्यवस्था की समीक्षा शुरू

घायल अमरनाथ श्रद्धालुओं को मिलेगा बेहतर इलाज, बोले मनोज सिन्हा

भारतेंदु संवाददाता, श्रीनगर। जम्मू-कश्मीर के गांदरबल जिले में अमरनाथ यात्रियों से भरी बस दुर्घटनाग्रस्त होने के बाद प्रशासन पूरी तरह सक्रिय हो गया है। हादसे में घायल श्रद्धालुओं का हाल जानने के लिए जम्मू-कश्मीर के उपराज्यपाल मनोज सिन्हा श्रीनगर स्थित एसकेआईएमएस अस्पताल पहुंचे। उन्होंने अस्पताल में भर्ती घायल यात्रियों से मुलाकात कर उनका स्वास्थ्य जाना और डॉक्टरों से उपचार की जानकारी ली।

उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने अधिकारियों और चिकित्सकों को निर्देश दिए कि सभी घायलों को सर्वोत्तम चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जाए। उन्होंने कहा कि घायलों के इलाज में किसी भी तरह की कमी नहीं रहनी चाहिए और जरूरत पड़ने पर बेहतर उपचार के लिए हर संभव व्यवस्था की जाए। गौरतलब है कि गांदरबल क्षेत्र में अमरनाथ यात्रियों को ले जा रही बस दुर्घटनाग्रस्त हो गई थी।

हादसे में करीब 39 से 40 श्रद्धालु घायल हो गए। घटना की जानकारी मिलते ही राहत और बचाव दल मौके पर पहुंचा और घायलों को तत्काल अस्पताल पहुंचाया गया। गंभीर रूप से घायल यात्रियों को विशेष चिकित्सा निगरानी में रखा गया है। मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रा केवल धार्मिक यात्रा नहीं, बल्कि लाखों लोगों की आस्था और विश्वास से जुड़ी हुई है।

उन्होंने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षा प्रशासन की सबसे बड़ी प्राथमिकता है। यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था और सुविधाओं की लगातार निगरानी की जा रही है। अस्पताल दौरे के दौरान उपराज्यपाल ने घायल यात्रियों और उनके परिजनों से बातचीत की। उन्होंने उन्हें हर संभव सहायता उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया। उन्होंने डॉक्टरों से कहा कि सभी घायलों की स्थिति पर लगातार नजर रखी जाए और उन्हें बेहतर उपचार दिया जाए। प्रशासन ने हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

हादसे के बाद यात्रा मार्ग पर कड़े इंतजाम

हादसे के बाद प्रशासन ने यात्रा मार्ग पर सुरक्षा व्यवस्था को और मजबूत करने की कवायद शुरू कर दी है। अधिकारियों को निर्देश दिए गए हैं कि श्रद्धालुओं की आवाजाही के दौरान हर स्तर पर सतर्कता बरती जाए। साथ ही आपात स्थिति से निपटने के लिए बचाव दलों को पूरी तरह तैयार रहने को कहा गया है। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने कहा कि अमरनाथ यात्रियों की सुरक्षा सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि घायल श्रद्धालुओं के इलाज और उनके परिवारों की सहायता के लिए प्रशासन हर संभव कदम उठाएगा। उन्होंने डॉक्टरों और स्वास्थ्य कर्मियों की तत्परता की सराहना करते हुए कहा कि सभी घायलों को बेहतर से बेहतर चिकित्सा सुविधा उपलब्ध कराई जा रही है। प्रशासन ने दुर्घटना की विस्तृत जांच शुरू कर दी है, ताकि हादसे के कारणों का पता लगाया जा सके और भविष्य में ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए प्रभावी कदम उठाए जा सकें। अधिकारियों ने कहा कि श्रद्धालुओं की सुरक्षित यात्रा सुनिश्चित करने के लिए सभी विभाग आपसी तालमेल के साथ काम कर रहे हैं।

कड़ी सुरक्षा के बीच अमरनाथ यात्रा का 21वां जत्था रवाना

जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 151 वाहनों के काफिले में रवाना हुए श्रद्धालु

बाबा बर्फानी के दर्शन की आस में आगे बढ़े 3029 श्रद्धालु।

भारतेंदु संवाददाता, जम्मू। अमरनाथ यात्रा के लिए श्रद्धालुओं का उत्साह लगातार जारी है। मंगलवार सुबह जम्मू के भगवती नगर आधार शिविर से 3029 श्रद्धालुओं का 21वां जत्था कड़ी सुरक्षा व्यवस्था के बीच बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए रवाना हुआ। अधिकारियों के अनुसार, सभी यात्रियों को 151 वाहनों के काफिले में बालटाल आधार शिविर की ओर भेजा गया। जत्थे की रवानगी के दौरान सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए थे।

पुलिस और सुरक्षा बलों के जवान पूरे मार्ग पर तैनात रहे, ताकि श्रद्धालुओं की यात्रा सुरक्षित और सुचारू रूप से पूरी हो सके। प्रशासन की ओर से यात्रियों की सुविधा और सुरक्षा को प्राथमिकता दी जा रही है। अमरनाथ यात्रा को लेकर देशभर से श्रद्धालुओं में खासा उत्साह देखने को मिल रहा है। कठिन पहाड़ी रास्तों के बावजूद बड़ी संख्या में श्रद्धालु बाबा बर्फानी के दर्शन के लिए पहुंच रहे हैं।

अधिकारियों ने बताया कि यात्रा मार्ग पर सुविधाओं, चिकित्सा सेवाओं और सुरक्षा व्यवस्था की लगातार निगरानी की जा रही है। प्रशासन ने श्रद्धालुओं से यात्रा के दौरान नियमों का पालन करने और सुरक्षा निर्देशों का ध्यान रखने की अपील की है।

न्यूज ब्रीफ

एसपीयू इतिहास विभाग के विद्यार्थी सेट परीक्षा में चमके

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। सरदार पटेल विश्वविद्यालय के इतिहास विभाग के विद्यार्थियों ने राज्य पात्रता परीक्षा (सेट)-2026 में उत्कृष्ट प्रदर्शन करते हुए विभाग एवं विश्वविद्यालय का नाम गौरवान्वित किया है। इतिहास विभाग के कुल पांच विद्यार्थियों ने यह प्रतिष्ठित परीक्षा सफलतापूर्वक उत्तीर्ण की है। एमए इतिहास सत्र 2024-2026 से गौरव रावत, दीपक दीपांशु, विक्रांत एवं कृष्णा देवी, जबकि एमए इतिहास सत्र 2023-2025 से सपना कुमारी ने सेट परीक्षा उत्तीर्ण कर अपनी शैक्षणिक प्रतिभा का उत्कृष्ट परिचय दिया है। इस अवसर पर सरदार पटेल विश्वविद्यालय के कुलपति आचार्य प्रो. ललित कुमार अवस्थी ने कहा कि सेट परीक्षा में इतिहास विभाग के विद्यार्थियों की सफलता विश्वविद्यालय की गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन तथा विद्यार्थियों की लगन व परिश्रम का उत्कृष्ट उदाहरण है। यह उपलब्धि अन्य विद्यार्थियों के लिए भी प्रेरणास्रोत बनेगी। उन्होंने कहा कि विश्वविद्यालय विद्यार्थियों को गुणवत्तापूर्ण शिक्षा, अनुसंधान तथा प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी के लिए अनुकूल शैक्षणिक वातावरण उपलब्ध कराने के लिए निरंतर प्रतिबद्ध है। इतिहास विभागाध्यक्ष डॉ. राकेश कुमार शर्मा, प्रो.राजेश कुमार शर्मा अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ.पवन चंद अधिष्ठाता छात्र कल्याण, डॉ. सनील ठाकुर अधिष्ठाता शोध, इतिहास विभाग के सहायक आचार्य डॉ. रामपाल, विकेश कुमार व राजेश कुमार ने विद्यार्थियों को बधाई दी।

पूर्व मुख्यमंत्री प्रो. धूमल से मिले भाजयुमो कार्यकर्ता

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। भारतीय जनता युवा मोर्चा (भाजयुमो) नादौन के पदाधिकारियों एवं कार्यकर्ताओं के एक प्रतिनिधिमंडल ने मंगलवार को हिमाचल प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री एवं भाजपा के वरिष्ठ नेता प्रो. प्रेम कुमार धूमल से समीरपुर स्थित उनके आवास पर शिष्टाचार भेंट की। इस दौरान प्रदेश की वर्तमान राजनीतिक परिस्थितियों, संगठनात्मक गतिविधियों, युवाओं की भूमिका तथा विभिन्न समसामयिक विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रो. धूमल ने युवा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते हुए कहा कि किसी भी संगठन की सबसे बड़ी ताकत उसके समर्पित व सक्रिय कार्यकर्ता होते हैं। उन्होंने युवाओं से सेवा, समर्पण व अनुशासन को अपनी कार्यशैली का आधार बनाने का आह्वान किया। उन्होंने कहा कि भाजपा की जनकल्याणकारी नीतियों और संगठन की विचारधारा को समाज के प्रत्येक वर्ग तक प्रभावी ढंग से पहुंचाने में युवाओं की महत्वपूर्ण भूमिका है। उन्होंने यह भी कहा कि राष्ट्र निर्माण और संगठन विस्तार में युवा शक्ति की भागीदारी निर्णायक होती है तथा उनका सकारात्मक योगदान भविष्य की दिशा तय करता है। प्रतिनिधिमंडल में भाजयुमो नादौन मंडलाध्यक्ष आशीष राणा, जिला उपाध्यक्ष जितेंद्र कुमार, जिला युवा प्रवक्ता सुनीत कटोच, जिला प्रवक्ता हर्षित चंदेल, जिला सोशल मीडिया प्रभारी कौशिक जरयाल, मंडल महामंत्री आकाश पराशर, मंडल उपाध्यक्ष आशीष रतन एवं सन्नी कटोच, मंडल सचिव राहुल ठाकुर, भाजपा कार्यकारिणी सदस्य आशीष सयाल तथा कार्यकर्ता अभिषेक रंजन संधाया सहित अन्य कार्यकर्ता उपस्थित रहे।

31 तक करें नवोदय चयन परीक्षा के लिए आवेदन

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जवाहर नवोदय विद्यालय में शैक्षणिक सत्र 2027-28 के लिए कक्षा छठी में प्रवेश के लिए जवाहर नवोदय विद्यालय चयन परीक्षा के ऑनलाइन आवेदन 31 जुलाई तक किए जा सकते हैं। परीक्षा का आयोजन 28 नवंबर 2026 को होगा। इच्छुक अभिभावक एवं विद्यार्थी www.navodaya.gov.in तथा httpsN//cbseitms.rcil.gov.in/nvs/ पर ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। जवाहर नवोदय विद्यालय ग्रामीण क्षेत्रों के मेधावी विद्यार्थियों को निशुल्क गुणवत्तापूर्ण आवासीय शिक्षा, भोजन, पुस्तकें, वर्दी, खेल और आधुनिक शैक्षणिक सुविधाएं उपलब्ध कराते हैं। पिछले वर्ष देशभर में लगभग 25.99 लाख विद्यार्थियों ने इस परीक्षा के लिए पंजीकरण कराया था। इस वर्ष भी ग्रामीण क्षेत्रों और बालिकाओं की अधिकतम भागीदारी सुनिश्चित करने पर विशेष जोर दिया गया है।

मतदाता सूची सुधार को लेकर किया जागरूक

भारतेन्दु संवाददाता, पठानकोट। मुख्य चुनाव अधिकारी पंजाब और जिला चुनाव अधिकारी-सह-डिप्टी कमिश्नर डॉ. पल्लवी के दिशा-निर्देशों पर जिला स्वीप टीम ने मंगलवार को एसआईआर (स्पेशल इंटेंसिव रिवीजन) अभियान के तहत शहर के विभिन्न क्षेत्रों में जागरूकता अभियान चलाया। जिला नोडल अधिकारी (स्वीप)-सह-जिला भूमि रक्षा अधिकारी गुरप्रीत सिंह के नेतृत्व में नोवेल्टी मॉल, मामून चौक और आसपास के क्षेत्रों में लोगों को मतदाता सूची से जुड़ी जानकारी दी गई। इस दौरान टीम ने राहगीरों और आम नागरिकों को जागरूकता पंपलेट वितरित किए। सहायक नोडल अधिकारी (सोशल मीडिया) रवि कांत और सहायक नोडल अधिकारी (स्वीप एवं जागरूकता सेल) संजीव कुमार ने लोगों को मतदाता सूची में नया नाम दर्ज करवाने, नाम संशोधन, स्थान परिवर्तन और आवश्यक दस्तावेजों की जानकारी दी। उन्होंने कहा कि सही और अद्यतन मतदाता सूची मजबूत लोकतंत्र की नींव है। प्रत्येक पात्र नागरिक को समय पर पंजीकरण करवाकर अपने मतदाता विवरण को अपडेट रखना चाहिए। अभियान में स्वीप टीम के सदस्य विवेक डोगरा, हरसिमरनजीत सिंह, अमित डोगरा सहित अन्य लोग उपस्थित रहे।

पांच मामलों में उद्घोषित अपराधी गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, शिमला। शिमला पुलिस ने लंबे समय से फरार चल रहे एक उद्घोषित अपराधी को रोहड़ू बाजार से गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार आरोपी की पहचान 57 वर्षीय राजपाल पुत्र स्वर्गीय गोपी नंद के रूप में हुई है। वह चिड़गांव के गांव थली का निवासी है। पुलिस के अनुसार उद्घोषित अपराधियों की गिरफ्तारी के लिए चलाए जा रहे अभियान के तहत रोहड़ू उपमंडल की पीओ सेल ने 27 जुलाई को सुबह करीब 11:30 बजे रोहड़ू बाजार में कार्रवाई कर आरोपी को गिरफ्तार किया। पुलिस ने बताया कि राजपाल को परक्राम्य लिखत अधिनियम (नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट) की धारा 138 और 142 के तहत दर्ज पांच अलग-अलग मामलों में एसीजेएम कोर्ट नंबर-1, रोहड़ू ने उद्घोषित अपराधी घोषित किया था। आरोपी लंबे समय से फरार चल रहा था और उसकी गिरफ्तारी के लिए पुलिस लगातार प्रयास कर रही थी।

चंबा जिले में फ्लैश फ्लड से जनजीवन हुआ प्रभावित, कई सड़कें बंद और वाहन हुए क्षतिग्रस्त

खाई में गिरी कार, एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत

भारतेन्दु संवाददाता, चंबा। हिमाचल प्रदेश के चंबा जिले में मूसलाधार बारिश और एक भीषण सड़क हादसे ने लोगों को झकझोर दिया। जिले में रात भर मूसलाधार बारिश के कारण कई जगह फ्लैश फ्लड जैसे हालात बन गए। घरों और दुकानों में पानी व मलबा घुस गया, सड़कें बंद हो गईं और कई वाहन क्षतिग्रस्त हो गए। इसी बीच पठानकोट-चंबा राष्ट्रीय राजमार्ग पर एक कार गहरी खाई में गिर गई, जिसमें एक ही परिवार के पांच लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 3 माह का बच्चा भी शामिल है।

सोमवार रात चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर परेल नामक स्थान पर नाले में अचानक भारी पानी आने से कई वाहन उसकी चपेट में आ गए। कुछ वाहनों को नुकसान पहुंचा, हालांकि किसी के हताहत होने की सूचना नहीं है। भारी मलबा और पानी आने से राष्ट्रीय राजमार्ग बंद हो गया। प्रशासन ने सड़क खोलने के लिए मशीनें मौके पर भेज दी हैं और बहाली का काम जारी है। भारी बारिश का सबसे अधिक असर चंबा शहर के सुल्तानपुर मोहल्ले में देखने को मिला। कई घरों और दुकानों में पानी और मलबा घुस गया, जिससे लोगों को भारी नुकसान उठाना पड़ा। रात में हालात इतने बिगड़ गए कि कई परिवारों ने घर छोड़कर सुरक्षित स्थानों की ओर भागकर जान बचाई। कई लोगों ने पूरी रात जागकर बिताई। कुछ मकानों पर बड़े पत्थर गिर गए और सड़क किनारे खड़ी कई गाड़ियां भी क्षतिग्रस्त हो गईं।

बारिश के कारण पक्काटाला-चंबा संपर्क मार्ग पर डंगा (रिटेनिंग वॉल) गिर गया। इसके चलते पास स्थित स्कूल की सुरक्षा को लेकर भी चिंता बढ़ गई है। प्रशासन प्रभावित क्षेत्रों का जायजा ले रहा है। उधर, डलहौजी उपमंडल के लाहड़ क्षेत्र में चंबा-पठानकोट राष्ट्रीय राजमार्ग पर मंगलवार सुबह एक अल्टो कार 400 मीटर गहरी खाई में गिर गई। हादसे में कार सवार पांच लोगों की मौत हो गई। एसपी विजय सकलानी ने हादसे की पुष्टि की है।

पुलिस ने शवों को खाई से निकालकर कब्जे में लिया और दुर्घटना के कारणों की जांच शुरू कर दी है। पुलिस के अनुसार मृतकों की पहचान चालक बचन सिंह (60) पुत्र नारायण सिंह, उनके पुत्र रिपन कुमार (30), रिपन की पत्नी रिम्पी (26), कीर्ति (23) पुत्र केसर सिंह और एक 3 माह के बच्चे के रूप में हुई है। सभी चंबा जिले के भरमौर विधानसभा क्षेत्र की ग्राम पंचायत गैहरा के रहने वाले थे और चंडीगढ़ से घर लौट रहे थे। भरमौर के विधायक डॉ. जनक राज ने हादसे पर शोक जताते हुए कहा कि गैहरा के पांच लोगों की मौत की खबर बेहद दुखद है। उन्होंने मृतकों की आत्मा की शांति और परिजनों को इस दुख को सहने की शक्ति देने की प्रार्थना की।

कांगड़ा में ट्रक पुल से नीचे गिरा, दो की मौत

धर्मशाला। पठानकोट-मंडी राष्ट्रीय राजमार्ग पर सोमवार देर रात 53 मील के पास एक सड़क हादसे में 2 लोगों की मौत हो गई। वहीं हादसे में जीवित चालक मौके से फरार हो गया। पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर आगामी कार्रवाई की है। पुलिस के मुताबिक 53 मील और खोली को जोड़ने वाले पुल पर 16 टायरी ट्रक पुल की रेलिंग को तोड़ता हुआ नीचे खड्ड में जा गिरा, जिसमें 2 लोगों की मौत हो गई, जबकि चालक फरार हो गया। जानकारी के अनुसार ट्रक पंजाब नंबर का है, जिसमें चालक सहित कुल तीन लोग सवार थे। जब ट्रक पुल से गुजर रहा था, उसी समय यह हादसा पेश आया। ऊपर पुलिस के अनुसार ट्रक में चालक समेत कुल तीन लोग थे, जिसमें से दो लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि चालक फरार हो गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर हादसे के कारणों की जांच शुरू कर दी है।

30 जुलाई तक भारी बारिश की संभावना

मौसम विभाग के अनुसार पिछले 24 घंटों में प्रदेश में सबसे अधिक 137.8 मिलीमीटर बारिश चंबा जिले के जोत में दर्ज की गई। इसके अलावा बिलासपुर के नैना देवी में 118.0 मिमी, मंडी की मुरारी देवी में 83.0 मिमी, कांगड़ा के घमरूर और शिमला में 58.2-58.2 मिमी, बिलासपुर के ब्रह्माणी में 54.6 मिमी, मंडी के जोगिंदरनगर में 52.0 मिमी, ओलिंडा में 44.0 मिमी, हमीरपुर में 43.0 मिमी, बिलासपुर के आरएल बीबीएमबी में 42.4 मिमी और कांगड़ा के नगरोटा सूरियां में 42.2 मिमी बारिश दर्ज की गई। मौसम विभाग ने 28 से 30 जुलाई तथा 3 अगस्त को प्रदेश के अलग-अलग स्थानों पर भारी से बहुत भारी बारिश की संभावना जताई है। 31 जुलाई से 2 अगस्त तक भी कई स्थानों पर भारी बारिश का अनुमान है। विभाग ने लोगों से नदी-नालों के आसपास नहीं जाने और खराब मौसम के दौरान अनावश्यक यात्रा से बचने की सलाह दी है।

जेई, ओटीए और शिक्षकों की भर्ती परीक्षाओं की तिथियां घोषित

भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। हिमाचल प्रदेश राज्य चयन आयोग (एचपीआरसीए) हमीरपुर ने चार अलग-अलग श्रेणियों के पदों की भर्ती के लिए कंप्यूटर आधारित परीक्षा (सीबीटी) की तिथियां घोषित कर दी हैं। आयोग के सचिव डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि कनिष्ठ अभियंता (सिविल) पोस्ट कोड-26016 की परीक्षा 9 अगस्त को तीन अलग-अलग शिफ्टों में सुबह 9 से 10:30 बजे तक, दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक और शाम को 4 से 5:30 बजे तक होगी। फाइन आर्ट्स शिक्षक पोस्ट कोड-26033 की परीक्षा 14 अगस्त को सुबह 9 से 10:30 बजे तक, साइकोलॉजी शिक्षक पोस्ट कोड-26031 की परीक्षा इसी दिन दोपहर 12:30 बजे से 2 बजे तक और ऑपरेशन थियेटर असिस्टेंट पोस्ट कोड-26008 की परीक्षा शाम को 4 से 5:30 बजे तक होगी। डॉ. विक्रम महाजन ने बताया कि परीक्षा से एक सप्ताह पहले आयोग की वेबसाइट एचपीआरसीए.एचपी.जीओवी.इन पर एक लिंक का प्रावधान किया जाएगा, जिससे अभ्यर्थी अपना रोल नंबर एवं एडमिट कार्ड डाउनलोड कर सकेंगे।

2 व 3 अक्तूबर को सजेगा घुमारवीं का सीर उत्सव

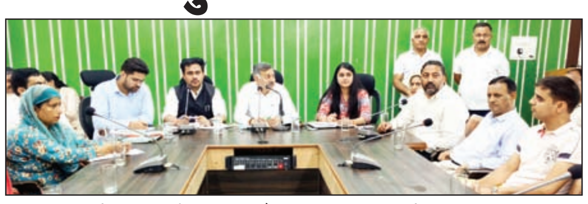

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, घुमारवीं। नगर व ग्राम नियोजन, आवास, तकनीकी शिक्षा, व्यावसायिक एवं औद्योगिक प्रशिक्षण मंत्री राजेश धर्माणी ने कहा कि इस वर्ष भी घुमारवीं में 2 और 3 अक्तूबर को जिला स्तरीय सीर उत्सव का भव्य आयोजन किया जाएगा। सोमवार को खंड विकास अधिकारी कार्यालय परिसर में आयोजित बैठक की अध्यक्षता करते हुए उन्होंने बताया कि गत वर्ष की तरह इस बार भी खेल आधारित गतिविधियां उत्सव का प्रमुख आकर्षण रहेंगी।

उन्होंने कहा कि समाज के प्रत्येक वर्ग की भागीदारी सुनिश्चित करने के उद्देश्य से लैंगिक समानता और स्वास्थ्य विषय पर मैराथन तथा वॉकथॉन प्रतियोगिताओं का आयोजन किया जाएगा, जिससे युवाओं और बच्चों को उत्सव से जोड़ा जा सके। राजेश धर्माणी ने बताया कि स्कूलों, कॉलेजों और आईटीआई के विद्यार्थियों के लिए खेलकूद एवं सांस्कृतिक प्रतियोगिताएं आयोजित होंगी। साथ ही विभिन्न वर्गों की भागीदारी बढ़ाने के लिए सांस्कृतिक प्रस्तुतियां, खेल प्रतियोगिताएं और महिला मंडलों के कार्यक्रम भी आयोजित किए जाएंगे।

उन्होंने कहा कि उत्सव के दौरान रोजगार मेले का आयोजन किया जाएगा, जिसमें प्रतिष्ठित कंपनियां युवाओं को रोजगार के अवसर उपलब्ध कराएंगी। इसके अलावा स्वास्थ्य जांच शिविर और रक्तदान शिविर भी लगाए जाएंगे। उन्होंने कहा कि सीर उत्सव केवल सांस्कृतिक आयोजन नहीं, बल्कि नशा मुक्ति, स्वास्थ्य जागरूकता और पर्यावरण संरक्षण का संदेश देने का प्रभावी मंच भी बनेगा। विभिन्न क्षेत्रों और विभागों में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों को भी सम्मानित किया जाएगा। पंचायत स्तर पर प्रारंभिक खेल प्रतियोगिताएं आयोजित कर विजेताओं को जिला स्तरीय मंच पर अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर दिया जाएगा। उन्होंने एनएसएस, एनसीसी तथा स्काउट्स एवं गाइड के कैडेट्स की भागीदारी सुनिश्चित करने पर भी जोर दिया। तकनीकी शिक्षा मंत्री ने एसडीएम को विभिन्न आयोजन समितियों का शीघ्र गठन करने और 15 अगस्त तक सभी समितियों की बैठकें आयोजित कर विस्तृत कार्ययोजना तैयार करने के निर्देश दिए। उन्होंने सरकारी और गैर-सरकारी संगठनों तथा आम जनता से सीर उत्सव के सफल आयोजन में सक्रिय सहयोग की अपील की। बैठक में एसडीएम अभिषेक बरवाल ने उत्सव की रूपरेखा प्रस्तुत की। इस दौरान एपीएमसी अध्यक्ष सतपाल, नगर परिषद अध्यक्ष अमित कुमार, उपाध्यक्ष सविता कुमारी सहित कई सरकारी एवं गैर-सरकारी प्रतिनिधि उपस्थित रहे।

भूस्खलन से कैंची मोड़-नयना देवी मार्ग बंद

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। लगातार हो रही भारी बारिश के कारण कैंची मोड़-नयना देवी मार्ग पर धारा, जनाली और पंचपीरा क्षेत्र में भारी भूस्खलन हुआ। इसके चलते जिला प्रशासन ने अगले आदेशों तक इस मार्ग को सभी प्रकार के वाहनों के लिए बंद कर दिया है।

उपायुक्त राहुल कुमार ने बताया कि सड़क पर भारी मलबा और चट्टानें आने से यातायात पूरी तरह बाधित है। लोक निर्माण विभाग व संबंधित एजेंसियां युद्धस्तर पर मार्ग बहाल करने में जुटी हैं। श्रद्धालुओं, पर्यटकों और अन्य वाहन चालकों को आनंदपुर साहिब-टोबा-नयना देवी वैकल्पिक मार्ग से यात्रा करने की सलाह दी गई है, जो फिलहाल सुरक्षित और सुचारू है। प्रशासन ने लोगों से अनावश्यक यात्रा से बचने, मौसम और मार्ग की ताजा जानकारी लेकर ही सफर करने तथा बंद मार्ग से गुजरने का प्रयास न करने और केवल आधिकारिक सूचनाओं पर भरोसा करने की अपील की है।

नरेश ठाकुर ने अधिकारियों के साथ किया नशा मुक्ति केंद्रों का निरीक्षण

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। राज्य नशा निवारण बोर्ड के संयोजक एवं सलाहकार नरेश ठाकुर ने मंगलवार को हमीरपुर में विभिन्न संस्थाओं के माध्यम से संचालित किए जा रहे नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का निरीक्षण किया।

एडीसी अभिषेक गर्ग, एसडीएम संजीत सिंह, मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉ. अजय अत्री, डॉ. राधाकृष्णन राजकीय मेडिकल कॉलेज अस्पताल के मनोचिकित्सा विभाग के डॉ. कमल प्रकाश, राज्य कर एवं आबकारी विभाग के सहायक आयुक्त नितिन कपूर, डीएसपी नितिन चौहान और अन्य अधिकारियों के साथ निरीक्षण के लिए पहुंचे नरेश ठाकुर ने इन केंद्रों में विभिन्न सुविधाओं का जायजा लिया। दोसड़का में संचालित किए जा रहे गोल्डन एज पुनर्वास केंद्र के निरीक्षण के दौरान नरेश ठाकुर ने इस केंद्र में विभिन्न सुविधाओं विस्तार के साथ-साथ इसके भवन में अग्निशमन और अन्य सुरक्षा मानकों का भी विशेष ध्यान रखने के निर्देश दिए। इसके बाद उन्होंने बड़ू के पास घनाल में स्थापित किए जा रहे नए नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्र के परिसर का भी जायजा लिया। उन्होंने कहा कि इस नए केंद्र का संचालन आरंभ करने से पहले सभी आवश्यक सुविधाओं का प्रावधान होना चाहिए। नरेश ठाकुर ने बताया कि नशा मुक्ति, उपचार एवं पुनर्वास केंद्रों के संचालन के संबंध में शीघ्र ही राज्य नशा निवारण बोर्ड की बैठक में व्यापक चर्चा के बाद विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए जाएंगे। इनमें विभिन्न सुविधाओं के साथ-साथ भवनों के सुरक्षा मानकों को भी शामिल किया जाएगा। उन्होंने बताया कि जिले के अन्य नशा मुक्ति एवं पुनर्वास केंद्रों का भी शीघ्र ही निरीक्षण किया जाएगा।

पुलिस ने 27.60 ग्राम चिट्टे सहित 3 आरोपी किए गिरफ्तार

भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। बिलासपुर पुलिस की स्पेशल डिटेक्शन टीम (एसडीटी) ने नशा तस्करी के खिलाफ चलाए जा रहे अभियान के तहत बड़ी कार्रवाई करते हुए 27.60 ग्राम चिट्टा (हेरोइन) बरामद कर तीन आरोपियों को गिरफ्तार किया है।

पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने बताया कि आरटीओ बैरियर के पास नाकाबंदी और वाहन चैकिंग के दौरान दिल्ली से लेह जा रही एचआरटीसी बस (एचपी-42-3331) की तलाशी ली गई। तलाशी के दौरान बस में सवार तीन व्यक्तियों के कब्जे से कुल 27.60 ग्राम चिट्टा बरामद हुआ। गिरफ्तार आरोपियों की पहचान हरियाणा के सोनीपत निवासी सुनील पुत्र धर्मपाल, अनिल राठी पुत्र जसपाल सिंह तथा हिमाचल प्रदेश के कुल्लू निवासी नरेंद्र सिंह पुत्र हीरू राम के रूप में हुई है। इस संबंध में पुलिस थाना स्वारघाट में एनडीपीएस अधिनियम के तहत मामला दर्ज कर तीनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस मामले की गहन जांच में जुटी है और यह पता लगाया जा रहा है कि बरामद नशीला पदार्थ कहां से लाया गया था और इसे कहां पहुंचाया जाना था। पुलिस के अनुसार गिरफ्तार आरोपी सुनील कुमार एक सक्रिय एवं आदतन नशा तस्कर है, जिसके खिलाफ पहले भी एनडीपीएस अधिनियम के तहत कई मामले दर्ज हैं। उसके विरुद्ध 3 मई को थाना सदर कुल्लू में 41 ग्राम चिट्टा बरामदगी का मामला दर्ज हुआ था। इसके अलावा मंडी जिले में उसके खिलाफ 1.229 किलोग्राम चरस तथा एक अन्य मामले में 92 ग्राम चरस बरामदगी से जुड़े मुकदमे भी दर्ज हैं। पुलिस अधीक्षक बिलासपुर ने कहा कि मुख्य आरोपी का आपराधिक इतिहास रहा है और उसके खिलाफ अन्य जिलों में भी कई मामले लंबित हैं।

नूरपुर में बीमा सखी योजना के तहत 80 पदों के लिए 4 अगस्त को साक्षात्कार

भारतेन्दु संवाददाता, नूरपुर। रोजगार की तलाश कर रही महिलाओं के लिए भारतीय जीवन बीमा निगम (एलआईसी) शाखा कार्यालय नूरपुर ने बीमा सखी योजना के तहत 80 पद अधिसूचित किए हैं। इन पदों के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता दसवीं पास तथा आयु सीमा 20 से 60 वर्ष निर्धारित की गई है। चयनित अभ्यर्थियों को पहले वर्ष 7 हजार रुपए, दूसरे वर्ष 6 हजार रुपए और तीसरे वर्ष 5 हजार रुपए प्रतिमाह मानदेय के साथ लक्ष्य आधारित कमीशन भी दिया जाएगा। प्रभारी उप रोजगार कार्यालय नूरपुर प्रवेश कुमार ने बताया कि इच्छुक अभ्यर्थी 4 अगस्त को सुबह 10 बजे एलआईसी शाखा कार्यालय, नूरपुर में आयोजित साक्षात्कार में भाग ले सकते हैं। अभ्यर्थियों को दो पासपोर्ट फोटो, हिमाचली प्रमाण पत्र, शैक्षणिक प्रमाण पत्र, आधार कार्ड, पैन कार्ड, बायोडाटा तथा अनुभव प्रमाण पत्र (यदि उपलब्ध हो) साथ लाना होगा। साक्षात्कार के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा। अधिक जानकारी के लिए 9857270066 या 7018300789 पर संपर्क किया जा सकता है।

वरिष्ठता विवाद में 642 प्रमोट शिक्षकों को नहीं मिले वित्तीय लाभ

डिमोशन नोटिस स्टे के बाद भी टीजीटी को नहीं मिला प्रमोशन स्केल

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। 21 अगस्त 2025 को टीजीटी से प्रमोट होकर प्रवक्ता बने सैकड़ों शिक्षकों को पदोन्नति का स्केल व वार्षिक इंक्रीमेंट अब तक नहीं मिली।

डीम्ड रेगुलर,पैरा टीचर्स से रेगुलर शिक्षकों के वरिष्ठता विवाद के बीच कुल 642 टीजीटी को अगस्त 2025 में प्रवक्ता पद पर पदोन्नत किया गया था और इसमें से अधिकतम प्रमोट शिक्षकों का वेतन निर्धारण अब तक लंबित है, जिन प्रमोट शिक्षकों को शिक्षा विभाग ने डिमोशन का नोटिस थमाया था, उनके वेतन निर्धारण के मामले वापिस लौटाने की प्रक्रिया चल रही है। यद्यपि डिमोशन पर हाईकोर्ट से स्टे लगा है, मगर इसके बाद भी प्रमोट हुए शिक्षकों को नए पद का स्केल नहीं मिला और कुछ शिक्षकों को पिछले वर्ष की इंक्रीमेंट नहीं मिली और अनेकों शिक्षकों को इस साल भी इंक्रीमेंट रुकती नजर आ रही है। हालांकि, इस शिक्षकों के वेतन निर्धारण पर कोई रोक नहीं है, मगर विभाग इसे कोर्ट केस के अंतिम निर्णय की शर्त लगाकर भी नहीं कर रहा है, ऐसे में राजकीय टीजीटी कला संघ ने शिक्षा निदेशक एवं शिक्षा मंत्री से मांग की है कि सभी पदोन्नत शिक्षकों का वेतन तत्काल प्रवक्ता पद के अनुरूप निर्धारित कर लंबित वित्तीय लाभ दें और 749 टीजीटी को एक माह के भीतर प्रवक्ता प्रमोशन दें ताकि यह विधिक विवाद हल हो सके। संघ के प्रदेश महासचिव विजय हीर ने कहा कि अनेक शिक्षकों ने अक्तूबर 2025 तक वेतन निर्धारण के विकल्प एवं संबंधित प्रकरण विभाग को प्रॉपर चैनल से भेज दिए थे।

◆ प्रमोशन स्केल और वार्षिक इंक्रीमेंट को तरसे टीजीटी से प्रमोट प्रवक्ता

गत वर्ष अक्तूबर माह में डीम्ड रेगुलर और सामान्य रेगुलर कर्मचारियों के मध्य वरिष्ठता विवाद हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट पहुंचा था। इस मामले से जुड़ी एल पी ए अनिल कुमार बनाम हिमाचल सरकार में प्रदेश हाईकोर्ट स्टे लगा चुका है, जबकि सर्वोच्च न्यायालय ने हिमाचल प्रदेश बनाम सतीश कुमार एवं अन्य मामले में 7 अक्तूबर 2025 को सुनवाई करते हुए राज्य सरकार की अपील स्वीकार कर ली और उच्च न्यायालय द्वारा जारी अवमानना कार्यवाही को स्थगित कर दिया है, जब तक यह अपील लंबित है, तब तक उच्च न्यायालय के निर्णय तथा उस पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर रोक रहेगी। हिमाचल प्रदेश में 592 प्रवक्ताओं के डिमोशन का आधार बनी दो प्रमुख याचिकाओं सतीश कुमार बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश तथा पूर्णिमा कुमारी बनाम राज्य हिमाचल प्रदेश पर अब न्यायालयों द्वारा रोक लगा दी गई है। कोर्ट ने यह स्पष्ट किया कि जब तक यह अपील लंबित है, तब तक उच्च न्यायालय के निर्णय तथा उस पर की जाने वाली किसी भी कार्यवाही पर रोक रहेगी। 23 जुलाई को प्रदेश हाईकोर्ट ने पैरा टीचर्स को डीम्ड रेगुलर शिक्षकों की वरिष्ठता के मामले निर्मल सिंह बनाम हिमाचल सरकार में एक और स्टे लगा दिया है। इस तरह कानूनी लड़ाई में शिक्षकों को प्रमोशन के कोई भी आर्थिक लाभ आज तक नहीं मिले हैं। रिक्त पदों की पर्याप्त संख्या के बावजूद 749 टीजीटी को प्रवक्ता प्रमोट नहीं किया जा रहा है जिससे विधिक विवाद हल नहीं हो रहा है।

टिक्कर कलां पंचायत के विकास के लिए प्रधान सुरेश शर्मा ने जमा करवाए 10 लाख

◆ पांच साल में 20 लाख के योगदान का संकल्प

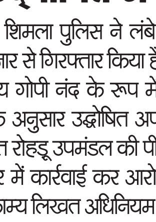

भगत सिंह गुलेरिया, भारतेन्दु संवाददाता, मंडी। बल्ह विकासखंड की नवगठित टिक्कर कलां पंचायत के नवनिर्वाचित प्रधान सुरेश शर्मा ने चुनाव के दौरान की गई अपनी घोषणा को पूरा करते हुए पंचायत के जनकल्याण एवं विकास कार्यों के लिए निजी योगदान की शुरुआत कर दी है।

उन्होंने हिमाचल प्रदेश ग्रामीण बैंक बेहना में एक संयुक्त खाता खुलवाकर उसमें प्रारंभिक राशि के रूप में 10 लाख रुपए जमा करवाए हैं। प्रधान सुरेश शर्मा ने बताया कि नई पंचायत होने के कारण अभी कई व्यवस्थाओं को स्थापित करने में समय लगेगा, लेकिन जनता से जुड़े कुछ कार्य ऐसे होते हैं जिन्हें तुरंत और समयबद्ध तरीके से पूरा करना जरूरी होता है। उन्होंने कहा कि इस राशि का उपयोग पंचायत के विकास और जनहित के कार्यों के लिए आवश्यकता अनुसार किया जाएगा। उन्होंने बताया कि प्रधान पद के लिए मिलने वाले 7500 रुपए मासिक वेतन को मिलाकर वह हर महीने 15 हजार रुपए इस खाते में जमा करवाते रहेंगे। इस प्रकार हर वर्ष करीब दो लाख रुपये और पांच वर्षों में लगभग 10 लाख रुपये अतिरिक्त जमा होंगे। उन्होंने कहा कि पांच साल की अवधि में पंचायत के लिए उनका निजी योगदान करीब 20 लाख रुपये तक पहुंच जाएगा। प्रधान ने स्पष्ट किया कि खाते में सभी लेनदेन का पूरा हिसाब रखा जाएगा। राशि केवल चेक के माध्यम से संबंधित लाभार्थियों के नाम जारी की जाएगी तथा कार्य समिति के ऑडिटर समय-समय पर खाते की जांच कर रिपोर्ट दर्ज करेंगे। उन्होंने बताया कि पंचायत के सभी वार्डों में मुख्य रास्तों से कांटेदार झाड़ियों और खरपतवार हटाने का कार्य शुरू कर दिया गया है, ताकि लोगों और स्कूली विद्यार्थियों को सुविधा मिल सके। इसके अलावा पंचायत घर के निर्माण के लिए जरूरत पड़ने पर पांच से सात बिस्वा निजी भूमि दान करने की घोषणा भी दोहराई है।

प्रदर्शन | भाजपा ने खोला जनविरोधी नीतियों के खिलाफ मोर्चा, सरकार के खिलाफ गरजे लखनपाल

बड़सर की अनदेखी पर कांग्रेस के खिलाफ उमड़ा जनसैलाब

अनिल कुमार, भारतेन्दु संवाददाता, हमीरपुर। बड़सर विधानसभा क्षेत्र के मैहरे में मंगलवार को भारतीय जनता पार्टी ने प्रदेश सरकार के खिलाफ अब तक का सबसे बड़ा जनआक्रोश प्रदर्शन करते हुए जोरदार शक्ति प्रदर्शन किया।

विधायक इंद्रदत्त लखनपाल के नेतृत्व में आयोजित विशाल धरना-प्रदर्शन और जनआक्रोश रैली में हजारों कार्यकर्ताओं और समर्थकों ने भाग लिया। प्रदर्शन के बाद भाजपा ने एसडीएम के माध्यम से राज्यपाल के नाम ज्ञापन भी सौंपा। रैली को संबोधित करते हुए विधायक इंद्रदत्त लखनपाल ने कांग्रेस सरकार पर तीखा हमला बोलते हुए आरोप लगाया कि सत्ता में आने के बाद सरकार ने विकास कार्यों पर पूरी तरह ब्रेक लगा दिया है। उन्होंने कहा कि प्रदेश में महंगाई, बेरोजगारी और अव्यवस्था चरम पर है। कर्मचारी अपने अधिकारों के लिए सड़कों पर उतरने को मजबूर हैं, किसान परेशान हैं और आम जनता मूलभूत सुविधाओं के लिए भटक रही है। लखनपाल ने आरोप लगाया कि मुख्यमंत्री लगातार बड़सर विधानसभा क्षेत्र की अनदेखी कर रहे हैं और चुनाव के दौरान किए गए वादों को पूरी तरह भूल चुके हैं।

उन्होंने कहा कि रोजगार देने का दावा करने वाली सरकार ने बड़सर के युवाओं के अधिकारों की अनदेखी कर उन्हें रोजगार से वंचित किया है, जबकि नौकरियों का लाभ अन्य क्षेत्रों, विशेषकर नादौन, तक सीमित कर दिया गया है। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार ने बड़सर के लिए करोड़ों रुपये का क्रिटिकल केयर सेंटर स्वीकृत किया, लेकिन प्रदेश सरकार आज तक उसका निर्माण कार्य शुरू नहीं करवा सकी। उन्होंने आरोप लगाया कि सरकारी विभागों की स्थिति बदहाल है। जल शक्ति विभाग में पाइप नहीं हैं, बिजली विभाग में तार और पोल की कमी है, शिक्षण संस्थानों में स्टाफ नहीं है, अस्पतालों में डॉक्टरों के पद खाली पड़े हैं और आपातकालीन स्वास्थ्य सेवाओं के लिए लोगों को दूसरे क्षेत्रों का रुख करना पड़ रहा है। लखनपाल ने कहा कि बिझड़ी में कम्युनिटी सेंटर के निर्माण के लिए डीपीआर तैयार होने के बावजूद आज तक धरातल पर कोई प्रगति दिखाई नहीं दे रही है। उन्होंने आरोप लगाया कि प्रदेश सरकार केवल घोषणाएं कर रही है, जबकि विकास कार्य पूरी तरह ठप पड़े हैं। भाजपा नेताओं ने अपने संबोधन में आरोप लगाया कि कांग्रेस सरकार चुनावी वादों को भूलकर केवल राजनीतिक प्रतिशोध और झूठे प्रचार की राजनीति कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रदेश की जनता कथित जनविरोधी नीतियों से त्रस्त हो चुकी है और हर वर्ग में सरकार के प्रति भारी नाराजगी है। प्रदर्शन के दौरान भाजपा कार्यकर्ताओं ने कांग्रेस सरकार के खिलाफ जोरदार नारेबाजी की और आरोप लगाया कि प्रदेश में विकास कार्य ठप पड़े हैं, नई योजनाएं केवल कागजों तक सीमित हैं तथा जनता की समस्याओं को सुनने वाला कोई नहीं है। नेताओं ने कहा कि सरकार की कथित विफलताओं के खिलाफ शुरू हुआ यह जनआक्रोश आने वाले समय में बड़े जन आंदोलन का रूप लेगा।

भव्य और गरिमापूर्ण होगा जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह: राहुल कुमार

अमर सिंह ठाकुर, भारतेन्दु संवाददाता, बिलासपुर। जिला मुख्यालय स्थित बचत भवन में मंगलवार को 80वें स्वतंत्रता दिवस के जिला स्तरीय समारोह की तैयारियों को लेकर उपायुक्त राहुल कुमार की अध्यक्षता में समीक्षा बैठक आयोजित की गई।

बैठक में समारोह के सफल, सुव्यवस्थित एवं गरिमापूर्ण आयोजन के लिए विभिन्न विभागों की तैयारियों की समीक्षा की गई तथा अधिकारियों को आवश्यक दिशा-निर्देश दिए गए। डीसी ने बताया कि जिला स्तरीय स्वतंत्रता दिवस समारोह 15 अगस्त को आदर्श राजकीय वरिष्ठ माध्यमिक पाठशाला (छात्र), बिलासपुर के प्रांगण में आयोजित होगा। उन्होंने कहा कि प्रदेश सरकार के निर्देशानुसार समारोह पूरे उत्साह, देशभक्ति व गरिमा के साथ मनाया जाएगा। सभी विभागों को आपसी समन्वय से समयबद्ध तरीके से अपनी जिम्मेदारियां पूरी करने के निर्देश दिए गए। बैठक में पुलिस विभाग को परेड में भाग लेने वाली टुकड़ियों का चयन, नियमित रिहर्सल तथा सुरक्षा, यातायात और पार्किंग व्यवस्था सुनिश्चित करने के निर्देश दिए गए। नगर परिषद को शहीद स्मारक की साफ-सफाई और सौंदर्यीकरण का कार्य समय पर पूरा करने को कहा गया। वहीं, संबंधित विभागों को समारोह स्थल पर पंडाल, मंच, बैठक व्यवस्था, पेयजल, बिजली और स्वच्छता सहित सभी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश दिए गए।

उपायुक्त ने शिक्षा विभाग और भाषा एवं संस्कृति विभाग को स्कूली विद्यार्थियों के सांस्कृतिक कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार कर नियमित अभ्यास करवाने को कहा। साथ ही सभी विभागों को सरकारी और गैर-सरकारी क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य करने वाले व्यक्तियों के नाम 10 अगस्त से पहले सम्मान के लिए उपायुक्त कार्यालय भेजने के निर्देश दिए। बैठक में अतिरिक्त उपायुक्त ओम कांत ठाकुर, एसडीएम सदर राजकुमार सहित सभी विभागाध्यक्ष एवं जिला स्तरीय अधिकारी उपस्थित रहे।

टिफनी स्ट्रैटन का खूबसूरत अंदाज

अमेरिका। टिफनी स्ट्रैटन एक अमेरिकी पेशेवर पहलवान हैं जो डब्लयूडब्लयूई में अपने शानदार प्रदर्शन के लिए जानी जाती हैं। उनका असली नाम जेसिका वॉड है। उन्होंने कम समय में अपनी ताकत, तकनीक और प्रभावशाली अंदाज से प्रशंसकों के बीच खास पहचान बनाई है।

स्पोर्ट्स विंडो

भारतीय महिला टीम विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में मलेशिया से हारी

एजेंसी, नई दिल्ली। हाल ही में विश्व जूनियर चैंपियन बनी अनाहत सिंह ने अपना मुकाबला तो जीत लिया, लेकिन भारत की अन्य खिलाड़ी अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाई जिससे महिला टीम को कनाडा के ओंटारियो में चल रही विश्व स्क्वाश जूनियर टीम चैंपियनशिप में मलेशिया से 1-2 से हार का सामना करना पड़ा। भारत के पहले दो मैच हारने के बाद अनाहत ने अंतिम मैच में व्हिटनी विल्सन को 11-2, 11-4, 11-5 से आसानी से हरा दिया। रुद्र सिंह पहले मैच में हरलीन टैन से 5-11, 4-11, 6-11 से हार गई जबकि अनिका दुबे को पांच गेम के रोमांचक मुकाबले में ये सान ली से 8-11, 11-8, 11-8, 10-12, 9-11 से हार का सामना करना पड़ा। इससे पहले भारतीय महिला टीम ने अपने पहले मैच में चीनी ताइपे को 3-0 से हराया था। अब टीम का अगला मुकाबला दक्षिण अफ्रीका से होगा, जबकि पुरुष टीम कुवैत के खिलाफ खेलेगी।

पोगैकर ने रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए पांचवीं बार टूर डी फ्रांस का खिताब जीता

एजेंसी, पेरिस। पेरिस में हुए 21वें और आखिरी चरण में सुरक्षित रूप से रेस पूरी करने के बाद तादेज पोगैकर ने रिकॉर्ड की बराबरी करते हुए पांचवीं बार टूर डी फ्रांस का खिताब जीता। साइक्लिंग की सबसे प्रतिष्ठित रोड रेस में पोगैकर की पिछली जीत 2020, 2021, 2024 और 2025 में हुई थी। 27 वर्षीय स्लोवेनियाई राइडर बेल्जियम के एडी मर्कक्स, स्पेन के मिगुएल इंदुरैन और फ्रांस के जैक्स एंक्वेटिल और बर्नार्ड हिनॉल्ट की उस खास सूची में शामिल हो गए हैं, जिन्होंने पांच बार यह टूर जीता है।

जस्टिन ग्रीव्स की घातक गेंदबाजी वेस्टइंडीज को 155 रन की बढ़त

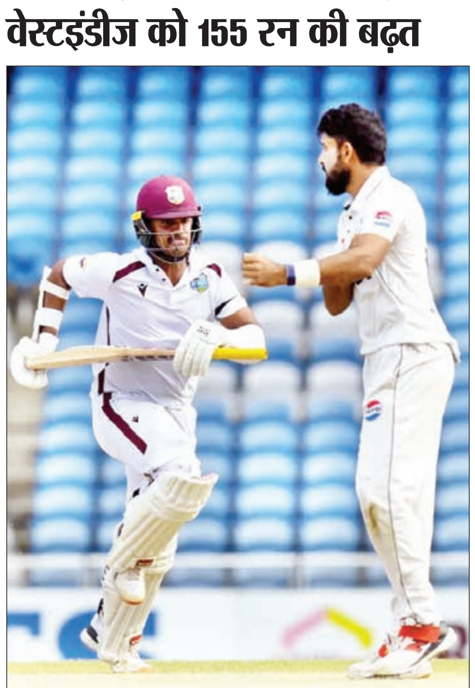

एजेंसी, तारौबा (त्रिनिदाद)। वेस्टइंडीज ने पहले टेस्ट क्रिकेट मैच के तीसरे दिन गेंदबाजों के दबदबे के बीच अपनी दूसरी पारी में सात विकेट पर 126 रन बनाकर पाकिस्तान के खिलाफ 155 रन की बढ़त हासिल कर ली है। सबसे पहले जस्टिन ग्रीव्स ने लगातार पांच विकेट मेडन ओवर फेंकते हुए 27 रन देकर पांच विकेट लिए, जिससे पाकिस्तान ने अपने छह विकेट 38 रन पर गंवा दिए। इस तरह से शान मसूद (109) के सातवें टेस्ट शतक के बावजूद पाकिस्तान की टीम अपनी पहली पारी में 282 रन पर आउट हो गई। इसके बाद पाकिस्तान के गेंदबाजों ने भी कहर बरपाया और पहली पारी में 311 रन बनाने वाले वेस्टइंडीज के बल्लेबाजों को नहीं चलने दिया। पाकिस्तान की तरफ से मोहम्मद अब्बास ने अभी तक 14 रन देकर तीन विकेट लिए हैं, जबकि खुर्रम शहजाद ने दो विकेट हासिल किए हैं। वेस्टइंडीज की तरफ से तेगनारायण चंद्रपाल ही कुछ संघर्ष कर पाए। उन्होंने 35 रन बनाए।

दिल्ली प्रीमियर लीग: 'पुरानी दिल्ली 6' ने अनुज रावत को कप्तान बनाया

एजेंसी, नई दिल्ली। 'पुरानी दिल्ली 6' ने 31 जुलाई से शुरू होने वाले दिल्ली प्रीमियर लीग (डीपीएल) सीजन 3 के लिए विकेटकीपर-बल्लेबाज़ अनुज रावत को अपनी टीम का कप्तान घोषित किया है। यह नियुक्ति ऐसे समय में हुई है जब टीम इस साल के टूर्नामेंट में शानदार प्रदर्शन करने के मकसद से अपनी तैयारियों के आखिरी चरण में है।टी 20 क्रिकेट में कप्तानी का अनुभव रखने वाले और घरेलू क्रिकेट के मंझे हुए खिलाड़ी, रावत एक ऐसी संतुलित टीम की अगुवाई करेंगे जिसमें अनुभवी खिलाड़ी और होनहार युवा प्रतिभाएं शामिल हैं।

रवींद्र जडेजा की वापसी, सारांश जैन को पहली बार मौका

श्रीलंका के खिलाफ दो टेस्ट मैचों की भारतीय टीम घोषित

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड (बीसीसीआई) ने मंगलवार को अगस्त में श्रीलंका के खिलाफ होने वाली दो मैचों की टेस्ट सीरीज के लिए 15 सदस्यीय भारतीय टीम का ऐलान कर दिया है। टीम की कमान एक बार फिर शुभमन गिल के हाथों में होगी, जबकि केएल राहुल को उपकप्तान बनाया गया है।

इस टीम में सबसे बड़ा आकर्षण मध्य प्रदेश के अनुभवी ऑफ स्पिन ऑलराउंडर सारांश जैन का पहली बार टेस्ट टीम में चयन है। 33 वर्षीय सारांश को वॉशिंगटन सुंदर के हैमस्ट्रिंग चोटिल होने के बाद मौका मिला है। घरेलू क्रिकेट और इंडिया ए के लिए लगातार शानदार प्रदर्शन के दम पर उन्होंने राष्ट्रीय टीम में जगह बनाई है।

वहीं, अनुभवी ऑलराउंडर रवींद्र जडेजा की भी टीम में वापसी हुई है। उन्हें जून में अफगानिस्तान के खिलाफ खेले गए एकमात्र टेस्ट मैच के लिए आराम दिया गया था।

तेज गेंदबाज जसप्रीत बुमराह और बल्लेबाज साई सुदर्शन को भी टीम में शामिल किया गया है, लेकिन दोनों का चयन बीसीसीआई के सेंटर ऑफ एक्सीलेंस (सीओई) से फिटनेस

◆ **राहुल को मिली उपकप्तानी की बड़ी जिम्मेदारी**

मंजूरी मिलने पर ही प्रभावी होगा। दूसरी ओर, चोट के कारण पुनर्वास कर रहे नितीश कुमार रेड्डी को टीम में जगह नहीं मिली है।

भारत और श्रीलंका के बीच पहला टेस्ट 15 अगस्त से गॉल में खेला जाएगा, जबकि दूसरा और अंतिम टेस्ट 23 अगस्त से एसएससी, कोलंबो में होगा। भारत ने पिछली बार 2017 में श्रीलंका का दौरा किया था, जहां उसने मेजबान टीम का 3-0 से सफाया किया था।

श्रीलंका दौरे के लिए भारतीय टेस्ट टीम

शुभमन गिल (कप्तान), केएल राहुल (उपकप्तान), यशस्वी जायसवाल, ऋषभ पंत (विकेटकीपर), साई सुदर्शन, ध्रुव जुरेल (विकेटकीपर), रवींद्र जडेजा, कुलदीप यादव, मानव सुथार, जसप्रीत बुमराह, मोहम्मद सिराज, प्रसिद्ध कृष्णा, गुरनूर बरार, देवदत्त पडिक्कल और सारांश जैन।

* जसप्रीत बुमराह और साई सुदर्शन का चयन फिटनेस मंजूरी के अधीन है।

कॉमनवेल्थ गेम्स-2026

शर्मिला ने शॉट पुट में भारत को दिलाया पहला स्वर्ण पदक

एजेंसी, ग्लास्गो

राष्ट्रमंडल खेल-2026 में भारत की पैरा एथलेटिक्स टीम ने ऐतिहासिक उपलब्धि हासिल की। भारतीय पैरा एथलीट शर्मिला धनखड़ ने स्थानीय समयानुसार सोमवार को महिलाओं की शॉटपुट एफ57 स्पर्धा में स्वर्ण पदक जीतकर राष्ट्रमंडल खेलों के इतिहास में पैरा एथलेटिक्स में भारत को पहला स्वर्ण पदक दिलाया। इसके साथ ही वह राष्ट्रमंडल खेलों में पैरा एथलेटिक्स में पदक जीतने वाली पहली भारतीय महिला भी बन गईं।

शर्मिला ने फाइनल में 9.81 मीटर का सर्वश्रेष्ठ थ्रो कर शीर्ष स्थान हासिल किया और इतिहास रच दिया। एफ57 वर्ग उन खिलाड़ियों के लिए होता है, जिनके निचले अंगों में दिव्यांगता, अंगों की कमी या मांसपेशियों की शक्ति कम होती है।

जस्टिन ग्रीव्स ने टेस्ट क्रिकेट में रचा नया इतिहास

एजेंसी, त्रिनिदाद। वेस्टइंडीज के तेज गेंदबाज जस्टिन ग्रीव्स ने पाकिस्तान के खिलाफ टेस्ट मैच में असाधारण गेंदबाजी करते हुए क्रिकेट इतिहास में अपना नाम दर्ज करा लिया। ग्रीव्स ने लगातार पांच विकेट मेडन ओवर फेंके और इस दौरान 30 गेंदों पर कोई रन नहीं दिया। उन्होंने पांचों ओवर में एक-एक बल्लेबाज को आउट किया। यह उपलब्धि टेस्ट क्रिकेट के रिकॉर्डेड इतिहास में पहली बार देखने को मिली है। ग्रीव्स की सटीक लाइन-लेंथ और अनुशासित गेंदबाजी के सामने पाकिस्तान के बल्लेबाज रन बनाने के लिए संघर्ष करते नजर आए।

राष्ट्रमंडल खेल: अजय बाबू ने भारोत्तोलन में जीता रजत पदक

एजेंसी, ग्लासगो

राष्ट्रमंडल खेल-2026 में भारत के भारोत्तोलक वल्लुरी अजय बाबू ने भारतीय समयानुसार मंगलवार तड़के पुरुषों के 79 किलोग्राम भारवर्ग में शानदार प्रदर्शन करते हुए रजत पदक अपने नाम किया। बेहद रोमांचक मुकाबले में अजय बाबू लंबे समय तक स्वर्ण पदक की दौड़ में आगे रहे, लेकिन मलेशिया के मुहम्मद एरी हिदायत ने अंतिम प्रयास में खेलों का नया रिकॉर्ड बनाते हुए स्वर्ण पदक जीत लिया।

अजय बाबू ने स्नैच स्पर्धा में 149 किलोग्राम वजन सफलतापूर्वक उठाकर राष्ट्रमंडल खेलों का नया रिकॉर्ड बनाया। दूसरे प्रयास में वह असफल रहे थे, लेकिन तीसरे प्रयास में उसी वजन को उठाकर उन्होंने शानदार वापसी की और स्नैच के बाद शीर्ष स्थान हासिल किया। क्लीन एंड जर्क में भी भारतीय खिलाड़ी ने लगातार तीनों प्रयास सफल किए। उन्होंने क्रमशः 174 किलोग्राम, 178 किलोग्राम और 181 किलोग्राम वजन उठाया। इस तरह उनका कुल वजन 330 किलोग्राम रहा और वह स्वर्ण पदक के बेहद करीब पहुंच गए। हालांकि मुकाबले के अंतिम क्षणों में मलेशिया के मुहम्मद एरी हिदायत ने 184 किलोग्राम वजन उठाकर नया खेल रिकॉर्ड बनाया। इसके साथ ही उनका कुल वजन 331 किलोग्राम हो गया और उन्होंने मात्र एक किलोग्राम के अंतर से स्वर्ण पदक अपने नाम कर लिया।

अजय बाबू ने छह में से पांच प्रयास सफलतापूर्वक पूरे किए और स्नैच में नया खेल रिकॉर्ड भी बनाया, लेकिन उन्हें रजत पदक से संतोष करना पड़ा। इंग्लैंड के क्रिस मरे ने कुल 325 किलोग्राम वजन उठाकर कांस्य पदक जीता।

हार्दिक को लेने की रेस में सीएसके और केकेआर, ट्रेड पर होंगी नजरें

एजेंसी, नई दिल्ली। आईपीएल के अगले सत्र से पहले हार्दिक पांड्या को लेकर ट्रेड की चर्चाएं तेज हो गई हैं। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार चेन्नई सुपर किंग्स उन्हें अपनी टीम में शामिल करने की कोशिश कर रही है और इसके लिए दो खिलाड़ियों सहित 10 करोड़ रुपये के प्रस्ताव की बात सामने आई है।

वहीं कोलकाता नाइट राइडर्स भी हार्दिक को लेने की दौड़ में शामिल बताई जा रही है।

दो खिलाड़ी और 10 करोड़ रुपए का ऑफर!

रिपोर्ट्स के अनुसार, चेन्नई सुपर किंग्स ने हार्दिक पांड्या के बदले डेवाल्ड ब्रेविस, शिवम दुबे और 10 करोड़ देने का प्रस्ताव रखा है। दूसरी ओर, रिपोर्ट्स का दावा है कि मुंबई इंडियंस हार्दिक के बदले आयुष म्हात्रे और शिवम दुबे को अपनी टीम में शामिल करना चाहती है। लेकिन चेन्नई युवा बल्लेबाज आयुष म्हात्रे को छोड़ने के पक्ष में नहीं दिख रही है, जिससे बातचीत फिलहाल अटकी हुई बताई जा रही है।

राज्य लीगों ने बदली युवा क्रिकेटरों की तस्वीर : भुवनेश्वर कुमार

एजेंसी, लखनऊ

भारतीय तेज गेंदबाज भुवनेश्वर कुमार ने उत्तर प्रदेश क्रिकेट एसोसिएशन की यूपीसीए स्पीड हंट पहल की जमकर सराहना की है। उन्होंने कहा कि यह अभियान पूरे उत्तर प्रदेश से तेज गेंदबाजी की नई प्रतिभाओं को खोजने का महत्वपूर्ण माध्यम बन गया है। भुवनेश्वर ने बताया कि यूपीटी20 लीग ने पिछले तीन सत्रों में शानदार सफलता हासिल की है और आने वाले समय में यह और बेहतर होगी।

उन्होंने कहा कि स्पीड हंट के जरिए कई युवा खिलाड़ियों को अपनी प्रतिभा दिखाने का अवसर मिला है। शुभम गौतम जैसे खिलाड़ियों को बड़े अनुबंध मिलना इस बात का प्रमाण है कि अच्छा प्रदर्शन करने वाले खिलाड़ियों के लिए आगे बढ़ने के रास्ते खुल रहे हैं।

भुवनेश्वर ने युवा क्रिकेटरों को सलाह दी कि वे मिले हुए हर अवसर का पूरा फायदा उठाएं और मैदान पर अपना सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करें। उन्होंने कहा कि यूपीसीए खिलाड़ियों को सही मंच उपलब्ध करा रहा है, लेकिन सफलता के लिए मेहनत और प्रदर्शन खिलाड़ियों पर निर्भर करता है।

उन्होंने राज्य स्तरीय लीगों को युवाओं के लिए प्रेरणादायक बताते हुए कहा कि अब खिलाड़ियों को अपनी क्षमता दिखाने के अधिक अवसर मिल रहे हैं। यूपीटी20 जैसी प्रतियोगिताएं आईपीएल तक पहुंचने का रास्ता भी तैयार कर रही हैं। वहीं, लीग के चौथे संस्करण का आयोजन लखनऊ और कानपुर में किया जाएगा, जिससे प्रशंसकों को भी अपनी टीमों से जुड़ने का बेहतर अवसर मिलेगा।

भारतीय रेलवे ने 163 करोड़ की परियोजना को दी मंजूरी

एजेंसी, नई दिल्ली

भारतीय रेलवे ने नेटवर्क क्षमता बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार के लिए दक्षिण मध्य रेलवे के नांदेड़ मंडल के परभणी-मुदखेड़ रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली के उन्नयन को मंजूरी दी है। इस परियोजना पर 163 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे। रेल मंत्रालय के अनुसार, 164 ट्रैक किलोमीटर लंबे इस रेलखंड पर मौजूदा 1×25 केवी इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन प्रणाली को आधुनिक 2×25 केवी प्रणाली में बदला जाएगा। इसके साथ ही बढ़े हुए विद्युत भार को संभालने के लिए बिजली आपूर्ति ढांचे को भी मजबूत किया जाएगा।

परभणी-मुदखेड़ रेलखंड रणनीतिक रूप से महत्वपूर्ण हाईली यूटिलाइज्ड नेटवर्क (एचयूएन) रूट-9 का हिस्सा है। यह मार्ग अजमेर, इंदौर, खंडवा, अकोला, पूर्णा, मुदखेड़, सिकंदराबाद, महबूबनगर और धोने जैसे प्रमुख क्षेत्रों को जोड़ता है। रेलवे ने बताया कि ट्रैक्शन प्रणाली के उन्नयन से

◆ **परभणी-मुदखेड़ रेलखंड पर इलेक्ट्रिक ट्रैक्शन सिस्टम होगा अपग्रेड, वंदे भारत संचालन को मिलेगा बल**

ट्रेनों के संचालन के लिए अधिक मजबूत और भरोसेमंद विद्युत आपूर्ति उपलब्ध होगी। इससे माल ढुलाई क्षमता बढ़ेगी और वंदे भारत एक्सप्रेस जैसी आधुनिक ट्रेनों के संचालन में भी सहायता मिलेगी। यह परियोजना वर्ष 2029-30 तक 3,000 मिलियन टन माल ढुलाई के लक्ष्य को हासिल करने की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है।

आईसीजी ने महिलाओं को बराबर मौके देने के लिए शुरू किया 'जेंडर न्यूट्रल फ्रेमवर्क'

एजेंसी, नई दिल्ली। भारतीय तटरक्षक बल (आईसीजी) के लिए दो महत्वपूर्ण नीतिगत सुधारों का मंगलवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने अनावरण किया। इनका उद्देश्य महिला अधिकारियों को समान अवसर देना और ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता कर्मियों के परिवारों को राहत प्रक्रिया आसान बनाना है। रक्षा मंत्री ने कहा कि आईसीजी में महिला अधिकारियों के इंडक्शन, प्रशिक्षण और स्थायी नियुक्ति के लिए जेंडर न्यूट्रल फ्रेमवर्क लागू किया गया है। इसके तहत महिला उम्मीदवारों को पुरुषों के समान शॉर्ट सर्विस अपॉइंटमेंट (एसएसए) और स्थायी नियुक्ति (पीए) के अवसर मिलेंगे। पुरुष उम्मीदवारों के लिए भी एसएसए का विकल्प उपलब्ध होगा। नीति के तहत पात्रता शर्तें पूरी करने वाली महिला अधिकारियों को उच्च पदों पर पदोन्नति के लिए भी विचार किया जाएगा। वहीं, वर्तमान महिला एसएसए अधिकारियों को भी सेवा को स्थायी नियुक्ति में बदलने का अवसर मिलेगा। दूसरे सुधार के तहत ड्यूटी के दौरान समुद्र में लापता होने वाले आईसीजी कर्मियों के परिजनों को अनुग्रह राशि और अन्य लाभ जल्द उपलब्ध कराने की प्रक्रिया सरल की गई है। इसके तहत ऐसे कर्मियों को भुगतान के लिए मृत माना जाएगा। राजनाथ सिंह ने कहा कि ये सुधार तटरक्षक बल के मनोबल और कार्यक्षमता को मजबूत करेंगे।

◆ **रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने दो नीतिगत सुधारों का किया अनावरण**

असम में बाढ़ की भयावह स्थिति पर प्रधानमंत्री मोदी ने सांसदों से की चर्चा, केंद्र ने मदद का दिया भरोसा

एजेंसी, नई दिल्ली

असम में लगातार जारी बाढ़ की स्थिति को लेकर प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने मंगलवार को राज्य के सांसदों से मुलाकात कर हालात की जानकारी ली। बैठक के दौरान राज्य के विभिन्न हिस्सों में बाढ़ से हुए नुकसान और प्रभावित लोगों की स्थिति पर विस्तार से चर्चा की गई। प्रधानमंत्री ने कहा कि केंद्र सरकार असम सरकार के साथ मिलकर बाढ़ प्रभावित लोगों तक हरसंभव सहायता पहुंचाने के लिए काम कर रही है। उन्होंने राज्य के लोगों की सुरक्षा और कुशलता के लिए प्रार्थना भी की। प्रधानमंत्री मोदी ने सोशल मीडिया के माध्यम से जानकारी साझा करते हुए कहा कि असम के सांसदों से मुलाकात कर वर्तमान बाढ़ की स्थिति पर चर्चा की गई है। उन्होंने भरोसा दिलाया कि संकट की इस घड़ी में केंद्र सरकार राज्य सरकार के साथ खड़ी है।

असम के कई जिलों में बाढ़ ने जनजीवन को प्रभावित किया है। शिवसागर, गोलाघाट, चराईदेव, जोरहाट, नगांव और कामरूप सहित कई क्षेत्रों में बड़ी संख्या में लोग प्रभावित हुए हैं। प्रभावित परिवारों के लिए 90 से अधिक राहत शिविर और 94 राहत वितरण केंद्र बनाए गए हैं, जहां लोगों को आवश्यक सहायता उपलब्ध कराई जा रही है। बाढ़ के कारण राज्य में 37 हजार हेक्टेयर से अधिक कृषि भूमि जलमग्न हो गई है।

सेंसेक्स 69 अंक टूटा, निफ्टी में 10 अंक की गिरावट

एजेंसी, मुंबई। भारतीय शेयर बाजार में मंगलवार को गिरावट दर्ज की गई। सेंसेक्स 69 अंक टूटकर 76,765 के स्तर पर बंद हुआ, जबकि निफ्टी 10 अंक की गिरावट के साथ 23,985 पर पहुंच गया। बाजार में सबसे ज्यादा दबाव आईटी और बैंकिंग शेयरों में देखने को मिला। वहीं, अंतरराष्ट्रीय बाजार में ब्रेंट क्रूड के दामों में करीब 2.5 प्रतिशत की गिरावट दर्ज की गई और कीमतें 85 डॉलर प्रति बैरल के आसपास पहुंच गईं। विशेषज्ञों के अनुसार, अमेरिका-इजराइल और ईरान के बीच तनाव कम होने की उम्मीद से कच्चे तेल की कीमतों में गिरावट आई है।

चांदी 6,543 रुपए सस्ती, सोना 1,907 रुपए गिरकर 1.43 लाख पहुंचा

एजेंसी, नई दिल्ली। सोने-चांदी की कीमतों में 28 जुलाई को गिरावट है। इंडिया बुलियन एंड ज्वेलर्स एसोसिएशन के मुताबिक, एक किलो चांदी 6,543 रुपए सस्ती होकर 2.18 लाख रुपए पर आ गई है। वहीं, 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का दाम 1,907 रुपए गिरकर 1.43 लाख रुपए पर आ गया है। इस साल सोने-चांदी की कीमत में लगातार उतार-चढ़ाव देखने को मिल रहा है। सोना 2026 में अब तक 10 हजार रुपए महंगा हुआ है।

सीडब्ल्यूआरसी की पानी छोड़ने की सिफारिश पर कर्नाटक ने जताई आपत्ति

कावेरी जल बंटवारे पर कर्नाटक-तमिलनाडु आमने-सामने

एजेंसी, बेंगलुरु/नई दिल्ली

कावेरी जल बंटवारे को लेकर कर्नाटक और तमिलनाडु के बीच विवाद फिर गहराता नजर आ रहा है। कावेरी जल विनियमन समिति (सीडब्ल्यूआरसी) ने तमिलनाडु के लिए 15 दिनों तक प्रतिदिन 3,500 क्यूसेक पानी छोड़े जाने की सिफारिश की है। इसके तहत करीब चार टीएमसी पानी छोड़े जाने का सुझाव दिया गया है।

नई दिल्ली में आयोजित वर्चुअल बैठक में कर्नाटक, तमिलनाडु, केरल और पुडुचेरी के प्रतिनिधियों ने जल उपलब्धता और मौजूदा हालात पर चर्चा की। इसके बाद समिति ने अपनी सिफारिश जारी की। कर्नाटक सरकार ने इस फैसले पर आपत्ति जताई है। जल संसाधन मंत्री रामलिंगा रेड्डी ने कहा कि राज्य खुद जल संकट का सामना कर रहा है और कम बारिश के कारण जलाशयों में पर्याप्त पानी उपलब्ध नहीं है। उन्होंने कहा कि पेयजल जरूरतें राज्य की पहली प्राथमिकता हैं।

वहीं, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष आर अशोक ने सरकार पर कर्नाटक के हितों की अनदेखी का आरोप लगाया। उन्होंने मुख्यमंत्री और जल संसाधन मंत्री से अधिकारियों व कानूनी विशेषज्ञों की बैठक बुलाकर कावेरी जल प्रबंधन प्राधिकरण के समक्ष राज्य का पक्ष मजबूती से रखने की मांग की। उन्होंने कहा कि जलाशयों की वास्तविक स्थिति और उपलब्ध आंकड़ों के आधार पर राज्य के हितों की रक्षा की जानी चाहिए।

सीजेपी प्रवक्ता आशुतोष और दीपक बालियान लौटे घर

एजेंसी, नई दिल्ली। सोशल मीडिया अभियान कॉकरोच जनता पार्टी (सीजेपी) के प्रवक्ता आशुतोष रांका और दीपक बालियान मंगलवार को जयपुर स्थित अपने घर लौट गए।

यह जानकारी खुद रांका ने एक्स पर साझा की। उन्होंने कहा, 'पिछले दो महीनों से दिल्ली में विरोध-प्रदर्शन करने के बाद आज मेरे साथी दीपक बालियान और मैं जयपुर स्थित अपने घर लौट रहे हैं। हम आज शाम 5 बजे राजस्थान यूनिवर्सिटी में छात्रों से मिलेंगे।' रांका ने कहा कि जब तक हम देश की शिक्षा व्यवस्था को ठीक नहीं कर लेते, तब तक सीजेपी चुप नहीं बैठेगी। उल्लेखनीय है कि दिल्ली के जंतर-मंतर पर करीब 37 दिनों तक सीजेपी ने छात्र आंदोलन चलाया। इस दौरान केंद्र सरकार से बातचीत करने वाले सीजेपी के प्रतिनिधियों में प्रवक्ता सौरव दास के साथ आशुतोष रांका भी थे।